राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 3 अंक 260

# दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 26 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

इवांका ने सिल्क शेरवानी में लिया देसी अवतार

>>6

# सीएए भारत का आंतरिक मामला : ट्रंप

## धार्मिक आजादी की दिशा में भारत के कदमों को सराहा

जयप्रकाश रंजन ● नई दिल्ली

ऐतिहासिक भारत यात्रा पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट तौर कहा कि नागरिक संशोधन कानून (सीएए) भारत का आंतरिक मामला है। इसे किस तरह से डील करना है यह भारत पर निर्भर करता है। धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि यहां की सरकार हर हालत में इसकी हिफाजत को तैयार है। ट्रंप ने कश्मीर को बड़ी समस्या मानते हुए उम्मीद जताई कि भारत-पाक इसका मिल-जुल कर समाधान निकालेंगे। अमेरिका जो भी कर सकता है, वह करेगा। भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हुए स्वागत से ट्रंप गदगद दिखे। मंगलवार रात अमेरिका रवाना होते समय उन्होंने सभी का धन्यवाद किया।

मंगलवार को हैदराबाद हाउस में ट्रंप और मोदी के बीच दो चरणों में बात हुई। पहले दोनों नेताओं ने तकरीबन 45 मिनट व्यक्तिगत तौर पर बात की और इसके बाद दोनों की अगुआई में अधिकारी स्तर की बातचीत एक घंटे चली। बातचीत वैसे तो रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, कारोबार, तकनीकी हस्तांतरण से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों पर ही केंद्रित रही लेकिन स्थानीय व वैश्विक मुद्दों को भी समय दिया गया। इसमें कश्मीर, पाक समर्थित आतंकवाद और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ संयुक्त रणनीति का मुद्दा भी उठा। बातचीत में ट्रंप ने सीएए का मुद्दा नहीं उठाया। हालांकि प्रेस कांफ्रेंस में एक सवाल पर ट्रंप ने दो टूक कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। कश्मीर में स्थिति सामान्य करने की दिशा में भारत के प्रयासों की भी उन्होंने सराहना की। भारत के भविष्य के प्रति आश्वस्त ट्रंप ने कहा कि भारत एक बहुत ही बड़ी शक्ति के तौर पर स्थापित होगा।

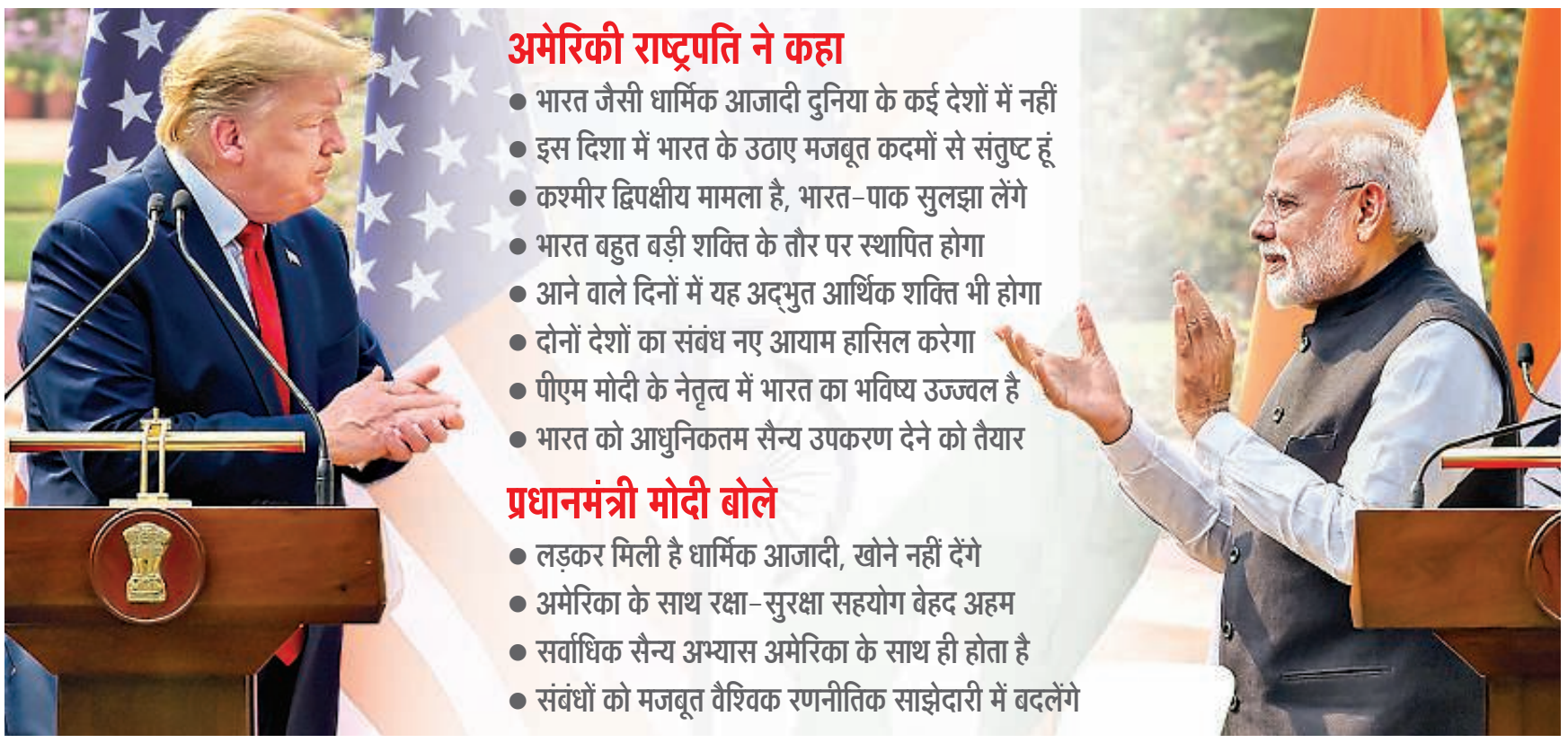

### अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा

- भारत जैसी धार्मिक आजादी दुनिया के कई देशों में नहीं
- इस दिशा में भारत के उठाए मजबूत कदमों से संतुष्ट हूं
- कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, भारत-पाक सुलझा लेंगे
- भारत बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर स्थापित होगा
- आने वाले दिनों में यह अद्भुत आर्थिक शक्ति भी होगा
- दोनों देशों का संबंध नए आयाम हासिल करेगा
- पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्ज्वल है
- भारत को आधुनिकतम सैन्य उपकरण देने को तैयार

### प्रधानमंत्री मोदी बोले

- लड़कर मिली है धार्मिक आजादी, खोने नहीं देंगे
- अमेरिका के साथ रक्षा-सुरक्षा सहयोग बेहद अहम
- सर्वाधिक सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ ही होता है
- संबंधों को मजबूत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बदलेंगे

नई दिल्ली में मंगलवार को हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेसवार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप ने देश-विदेश के पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब दिया ● पीटी

### 50 मिनट हुई प्रेस कांफ्रेंस

मोदी के साथ लंच के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय व अमेरिकी उद्योगपतियों के समूह के साथ अलग से बैठक की और इसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। पिछले दो दशकों में पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत में 50 मिनट लंबी प्रेस कांफ्रेंस की और देश-विदेश के पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान ट्रंप ने हर सवाल पर खुलकर अपने विचार बताए और अमेरिका का पक्ष रखा।

### प्रधानमंत्री की सोच मजबूत

धार्मिक आजादी के मुद्दे पर मोदी के जवाब से ट्रंप संतुष्ट नजर आए। ट्रंप ने कहा, 'इस पर हमारी काफी बात हुई। मैंने मुस्लिमों के साथ ईसाइयों की धार्मिक आजादी का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी इस बारे में सशक्त तरीके से सोचते हैं। भारत ने धार्मिक आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है और वह उसे बचाकर रखेगा। भारत में 20 करोड़ मुस्लिम हैं, कुछ साल पहले वे 14 करोड़ थे। मोदी मुस्लिमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।'

### सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन का वादा

साझा बयान में अमेरिका की ओर से यह वादा दोहराया गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) में भी भारत के बिना देरी प्रवेश के लिए अमेरिका सहयोग करेगा। आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग समेत सभी क्षेत्रों में आपसी समझ और भरोसे के साथ संबंध मजबूत बनाने की बात दोनों नेताओं ने दोहराई।

### ट्रंप बोले, आतंकवाद से निपट लेंगे मोदी

ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि वे आतंकवाद से निपट लेंगे। ट्रंप ने कहा, 'मोदी बहुत धार्मिक और शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं। लेकिन, असल में वे बहुत सख्त हैं। मैंने उनको कार्रवाई करते देखा है। उनके जेहन में आतंकवाद सबसे ऊपर है और वे इस समस्या का समाधान कर लेंगे।' आतंक के खिलाफ अपने रिकॉर्ड पर चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा, 'मैंने किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा आतंकियों को खत्म किया है।'

### यह अहम साझेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त बयान में कहा, 'भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी 21 वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी होगी। इसलिए मैंने और राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप ने यह फैसला किया है कि इस साझेदारी को समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील किया जाएगा। अमेरिका के साथ हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका के बेहद आधुनिक रक्षा उपकरण हमारी क्षमता को और बढ़ाएंगे।'

### आतंक के खिलाफ एक साथ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वह पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहे हैं। सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि आतंकवाद का साथ देने वाले देशों पर दबाव बनाने का काम और तेज होगा। इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका का सहयोग और मजबूत होगा। दोनों देश इस्लामी आतंकवाद के इस खतरे से मिलकर लड़ेंगे।

## भारत-अमेरिका में तीन अरब डॉलर का रक्षा करार

संजय मिश्र ● नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक में भारत और अमेरिका ने रक्षा-सुरक्षा संबंधों को नए आयाम पर ले जाने का फैसला करते हुए तीन अरब डॉलर के बड़े रक्षा सौदे का एलान किया। सौदे के तहत भारत एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट सिस्टम के साथ अपाचे और एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदेगा। ट्रंप ने दुनिया के सबसे आधुनिक और उच्च कोटि के अमेरिकी हथियारों जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रॉकेट से लेकर नौसैनिक जहाज आदि को भारत को देने का भी एलान किया।

भारत-अमेरिका के बीच सुरक्षा-रक्षा रणनीतिक रिश्तों के दायरे को वैश्विक कूटनीति का पंख लगाने का भी डोनाल्ड ट्रंप ने एलान किया। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप ने तीन अरब डॉलर से अधिक के रक्षा सौदों पर करार की घोषणा की। ट्रंप ने भारत से बड़े और ऐतिहासिक ट्रेड डील पर चर्चा की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बात सही दिशा में बढ़ रही है। हालांकि, अभी दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई एलान नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में इस संबंध में भी दोनों देशों के बीच बड़ा एलान सुनने को मिल सकता है। अमेरिका कुछ ऐसे देशों में शामिल है, जिससे साथ भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। यानी भारत यहां से आयात के मुकाबले निर्यात ज्यादा करता है।

नमस्ते ट्रंप पेज>>6,7

### सरोकार

**रंग बन परिधानों पर शोभित हो रहे बुद्ध को अर्पित फूल**

**गया :** महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के श्रीचरणों में अर्पित श्रद्धा के फूल रंग बन और परिधानों में समा जहां बौद्ध श्रद्धालुओं को लुभा रहे हैं, वहीं इससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी मुहैया हो गया है। (पेज-11)

### जागरण विशेष

**जम्मू-कश्मीर में अब जमीन पर दिख रहीं योजनाएं**

**जम्मू :** जम्मू-कश्मीर में पहली बार बिजली, शौचालय व स्वास्थ्य सुविधाएं फाइलों से निकल लोगों के घरों तक पहुंचीं हैं। तेजी से विकास की गति से आमजन खुश हैं। परिवर्तन को मान रहे मुख्य वजह। (पेज-11)

# दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश

## स्थिति गंभीर ▶ हिंसा में मंगलवार को आठ की गई जान, अब तक 13 की मौत और 186 घायल

### तीन दिन की हिंसा में 56 पुलिसकर्मी भी घायल, 11 मुकदमे दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में तीसरे दिन हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने दंगाइयों को गोली मारने का आदेश दिया है। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक के इस आदेश के बाद दंगा प्रभावित सभी इलाकों में लाउडस्पीकर से घोषणा की कि दंगा करने वालों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। धारा-144 का कोई असर न देखते हुए पुलिस ने मंगलवार देर शाम चार इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। इसमें सबसे संवेदनशील मौजपुर, जाफराबाद, करावल नगर और बाबरपुर शामिल हैं। दंगाइयों ने मंगलवार को भी जमकर उत्पात मचाया। इस उपद्रव में आठ और लोगों की मौत हो गई। सोमवार को भी पांच की जान गई थी। कुल मिलाकर अब तक 13 लोग मारे गए हैं। घायलों की संख्या 186 पहुंच गई है। इसमें दो आइपीएस अधिकारी सहित 56 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मंगलवार को सीआरपीएफ जवानों पर दंगाइयों ने एसिड से हमला किया, इसमें दो जवान झुलस गए।

नई दिल्ली के भजनपुरा में मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून विरोधियों और समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के दौरान लगाई गई आग। ध्रुव कुमार

हिंसा फैलाने वालों की पहचान के लिए ड्रोन के साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। पुलिस की टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही है। स्थिति काबू में है। हिंसा की शुरुआत में पुलिस की निष्क्रियता की बात गलत है। पुलिस पहले दिन से ही सक्रिय है। चार जिलों में कर्फ्यू हैं, यहां दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं।

**-एमएस रंधावा, प्रवक्ता, दिल्ली पुलिस**

**दंगाइयों ने दागीं एक हजार गोलियां :** दंगाइयों ने मंगलवार को न सिर्फ दुकानों, वाहनों व घरों में आग लगाई, बल्कि पांच धार्मिक स्थलों को भी फूंक दिया। उपद्रवी हथियार लहराते हुए फायरिंग कर दहशत फैला रहे थे। हालात काबू करने को दोपहर बाद आरएएफ और सीआरपीएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। प्रभावित क्षेत्र यमुनापार के कई इलाके भीषण हिंसा की चपेट में रहे। दो दिनों में दंगाइयों की तरफ से एक हजार से ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं।

**हालात संभालने को 67 कंपनियां तैनात :** गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद दोपहर तीन बजे के बाद केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल (सीआरपीएफ), रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और एसएसबी (सीमा सशस्त्र बल) की 67 कंपनियां हालात को काबू करने के लिए तैनात कर दी गई हैं। इन कंपनियों ने पहले मौजपुर के पास जाफराबाद रोड से भीड़ हटानी शुरू की। लेकिन, इसी दौरान अन्य इलाकों में हिंसा का दायरा बढ़ने लगा।

**सोमवार को पूरी रात हुई हिंसा :** दस थाना क्षेत्रों में धारा-144 लागू होने के बाद भी रातभर हिंसा होती रही। मंगलवार को दिन चढ़ने के साथ बवाल बढ़ता गया। गोकलपुरी में टायर मार्केट फूंका गया। सौ से ज्यादा दुकानों में आगजनी की गई। पुलिस ने 11 मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें हिंसा करने, सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमला, हत्या, हत्या के प्रयास जैसी धाराएं लगाई गई हैं। 25 उपद्रवियों को पकड़ा गया है।

**धार्मिक स्थलों में लगाई आग :** दंगाइयों ने गोकलपुरी में दो, अशोक नगर, बाबरपुर और चांद बाग में एक-एक धार्मिक स्थलों को दंगाइयों ने आग लगा दी। कई वाहनों को भी फूंक दिया। यमुना विहार में भजनपुरा पेट्रोल पंप के पास सौ से ज्यादा वाहन सड़क पर जले पड़े हैं। इनमें 50 कारें और इतनी ही मोटरसाइकिलें शामिल हैं। एक मिनी बस में आग लगाने के अलावा कई ई-रिक्शा, बाइक व अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।

**गोली लगने से हुई रतन लाल की मौत :** सोमवार को हिंसा के दौरान डीसीपी को बचाने के प्रयास में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत गोली लगने से हुई थी। मंगलवार को पोस्टमार्टम में यह बात स्पष्ट हो गई है। सोमवार को रतन लाल की मौत पत्थर लगने और पिटाई से होने का दावा किया गया था।

**आज भी परीक्षाएं स्थगित, स्कूल बंद :** उत्तर- पूर्वी दिल्ली में हिंसा और आगजनी के चलते बुधवार को भी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने उत्तर-पूर्वी इलाकों के स्कूलों में होने वाली परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है।

दो जवानों पर एसिड अटैक पेज>>2

## सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्वाइन फ्लू की चपेट में

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीश स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। हालांकि, तीन ने काम शुरू कर दिया है, जबकि दो घर में चिकित्सकीय निगरानी में हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई। इसमें स्वाइन फ्लू की रोकथाम व बचाव के उपायों पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट सीजीएचएस डिस्पेंसरी के डॉक्टरों के साथ चर्चा हुई। इसमें बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट में काम करने वालों के टीकाकरण का सुझाव दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों के घरों में रोकथाम व बचाव के उपाय शुरू कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं, इस बात का पता मंगलवार सुबह तब चला, जब मुकदमों की सुनवाई के लिए अदालत में बैठे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि कई न्यायाधीश स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने इसकी रोकथाम के लिए बैठक बुलाई है। मुख्य न्यायाधीश ने सुबह अदालत में बैठने से पहले इस पर बैठक की। इस कारण मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की अदालत 11 बजे बैठी, जबकि इसका सामान्य समय 10.30 बजे है।

सीजेआइ ने टीकाकरण का दिया सुझाव पेज>>3

### मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का निधन

**काइरो :** सत्ता से बेदखल किए जाने से पहले पश्चिम एशिया में स्थायित्व का निरंकुश चेहरा और करीब 30 साल तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे होस्नी मुबारक का मंगलवार को निधन हो गया। वह 91 साल के थे। (पेज-13)

### बच्चों के बीच फर्स्ट लेडी

दिल्ली के स्कूल में पहुंचीं अमेरिका की प्रथम महिला, निरीक्षक की तरह नहीं, छात्र की तरह की शिरकत

## हैप्पीनेस क्लास में मासूम सवालों से हैप्पी हुई मेलानिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

...अमेरिका कितना बड़ा है..., यहां से कितना दूर है?... आपको कौन सा कार्टून पसंद है?...ये कुछ ऐसे मासूम सवाल थे, जिनका सामना दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की प्रथम महिला को करना पड़ा। उन्होंने भी मासूम सवालों के जवाब मुस्कराते हुए दिए। पसंदीदा कार्टून पर मेलानिया का जवाब था-टॉम एंड जेरी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत दौरे पर आईं उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप मंगलवार दोपहर दक्षिणी दिल्ली के मोतीबाग स्थित सर्वोदय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल पहुंचीं और हैप्पीनेस क्लास में गईं। यही वह कार्यक्रम था, जिसे वह दिल्ली सरकार के स्कूल में देखने आई थीं।

हैप्पीनेस कार्यक्रम का संचालन कर रहीं शिक्षिका मनु गुलाटी ने बताया कि मेलानिया ने इसे न सिर्फ देखा बल्कि उन्होंने बच्चों के साथ करिकुलम के माइंडफुलनेस वाले हिस्से का अभ्यास भी किया। मेलानिया ने कहा, इससे मैं तनावमुक्त महसूस कर रही हूं। इसमें एक कार्यक्रम था जिसमें बच्चों को बताना था कि उनके साथी में कौन सी वह बात है जो उन्हें अच्छी लगती है। इसके अलावा कार्यक्रम का एक भाग यह भी था, जिसमें बच्चों को आभार नोट लिखना था। बच्चों ने आभार नोट लिखा तो मेलानिया ने भी ऐसा एक नोट लिखा, जिसे बच्चों के साथ उन्होंने भी हैप्पीनेस कक्षा की दीवार पर लगाया। उन्होंने लिखा, परिवार, दोस्त, स्वतंत्रता... खूबसूरत स्वागत के लिए आपका और आपके शिक्षकों का धन्यवाद।

अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप दक्षिणी दिल्ली के मोतीबाग स्थित सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों से बेहद आत्मीयता से मिली। एएनआइ

**मेलानिया का स्वागत :** मेलानिया के स्वागत के लिए स्कूल को फूलों व रंगोली से सजाया गया था। वह जैसे ही पहुंचीं बच्चों के बैंड ने स्वागत धुन बजाई। दीप प्रज्वलित करने के बाद मेलानिया सबसे पहले स्कूल की लाइब्रेरी में गईं, जहां रूम टू रीडिंग कार्यक्रम के तहत शिक्षिका दीपा ने कक्षा चार के बच्चों को एक कहानी सुनाई। कहानी थी- एक बच्ची को स्टेज पर कुछ बोलने में डर लगता था। उसने यह बात स्कूल के अपने दोस्तों को बताई। इस पर दोस्तों ने उसे हिम्मत दी और कहा, आप स्कूल के एक कार्यक्रम में गाना गाओ। बच्ची ने वैसे ही किया। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में कहानी को लेकर एक अन्य शिक्षिका प्रियंका ने बच्चों से सवाल पूछे।

**क्ले से बनाया फल :** इसके बाद मेलानिया एक्टिविटी रूम में गईं। यहां शिक्षिका आराधना व संगीता ने छोटे बच्चों से क्ले से फल और अन्य चीजें बनवाकर उन्हें दिखाईं। नन्हे हाथों से बनाई गई चीजों से वह इतना प्रभावित हुईं कि वह भी क्ले से उसे बनाने का प्रयास करने लगीं। उन्होंने छोटी बच्चियों को गले लगाया तथा बच्चों से हाथ मिलाया। उन्होंने बच्चों का योगाभ्यास भी देखा। इस दौरान छोटे बच्चों ने उन्हें सूर्य नमस्कार करके दिखाया।

गिफ्ट की मधुबनी पेंटिंग पेज>>3

## बिहार को एनआरसी की जरूरत नहीं एनपीआर का पुराना फॉर्मेट लाएं

- सीएम नीतीश कुमार की पहल पर विस ने सर्वसम्मति से पारित किया प्रस्ताव
- केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव, जाति जनगणना कराने की भी बनी सहमति

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया है कि बिहार को एनआरसी (नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजंस) की जरूरत नहीं और मामूली संशोधन के साथ एनपीआर (नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) का पुराना फॉर्मेट ही लागू होना चाहिए। दो घंटे की हंगामेदार चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने यह प्रस्ताव पढ़ा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसमें कहा गया कि 2010 के प्रारूप में ही एनपीआर को लाया जाए और इसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर संबंधित सूचना वाले कॉलम को बदलाव के रूप में जोड़ा जा सकता है। जाति जनगणना कराए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। इसे बाद में पारित किया जाएगा। हालांकि इस चर्चा के दौरान विधानसभा में हाथापाई की नौबत कड़ी मशक्कत के बाद टाली जा सकी।

**भाजपा ने भी दी सहमति :** मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन राजद और भाकपा (माले) ने एनआरसी और एनपीआर के मसले पर कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सभी की सहमति से विस से प्रस्ताव स्वीकृत होने पर केंद्र को भेजा जाए। भाजपा ने भी सदन में बिहार में एनआरसी नहीं लागू होने व एनपीआर के पुराने फॉर्मेट पर ही काम किए जाने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दी।

एनआरसी का कोई तुक ही नहीं पेज>>3

# शांति बहाली के लिए शाह ने सभी दलों से की अपील

**पहल** ▶ हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की, भड़काऊ बयान से बचने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश की राजधानी में जारी हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक की। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। सोमवार की रात उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी स्थानीय शांति समितियों को सक्रिय करने और उसमें सभी धर्म व वर्ग के लोगों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नेताओं को भड़काऊ बयान देने से बचने और आम जनता को अफवाहों से दूर रहने को कहा है।

गृहमंत्री ने दिल्ली में हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए सभी दलों से राजनीतिक मतभेद भुलाकर शांति बहाली के लिए एकजुट प्रयास करने की अपील की। साथ ही सभी पार्टियों से अपने सांसदों, विधायकों, काउंसलरों व समर्थकों को आम जनता के बीच भेजने का आग्रह किया, ताकि वे प्रभावित इलाकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर भय और अफवाह के माहौल को दूर कर सकें। उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त को शांति समितियों को सक्रिय कर जनता के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर विधुड़ी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के साथ-साथ गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

दिल्ली में भड़की हिंसा रोकने के लिए बुलाई गई बैठक में (बाएं से) उप राज्यपाल अनिल बैजल, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बैठक में हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। प्रेट्र

बैठक में अमूल्य पटनायक ने हालात को काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान घायल हुए हैं। सभी दलों ने हिंसा को तत्काल रोकने में सहयोग का भरोसा दिया। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने सभी लोगों से हिंसा को रोकने की अपील करते हुए कहा कि तत्काल शांति बहाली जरूरी है।

बैठक में दिल्ली में पुलिस बलों की पर्याप्त संख्या में तैनाती का मुद्दा भी उठा। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि हिंसा को रोकने में दिल्ली पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की सहायता मुहैया कराई जा रही है। अभी तक केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 35 कंपनियां दिल्ली में भेजी जा चुकी हैं और जरूरत पड़ने पर तत्काल अतिरिक्त केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल भेजे जा सकते हैं।

**शाह ने शहीद सिपाही की पत्नी को पत्र भेजकर जताया दुख** : गृह मंत्री शाह ने हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत को दुखद बताया। बाद में रतन लाल की पत्नी पूनम देवी को पत्र लिखकर संवेदना जताई। अमित शाह ने कहा, 'आपके पति सच्चे सिपाही थे, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है।'

## माहौल सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए सोमवार को आधी रात आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जहां उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे, वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई। इसमें हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के भाजपा विधायक व सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हालात खराब हुए हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। प्रभावित इलाकों के विधायकों को बुलाया था। भाजपा के विधायक भी आए थे। बैठक में तय किया गया कि जल्द से जल्द माहौल को सुधारने के प्रयास शुरू किए जाएं। माहौल सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अस्पतालों को आदेश दिया गया कि डॉक्टर और उनका स्टाफ मुस्तैद रहे। अग्निशमन विभाग को भी और सक्रिय होने के लिए कहा गया है। यदि प्रभावित इलाकों में दमकल पहुंचने में दिक्कत आ रही है तो पुलिस के साथ पहुंचें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे मुनादी कराएं और स्थानीय पुलिस के साथ शांति मार्च निकालें। शांति बनाए रखने की अपील करें। सभी लोगों को बुलाकर स्थानीय स्तर पर पीस कमेटी की बैठक करें। उसमें विधायक भी मौजूद हों। प्रभावित क्षेत्र के मंदिरों और मस्जिदों से शांति बनाए रखने की अपील की जाए। मुख्य सचिव भी बैठक में थे। उन्होंने बताया कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को बॉर्डर सील करने और ऐसे लोगों को दिल्ली में प्रवेश न करने देने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के सभी लोगों से अपील की कि शांति बनाए रखें।

**सक्रियता**

**प्रभावित इलाके की मस्जिदों व मंदिरों से शांति बनाए रखने की अपील करने का अनुरोध**

वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि लगता है कि शहर में दरिंदे घुस आए हैं। ये हमारी दिल्ली की आम जनता नहीं है। ये लोग जिस भी धर्म जाति और क्षेत्र से हैं। जो भी हो, उसे तुरंत पकड़कर अंदर डालना चाहिए। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

इस बीच दिल्ली में शांति बहाली की कोशिश के लिए केजरीवाल और सिसोदिया मंगलवार को राजघाट पहुंचे। दोनों ने यहां शांति के लिए प्रार्थना भी की।

## पुलिस फोर्स की कमी से बेकाबू हुई हिंसा

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गृह मंत्रालय को बताया कि फोर्स की कमी के चलते राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में भड़की हिंसा पर तत्काल काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि, बाद में दिल्ली पुलिस ने फोर्स की कमी की बात नकार दी।

एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि पर्याप्त फोर्स नहीं होने की वजह से हिंसा पर तत्काल काबू नहीं पाया जा सकता। इसकी वजह से हालात और बेकाबू हो गए। हालांकि, कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी मनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि बैठक में दिल्ली पुलिस की तरफ से कभी भी यह नहीं कहा गया कि उसके पास फोर्स की कमी थी। उन्होंने कहा, 'हमारे पास पर्याप्त फोर्स थी, जिसे मौके पर तैनात किया गया और अतिरिक्त फोर्स भी मिली है।' दिल्ली पुलिस ने अपनी सशस्त्र पुलिस की एक बटालियन (लगभग एक हजार जवान) को हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया है।

## परीक्षा केंद्र व तारीख बदलने पर सीबीएसई करे विचार : हाई कोर्ट

**जासं, नई दिल्ली** : उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के बीच बोर्ड परीक्षा केंद्र बदलने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। पीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को निर्देश दिया कि वह परीक्षा की तारीख या फिर परीक्षा केंद्र बदलने पर फैसला ले। पीठ ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला करे। याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

पूर्वी दिल्ली में सूर्या निकेतन स्थित भाई परमानंद विद्या मंदिर व इसके दसवीं व 12वीं कक्षा के कुछ छात्रों ने याचिका दायर कर कहा कि सीबीएसई द्वारा करावल नगर रोड स्थित जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वह 16 किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने में परीक्षार्थियों को 40 मिनट का वक्त लगता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस इलाके में हिंसा है और इससे उनकी जान को खतरा है। उन्होंने मांग की कि उनका परीक्षा केंद्र न्यू संध्या पब्लिक स्कूल को बनाया जाए और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें संसाधन व सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पीठ को बताया कि इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। अधिवक्ता कमल गुप्ता के माध्यम से याचिका में स्कूल प्रशासन ने याचिका में कहा कि जब उन्हें पता चला कि परीक्षा केंद्र उक्त क्षेत्र में आवंटित किया गया है, उन्होंने तत्काल इस संबंध में सीबीएसई को पत्र लिखा गया था।

# तीसरी बार दिखा राजधानी में तबाही का ऐसा मंजर

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

दंगाइयों के आतंक और दहशत के बीच वर्षों की मेहनत से बनाए गए आशियाने और दुकानें जल रही थीं और पुलिस असहाय नजर आ रही थी। कहीं बाइकें जल रही थीं तो कहीं कार और शोरूम लपटों और धुएं के गुबार में घिरा हुआ दिख रहा था। यह नजारा मंगलवार को उत्तर-पूर्वी जिले के कई क्षेत्रों का था। हालांकि हिंसा के तीसरे दिन पुलिस प्रवक्ता इलाके में पुलिसकर्मियों व पैरा मिलिट्री की संख्या बढ़ाने के साथ ही हालात नियंत्रण में होने का दावा कर रहे थे। राजधानी में तबाही का ऐसा मंजर 1984 और 1992 के बाद तीसरी बार देखने को मिल रहा है।

दिल्ली झुलस रही है और नेता ट्वीट कर लोगों को दिल्ली में जल्द शांति व्यवस्था बहाल होने का दिलासा दे रहे हैं। हालात पर जल्द काबू के लिए मंगलवार को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। इसमें पुलिस आयुक्त व उपराज्यपाल आदि अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के लोगों को उम्मीद थी कि बैठक के बाद कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा, जिससे सुलगती दिल्ली में शांति व्यवस्था बहाल हो सकेगी। लेकिन, नतीजा कुछ नहीं निकला। उत्तर-पूर्वी जिले के लोग जान माल की सुरक्षा को लेकर बेहद डरे सहमे नजर आए। पिछली तीन रातों से वह सोए नहीं और छतों या बालकनी में टहलकर आशियाने की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। दर्जनों परिवार अपने घरों में ताला लगाकर रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं।

दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में दंगाइयों ने कई घरों, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ध्रुव कुमार

इस घटना ने यमुनापार में रहने वाले लोगों की 1984 और 1992 में हुई सांप्रदायिक हिंसा की यादों को ताजा कर दिया है। उस समय भी यमुनापार ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। 84 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख बाहुल्य इलाकों में भीषण दंगे हुए थे। जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। वहीं 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। उस समय तत्कालीन डीसीपी दीपक मिश्रा ने सख्त कार्रवाई करते हुए दंगे पर काबू पा लिया था। वहीं इस बार जिस तरह से सरेआम दंगाई पुलिस की मौजूदगी में तीन दिन से अवैध हथियार लहराकर फायरिंग और उपद्रव कर रहे हैं। उससे कानून व्यवस्था कायम करने को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं।

## दंगे में घायल पुलिस उपायुक्त अमित की हालत खतरे से बाहर

**जासं, पूर्वी दिल्ली** : चांद बाग के पास दंगाइयों के हमले में गंभीर रूप से घायल शाहदरा के पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा की हालत अब खतरे से बाहर है। चोट लगने के कारण उनके सिर में खून का थक्का जम गया था। इसके बाद उन्हें पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूरो विभाग के डॉक्टरों ने देर रात उनका सफल ऑपरेशन किया।

अमित शर्मा से उनके परिजनों के अलावा पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक और पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर मिलने पहुंचे। गौतम गंभीर यहां इलाज करवा रहे एसीपी अनुज जैन और हेड कांस्टेबल यशपाल सिंह भी मिले। गंभीर ने दंगा करने वालों और भड़काऊ भाषण देने वालों की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। हिंसा दिल्ली की पहचान नहीं है। हम सब हमेशा से प्यार और शांति के साथ रहते आए हैं। मैक्स अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अमित शर्मा सहित कुल दस पुलिसकर्मी यहां भर्ती कराए गए थे। इनमें से तीन अभी भर्ती हैं। अमित शर्मा को ठीक होने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। दो से तीन दिन बाद उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। बता दें कि अमित शर्मा चांद बाग के पास दंगाइयों को काबू करने की कोशिश के दौरान घायल हो गए थे।

# हेड कांस्टेबल रतनलाल को शहीद का दर्जा देने की मांग

राज्य ब्यूरो, जयपुर

दिल्ली में सोमवार को उपद्रवियों की हिंसा में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल रतनलाल को शहीद का दर्जा देने की मांग उठी है। रतनलाल सीकर जिले के तिहावली गांव के रहने वाले थे। मंगलवार को उनके गृह ग्राम से लेकर राजस्थान विधानसभा तक में उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग उठी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है।

उनके निधन की खबर आने के बाद से गांव में शोक की लहर है। गांव की पंचायत पर उमड़े ग्रामीणों ने उन्हें शहीद का दर्जा देने के साथ ही आश्रितों को मुआवजा देने और गांव के स्कूल के स्टेडियम का नाम रतनलाल के नाम पर रखने की मांग की है। रतनलाल की मां संतरा देवी और भाई दिनेश गांव में ही परिवार के साथ रहते हैं। स्वजनों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि दो दिन पहले ही रतनलाल ने फोन पर मां और छोटे भाई से बातचीत की थी। तब रतनलाल ने मां से कहा था कि इस बार छुट्टी लेकर परिवार के साथ होली पर गांव आएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि करीब ढाई साल पहले ही रतनलाल के पिता बृजमोहन का निधन हुआ था। तीन भाइयों में रतनलाल सबसे बड़े थे। उनका एक छोटा भाई दिनेश गांव में ही खेतीबाड़ी कर और गाड़ी चलाकर आजीविका कमाता है। एक अन्य छोटा भाई रमाकांत बंगलुरु में रहकर निजी कामकाज करता है। रतनलाल वर्ष 1998 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में 12 साल की बेटी सिद्धि, 10 साल की बेटी कनक और सात साल का बेटा राम है।

**राजस्थान के सीकर जिले के थे रहने वाले, निधन पर सीएम सहित कई ने जताया दुख**

रतनलाल। फाइल

राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान फतेहपुर से विधायक हाकम अली ने बताया कि रतनलाल उनकी ही विधानसभा क्षेत्र के निवासी थे। ऐसे में राजस्थान सरकार से उनकी मांग है कि रतनलाल को शहीद का दर्जा दिया जाए। उनकी अंत्येष्टि में उन्हें शहीद जैसा ही सम्मान दिया जाए। राजस्थान विधानसभा में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में भी दो मिनट मौन रखकर रतनलाल को श्रद्धांजलि दी गई।

# भड़की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

**नई दिल्ली, एजेंसियां** : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के पक्ष-विपक्ष में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला और अन्य ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की अपील की है।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ के सामने याचिका को आपात सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था, जिस पर पीठ ने बुधवार को सुनवाई करने की बात कही। इसी पीठ में बुधवार को ही सीएए के विरोध में शाहीन बाग में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के मुद्दे पर सुनवाई होनी है।

हबीबुल्ला के अलावा नई याचिका दायर करने वालों में भीम आर्मी के

**हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए निर्देश देने की अपील**

प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और सामाजिक कार्यकर्ता बहादुर अब्बास नकवी का भी नाम है। इन तीनों ने शाहीन बाग के मुद्दे पर भी शीर्ष अदालत में हलफनामा के जरिए अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें इन्होंने दिल्ली-नोएडा के बीच कालिंदी कुंज के रास्ते यातायात ठप होने के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की मांग की है।

वजाहत हबीबुल्ला और अन्य ने दिल्ली में भड़की हिंसा के लिए भाजपा नेता कपिल मिश्र को जिम्मेदार ठहराया है। इन्होंने कहा है कि 23 फरवरी को कपिल मिश्र सीएए के समर्थन में रैली करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मौजपुर-बाबरपुर के पास जमा हुए। उससे कुछ ही दूरी पर सीएए के विरोध में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। आरोप लगाया है कि कपिल मिश्र अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसा कर वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद ही जाफराबाद इलाके में हिंसा भड़क गई थी। अब शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को भी जाफराबाद और चांदबाग की तरह की घटना की धमकी दा जी रही है।

**हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई** : सीएए को लेकर भड़की हिंसा पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी बुधवार को सुनवाई होगी। मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर और फराह नकवी ने याचिका दायर की है। इन दोनों ने भी हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। इन लोगों ने खासकर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्र के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए कार्रवाई करने की मांग की है।

## दिल्ली की हिंसा को लेकर मुंबई में हाई अलर्ट

**मुंबई, एएनआइ** : राष्ट्रीय राजधानी में सीएए को लेकर हिंसक घटनाओं को देखते हुए मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस ने सतर्कता के कदम उठाए हैं। अधिकारी ने कहा कि निर्धारित आजाद मैदान इलाके को छोड़कर मुंबई में किसी भी अन्य जगह पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**हैदराबाद पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने को कहा**

**हैदराबाद, प्रेट्र** : दिल्ली में हुई हिंसा को ध्यान में लेते हुए हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने शहर के लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अफवाह फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

# दिल्ली और अलीगढ़ हिंसा में है संबंध

**नई दिल्ली, आइएएनएस** : दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालिया हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) और भीम आर्मी का हाथ होने का संदेह है। पिछले दो दिनों से दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में हो रही आगजनी और फायरिंग की घटनाओं के साथ-साथ अलीगढ़ में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लिंक भी मिला है। कुछ प्रमुख मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) के आधार पर उत्तर प्रदेश इंटेलीजेंस की रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, अलीगढ़ के आंबेडकर पार्क में विरोध प्रदर्शन करने वाले भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के बाद पीएफआइ के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के छात्रों के एक

**यूपी इंटेलीजेंस की रिपोर्ट**

**पीएफआइ व भीम आर्मी के हाथ का संदेह**

समूह ने भी भीम आर्मी और पीएफआइ के नेताओं से मुलाकात की थी। तत्पश्चात भीम आर्मी के नेतृत्व में एक बड़ा समूह शहर के प्रमुख स्थान पर स्थित धार्मिक स्थल पर पहुंचा और पोस्टर हटाने के साथ-साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। अलीगढ़ पुलिस के एक सर्किल ऑफीसर (सीओ) ने फोन पर बताया, 'अलग-अलग स्थानों पर एक साथ हिंसक घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि यह (पथराव) पूर्व नियोजित है और इसका दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में हुई हिंसा से लिंक है। हम कुछ अहम फोन कॉल डाटा का सत्यापन कर रहे हैं।'

**पीएफआइ के खाते से प्रदर्शकारियों के खातों में ट्रांसफर हुई धनराशि** : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि पीएफआइ ने अपने खाते से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई लोगों के खातों में धनराशि ट्रांसफर की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे कुल 73 खातों की पहचान की गई है। ईडी रिपोर्ट के मुताबिक, बड़े लेन-देन पीएफआइ के दिल्ली स्थित मुख्य खाते से किए गए हैं। पीएफआइ का राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित है। ईडी ने पीएफआइ के नेताओं और भीम आर्मी पदाधिकारियों के बीच लिंक का भी पता लगाया है। पीएफआइ दिल्ली का अध्यक्ष मुहम्मद परवेज अहमद शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख रूप से सक्रिय है।

**रखी बात**

अभिभाषण में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील, कहा-सुरक्षा एजेंसियों को करें सहयोग, सरकार की दस गारंटी का जिक्र, केंद्रीय कर में दिल्ली को ज्यादा हिस्सेदारी देने की मांग

# एलजी ने पेश किया विश्वस्तरीय शहर बनाने का खाका

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की सातवीं विधानसभा के प्रथम सत्र के अभिभाषण में उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने का खाका पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने विधायकों और दिल्लीवासियों से शांति, कानून-व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सभी को सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए।

अभिभाषण में आप सरकार के पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां और दस गारंटी को विस्तार से बताने के साथ ही केंद्रीय कर में दिल्ली को अन्य राज्यों की तरह ज्यादा हिस्सा देने की मांग की गई। वर्ष 2001 से पहले केंद्रीय करों में दिल्ली के विकास के लिए हिस्सेदारी की व्यवस्था थी जिसे फिर से शुरू करने और यहां के नगर निगमों को भी केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के

दिल्ली विधानसभा में अभिभाषण देते उपराज्यपाल अनिल बैजल (बाएं)। इस दौरान बैठे विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल (दाएं)। सौजन्य : दिल्ली सरकार

अनुसार धनराशि मिलनी चाहिए। छात्रों को भी मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत किया और उसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उपराज्यपाल ने शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न होने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने सरकार और इसकी नीतियों पर लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए विश्वास व्यक्त किया है। पिछले कार्यकाल में सरकार ने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों अर्थात बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया और 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवाओं को मोहल्ला क्लीनिक के माध्यम से लोगों के करीब ले जाने, श्रमिकों को देश में सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी देने जैसी योजनाएं शुरू की थीं। इसके साथ ही सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी एवं तीर्थ यात्रा योजना को भी लोगों ने सराहा है। इन कल्याणकारी गतिविधियों को और आगे बढ़ाने और दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जन-कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दस गारंटी द्वारा सुनिश्चित की गई है।

## दो जवानों पर एसिड अटैक

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

करावल नगर में दंगे पर नियंत्रण के लिए पहुंची सीआरपीएफ जवानों पर दंगाइयों ने छतों से तेजाब फेंक दिया। इसमें दो जवान झुलस गए। उन्हें पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दंगाई इससे पहले भी ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल करते आ रहे थे। मौजपुर के पास बोतलों में मिर्च के पाउडर तक फेंके गए थे। लेकिन, तेजाब की यह पहली घटना है। भजनपुरा में दंगा नियंत्रण के लिए सीआरपीएफ की कंपनी बस से पहुंच रही थी, लेकिन रास्ते में ही बस खराब हो गई। इसके बाद जवान पैदल की मौके पर पहुंच गए।

**मुस्लिम परिवार को सुरक्षित निकाला** : कुछ मुस्लिम परिवार की महिलाएं दंगे में फंस गईं। सुरक्षाकर्मियों को जैसे ही इनके बारे में पता चला, वे मौके पर पहुंच गए और सुरक्षा घेरा बनाकर इन महिलाओं के साथ उनके बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाला।

**घायलों को सुरक्षाकर्मियों ने दिया खून** : दंगे में सुरक्षाकर्मियों पर हमले करने वाले जब जख्मी हो गए तो वही जवान उनके लिए संकटमोचक भी बन गए। पहले तो उन्हें अपने इन जवानों ने जीटीबी अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद जब कुछ घायलों को खून देने की बारी आई तो भी यही जवान आगे आ गए।

**उत्तर-पूर्वी जिले में आज भी परीक्षाएं स्थगित, स्कूल बंद** : उत्तर- पूर्वी दिल्ली के स्कूल बुधवार को भी बंद रहेंगे। वहीं, सीबीएसई ने उत्तर-पूर्वी इलाकों के स्कूलों में होने वाली परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी के मुताबिक उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 86 स्कूलों में बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां 26 फरवरी को होने वाली दसवीं की अंग्रेजी विषय और 12वीं में वेब एप्लीकेशन और मीडिया विषय की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। उत्तर-पूर्वी सहित पूर्वी जिला के भी सात परीक्षा केंद्रों में परीक्षा को स्थगित किया गया है। जिन केंद्रों पर परीक्षा स्थगित की गई है उसका विवरण सीबीएसई ने वेबसाइट पर दे दिया है।

**22** वें विधि आयोग के गठन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। सरकार को जटिल विधिक मामलों पर सलाह देने वाले इस आयोग का कार्यकाल तीन साल का होगा। पिछले आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 को खत्म हो गया था।



## कुणाल कामरा मामले में हाई कोर्ट ने डीजीसीए से जवाब मांगा

**जासं, नई दिल्ली :** एयरलाइंस के प्रतिबंध के खिलाफ मंगलवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। कुणाल कामरा की याचिका पर न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से कहा कि इंडिगो के अलावा अन्य एयरलाइंस द्वारा कामरा पर लगाए गए अनिश्चितकालीन प्रतिबंध को उसे प्रमाणित नहीं करना चाहिए था। पीठ ने डीजीसीए से सवाल किया कि आपने ट्विटर पर सर्टिफिकेशन क्यों दिया? पीठ ने कहा 'आप अपना ट्वीट देखिए, आपने कहा कि विभिन्न एयरलाइन्स द्वारा की गई कार्रवाई सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) के तहत है। आपने इंडिगो ही नहीं, अन्य एयरलाइंस को भी सर्टिफिकेशन दिया। आपको अपना ट्वीट हटाना चाहिए।' कामरा पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में एक चैनल के पत्रकार से बदसुलूकी करने का आरोप है।

पीठ ने इसके साथ ही डीजीसीए से कहा कि अब आपको अदालत को संतुष्ट करना पड़ेगा कि सीएआर के तहत एयरलाइंस की कार्रवाई सही थी। सुनवाई के दौरान डीजीसीए की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि मामले में पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। इस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।

# पवार से पूछताछ कर सकता है भीमा-कोरेगांव जांच आयोग

**जांच की आंच** ▶ फड़नवीस को भी समन करने की बात कर चुका है आयोग

### यलगार परिषद की सभा के एक जनवरी, 2018 को भड़की थी जातीय हिंसा

**राज्य ब्यूरो, मुंबई**

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रहा दो सदस्यीय आयोग पूछताछ के लिए राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को बुला सकता है। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जरूरत पड़ने पर पवार के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को बुलाया जा सकता है।

शरद पवार कई बार कह चुके हैं कि एक जनवरी, 2018 को भड़की भीमा-कोरेगांव की जातीय हिंसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित तत्वों का हाथ था। इस संबंध में वह आठ अक्तूबर, 2018 को एक शपथपत्र भी जांच आयोग के सामने दाखिल कर चुके हैं। इसी महीने की 18 तारीख को भी पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं मिलिंद एकबोटे एवं शंभाजी भिड़े का नाम लेते हुए कहा

शरद पवार। फाइल

कि इन दोनों ने ऐसा वातावरण बनाया, जिसके कारण एक जनवरी, 2018 को भीमा-कोरेगांव में हिंसा भड़की। उन्होंने पुणे के पुलिस आयुक्त की भूमिका को संदेहास्पद बताते हुए इसकी जांच पर बल दिया था।

बता दें कि शरद पवार के तर्कों के विपरीत पुणे पुलिस ने इस हिंसा के लिए 31 दिसंबर, 2017 की शाम पुणे स्थित शनिवार वाड़ा के बाहर आयोजित यलगार परिषद की सभा में दिए गए भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने यह भी कहा था कि इस सभा का आयोजन महाराष्ट्र में जातीय हिंसा भड़काने के लिए माओवादियों के सहयोग से किया गया था।

पवार द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद एक सामाजिक संगठन विवेक विचार मंच के कार्यकर्ता सागर शिंदे ने जांच आयोग के सामने एक आवेदन देकर पवार से पूछताछ करने की अपील की है। उनका कहना है कि पवार के पास ऐसी और भी कई जानकारियां हैं, जिनका जिक्र उन्होंने शायद अपने शपथपत्र में नहीं किया है। इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए।

जांच आयोग के वकील आशीष सातपुते के अनुसार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जेएन पटेल ने संकेत दिए हैं कि जांच प्रक्रिया के अंतिम चरण में शरद पवार को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जांच आयोग में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक हैं। हाल ही में उद्धव सरकार ने आयोग का कार्यकाल बढ़ाते हुए इसे आठ अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। आयोग का गठन पूर्व की फड़नवीस सरकार ने किया था।

## विदेशी वकील को नहीं दे सकते जेल में कैदी से मिलने की अनुमति

**जासं, नई दिल्ली :** अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल ने विशेष अदालत में अर्जी दायर कर एक विदेशी वकील से मुलाकात करने की मांग की। अदालत ने इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नियमों के मुताबिक विदेशी वकील को जेल में बंद कैदी से कानूनी मुलाकात की मंजूरी नहीं दे सकते। विशेष कोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि विदेशी वकील एक मित्र की तरह तिहाड़ में बंद कैदी से मिल सकता है, लेकिन कानूनी मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिल्ली जेल नियमावली सिर्फ उन्हीं वकीलों को जेल में बंद कैदी से कानूनी मुलाकात की अनुमति देती है, जो अधिवक्ता अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। क्रिश्चियन मिशेल ने विशेष अदालत में अर्जी दायर कर मांग की थी कि उसे अपने देश ब्रिटेन के वकील से मुलाकात की अनुमति दी जाए। सीबीआइ ने मिशेल की इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी-अपनी जांच के आधार पर आरोपपत्र दायर कर चुके हैं। मिशेल को इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा करने और करीब 225 करोड़ रुपये लेने का आरोपित बनाया है।

# दोषियों को अलग-अलग फांसी की इजाजत पर सुनवाई टली

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

**निर्भया मामला**

- केंद्र ने एक साथ फांसी के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती
- कोर्ट पहले ही कर चुका है स्पष्ट- इस याचिका के लंबित रहने का डेथ वारंट जारी होने पर नहीं होगा असर

दिल्ली दुष्कर्म कांड यानी निर्भया कांड के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की इजाजत मांगने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पांच मार्च तक टाल दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस याचिका के लंबित रहने का निचली अदालत से दोषियों की फांसी का डेथ वारंट जारी होने पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तीन मार्च सुबह छह बजे का वक्त तय कर दिया है।

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी। दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती। केंद्र की याचिका मंगलवार को न्यायमूर्ति आर. भानुमति, अशोक भूषण और नवीन सिन्हा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगी थी। लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई पांच मार्च तक के लिए टाल दी। निचली अदालत ने चारों दोषियों-मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को फांसी देने के लिए तीन मार्च की तारीख तय की है। तीन दोषी मुकेश, अक्षय और विनय की दया याचिका तक खारिज हो चुकी है, लेकिन अभी तक चौथे दोषी पवन ने न तो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है और न ही राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की है। हालांकि चारों दोषियों को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए कोर्ट द्वारा तय सात दिन का समय समाप्त होने के बाद ही निचली अदालत ने तीन मार्च को फांसी देने की नई तिथि तय की थी। इससे पहले दो बार और तारीखें तय की जा चुकी हैं, जो कि बाद में बदल दी गईं थीं।

**क्या है मामला**

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में पैरा मेडिकल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छात्रा के साथ इस कदर दरिंदगी हुई थी कि बाद में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इन मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से चारो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।

# अगले साल टिड्डी दलों के बेस पर ही होगा हमला

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

**समीक्षा बैठक**

- भारतीय सीमा पर तैनात बीएसएफ को सौंपी जाएगी इसकी खास जिम्मेदारी
- भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और बांग्लादेश करेंगे साझा आक्रमण

वैसे तो इस बार भारत अपनी सीमा में घुसते ही टिड्डी दलों के सफाये में सफल रहा है, लेकिन अगले साल उसके पैदाइश वाले स्थान (बेस) पर ही हमला बोलने की तैयारी की जा रही है। भारतीय सीमा पर तैनात बीएसएफ को इसकी खास जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस हमले में भारत का साथ टिड्डी दलों से प्रभावित होने वाले अन्य पड़ोसी देश देंगे।

फसलों को पलक झपकते ही नष्ट करने वाले इन टिड्डी दलों के बेस पर हमला करने में भारत का साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और बांग्लादेश देंगे। इसे लेकर इन देशों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने मंगलवार को यहां हुई समीक्षा बैठक में चालू सीजन में टिड्डी दलों से निपटने में आई चुनौतियों के साथ आगामी रणनीति को पुख्ता बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगले साल की तैयारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था कृषि व खाद्य संगठन (एफएओ) के साथ आगे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बार एफएओ के प्रतिनिधि ने 16 और 17 जनवरी को यहां का दौरा कर टिड्डी दलों का मुकाबला करने में भारत की तत्परता पर संतोष जताया था।

कृषि सचिव अग्रवाल ने लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, राज्यों के कृषि विभागों, सीमा सुरक्षा बल और किसानों के उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए कहा कि अगले साल के लिए हर तरह की मदद समय से मुहैया करा दी जाएगी। इससे टिड्डी दलों का मुकाबला करने में सहूलियत होगी। इसके पहले सभी राज्यों में किसानों के साथ स्थानीय अधिकारियों की मदद से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हर हाल में हम टिड्डी दलों का सफाया करके रहेंगे।

# राज्यसभा की 55 सीटों पर 26 मार्च को होंगे चुनाव

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

**गुणा-भाग**

- फिलहाल उच्च सदन में बहुमत से दूर ही रहेगी सत्तारूढ़ भाजपा
- उपसभापति हरिवंश, मंत्री आठवले व हरदीप पुरी हो रहे रिटायर

संसद भवन। फाइल

राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होंगे। चुनाव के बाद भी सत्तारूढ़ भाजपा अपने दम पर उच्च सदन में बहुमत से दूर ही रहेगी। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। आयोग के मुताबिक, 17 राज्यों से निर्वाचित 51 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। इनमें सदन के उपसभापति हरिवंश, शरद पवार, मोतीलाल वोरा, केंद्र में मंत्री रामदास आठवले, हरदीप सिंह पुरी, कांग्रेस के सदस्य दिग्विजय सिंह, डॉ. संजय सिंह, कुमारी शैलजा, विजय गोयल, प्रेमचंद गुप्ता, तिरुचि शिवा आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा चार सीटें सदस्यों के त्यागपत्र के चलते खाली हुई हैं।

कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना छह मार्च को जारी होगी। 13 मार्च को नामांकन, 16 को नामांकन पत्रों की जांच और 18 मार्च को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है। महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और बंगाल से चुने गए सदस्य दो अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल के सदस्यों का कार्यकाल नौ अप्रैल और मेघालय के सदस्यों का कार्यकाल 12 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा।

महाराष्ट्र में सात सीटें, तमिलनाडु में छह सीटें, बंगाल और बिहार में पांच-पांच, ओडिशा, गुजरात और आंध्र प्रदेश में चार-चार सीटें, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन सीटें, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड में दो-दो और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में एक-एक सीट रिक्त हो रही है। राज्यसभा में भाजपा के पास फिलहाल 83 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 45 सीट। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसकी सीटों की संख्या में कुछ इजाफा हो सकता है। 26 मार्च को होने वाले चुनाव से सबसे अधिक फायदा तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस को हो सकता है, जिनके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है।

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने वाला है। यहां से निर्वाचित दिग्विजय सिंह, प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल नौ अप्रैल को पूरा हो रहा है। 230 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में विधायकों की संख्या के आधार पर माना जा रहा है कि तीन में से दो सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी विजयी हो सकते हैं। दोनों बड़े दलों में राज्यसभा जाने के इच्छुक दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है।

### तारीख तय होते ही उछलने लगे उम्मीदवारों के नाम

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली**

राज्यसभा की खाली होने वाली सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही लॉबिंग शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दल के नेता अपनी-अपनी दावेदारी करने में जुट गए हैं। पार्टियां भी जातीय समीकरण के साथ ही आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी तय करने की जुगत में जुटी हैं।

**छत्तीसगढ़ में अटल की भतीजी करुणा की चर्चा :** छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें से एक सीट से अभी भाजपा के रणविजय सिंह जूदेव और दूसरी से कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा सदस्य हैं। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर अब दोनों सीट कांग्रेस के खाते में चली जाएंगी। इसी वजह से कांग्रेस के दावेदारों ने रायपुर से दिल्ली तक की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस से टिकट के दावेदारों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का नाम भी शामिल है। शुक्ला के साथ प्रदेश संगठन के महामंत्री गिरीश देवांगन का नाम भी दावेदारों में सबसे आगे माना जा रहा है।

**हरियाणा में कई हैं दावेदार :** हरियाणा में एक सीट इनेलो के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे रामकुमार कश्यप के इस्तीफा देने से खाली हुई, जबकि दूसरी सीट नौ अप्रैल को कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य कु. सैलजा का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो जाएगी। दोनों सीटों पर भाजपा-जजपा गठबंधन के साथ ही कांग्रेस नेता लॉबिंग में जुट गए हैं। भाजपा में जातीय समीकरणों के आधार पर ओमप्रकाश धनखड़, प्रो. रामबिलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और सुधा यादव के नाम चर्चा में हैं, जबकि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के नाम लिए जा रहे हैं। सैलजा को भी दोबारा राज्यसभा भेजा जा सकता है।

## बीके शर्मा समिति ने असम समझौते के अनुच्छेद छह पर सौंपी रिपोर्ट

**गुवाहाटी, प्रेट्र :** असम समझौते के अनुच्छेद छह पर एक उच्चस्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। यह अनुच्छेद असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषायी पहचान और विरासत के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया कराता है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति के चेयरमैन जस्टिस (सेवानिवृत्त) बीके शर्मा ने राज्य मंत्रिमडल की मौजूदगी में रिपोर्ट सौंप दी। सील बंद लिफाफा सौंपने के बाद जस्टिस शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट सौंपने के पहले समिति ने पूरे असम के लोगों से मुलाकात की है।

राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सोनोवाल बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट के आधार पर आगे के कदमों का फैसला करेगा। हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (एएएसयू) के मुख्य सलाहकार डॉ. समुज्जल भट्टाचार्य, अध्यक्ष दीपांकर नाथ और महासचिव लुरिंगज्योति गोगोई समिति में शामिल थे, लेकिन रिपोर्ट सौंपे जाने के मौके पर वे लोग उपस्थित नहीं थे।

# नीतीश ने सदन में प्यार से समझाया और तेजस्वी यादव उनसे मिलने पहुंच गए

**राज्य ब्यूरो, पटना**

बिहार की राजनीति में मंगलवार का दिन उठापटक और चौंकाने वाला रहा। बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ, लेकिन एनसीआर और एनपीआर को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव और बहस के बाद घटित घटनाएं चर्चा में रहीं। दिन में एनपीआर पर कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को समझाया कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। इस क्रम में तेजस्वी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू और राजद के बीच हुए गठबंधन और उसके बाद भाजपा के साथ चले जाने की घटना की चर्चा की। जवाब में नीतीश ने तेजस्वी से कहा कि 'आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इन बातों की चर्चा का अधिकार आपके पिताजी को है।'

नीतीश से तेजस्वी की भेंट भी चर्चा में आ गई है। मुख्यमंत्री सदन में जाने ही वाले थे कि राजद नेता ललित यादव ने नीतीश को जाकर यह कहा कि तेजस्वी उनसे मिलने आना चाहते हैं। उनकी सहमति के तुरंत बाद तेजस्वी वहां पहुंच गए।

### एनआरसी का कोई तुक ही नहीं

**प्रथम पृष्ठ से आगे**

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआरसी का कोई तुक नहीं है। इसलिए इसे लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य का भी जिक्र किया, जिसमें पीएम ने यह कहा है कि एनआरसी की कोई योजना नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि एनपीआर में जो नए प्रावधान किए गए है, उससे यह खतरा है कि अगर भविष्य में कभी एनआरसी लागू होता है, तो इसका बड़ा नुकसान होगा। यह जरूरी है कि एनपीआर के तहत 2010 में जो सूचनाएं संग्रह की जा रही थीं, उन्हें ही जारी रखा जाए। इससे आम लोगों को कठिनाई नहीं होगी। वैसे भी अभी एनपीआर के उन प्रश्नों को अधिसूचित नहीं किया गया है, जो एनपीआर के नए फॉर्मेट के तहत पूछे जाने हैं। राज्य सरकार की ओर से इस आशय का एक आधिकारिक पत्र भी 15 फरवरी को केंद्र को भेजा गया है।

**माता-पिता के जन्मदिन पूछने की क्या जरूरत :** मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीआर के नए फॉर्मेट में माता-पिता के जन्म दिन, जन्म स्थान व अन्य जानकारी मांगी जाएगी, जो स्वाभाविक नहीं है। उन्होंने कहा कि संशय की कोई बात नहीं, क्योंकि एनपीआर के नए फॉर्मेट को लागू नहीं करने का अनुरोध बिहार से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भेजा गया है। इस विभाग के मंत्री भाजपा के हैं। समाज के किसी भी तबके की उपेक्षा नहीं होगी। समाज में अनावश्यक रूप से विवाद पैदा नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सीएए की चर्चा करते हुए एक दस्तावेज भी सदन में पढ़ा जिसमें यह बताया गया कि लालू प्रसाद भी इसके पक्ष में रहे हैं। कपिल सिब्बल और कांग्रेस के अन्य दिग्गजों का भी नाम लिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का भी जिक्र आया जिसमें यह कहा कि राज्यसभा में किस तरह से उन्होंने सीएए के समर्थन में अपनी बात कही थी।

# सीजेआइ ने टीकाकरण का दिया सुझाव

**प्रथम पृष्ठ से आगे**

मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठक में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे और सचिव अशोक अरोड़ा भी मौजूद थे। बैठक में बचाव के उपायों पर चर्चा हुई। मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों और वकीलों को संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण का सुझाव दिया। एचवन एनवन टीके की कीमत 1,539 रुपये हैं।

दुष्यंत दवे ने कहा कि जो वकील टीके की कीमत वहन नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए वह 10 लाख रुपये की पेशकश करते हैं। बैठक के बाद एससीबीए ने बुधवार को स्वाइन फ्लू संक्रमण से बचाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए दोपहर में 1.10 बजे वकीलों के बार लाउंज में बैठक करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सीजीएचएस डिस्पेंसरी टीकाकरण और उपचार के लिए स्पेशल क्लीनिक भी कोर्ट परिसर में खोलेगी।

मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भी वरिष्ठ वकील ए सुंदरम से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एचवन एनवन फैल रहा है।

### स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने और मुख्य न्यायाधीश की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोकथाम और बचाव के उपाय शुरू कर दिए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीश स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। यह एचवन एनवन वायरस के कारण होता है। प्रोटोकॉल के अनुसार सभी न्यायाधीशों के इलाज व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों के संपर्क में आने वाले उनके परिवार के सदस्यों सहित सभी का संक्रमण रोकने के लिए उपचार किया गया है। बताया गया है कि इन पांच न्यायाधीशों को घर में अलग रखा गया है। इनमें से तीन न्यायाधीशों ने अपना काम शुरू कर दिया है और दो न्यायाधीश घर में निगरानी में हैं और स्वस्थ हो रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अदालत कक्षों और रिहायशी स्थानों की सफाई की गई है। सभी संबंधित लोगों में इससे बचाव के लिए जागरूकता लाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय बुधवार को बार काउंसिल कार्यालय में वकीलों और कर्मचारियों के बीच एचवन एनवन पर कार्यशाला भी आयोजित करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एचवन एनवन एक मौसमी संक्रमण है, जो आमतौर पर जनवरी से मार्च और जुलाई से सितंबर के बीच होता है। मंत्रालय ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है ताकि यह संक्रमण न फैले।

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आप सभी से अनुरोध है कि जो ठीक नहीं महसूस कर रहे वे अदालत न आएं। मालूम हो कि कुछ दिन पहले जस्टिस भानुमति निर्भया मामले के दोषियों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए बेहोश हो गई थीं। बीच में एक दिन जस्टिस एनवी रमना मास्क लगा कर कोर्ट में बैठे थे। मंगलवार को जस्टिस संजीव खन्ना को मास्क लगा कर कोर्ट में बैठे देखा गया।

**ईडी की कार्रवाई**

दो चरणों में होने वाली नीलामी प्रक्रिया में एमएफ हुसैन और अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स और लग्जरी कारें रॉल्स रॉयस घोस्ट और पोर्श पनामरा की भी लगेगी बोली

# नीरव मोदी की कारें, घड़ियां-पेंटिंग बेचकर होगी वसूली

**मुंबई, आइएएनएस :** पीएनबी घोटाले का आरोपित और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कीमती 112 संपत्तियों की 27 फरवरी से लाइव और ऑनलाइन नीलामी होगी। इन संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न बैंकों की बकाया वसूली के सिलसिले में जब्त किया है। दो चरणों में होने वाली नीलामी प्रक्रिया में नीरव मोदी की मिल्कियत वाली महत्वपूर्ण कलाकृतियां, कीमती घड़ियां और हैंडबैग तथा दो कारों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान मशहूर कलाकार एमएफ हुसैन और अमृता शेरगिल की पेंटिंग और लग्जरी कारें रॉल्स रॉयस घोस्ट और पोर्श पनामरा भी नीलाम की जाएंगी।

पहली नीलामी का आयोजन सैफरनआर्ट नामक कंपनी की तरफ से स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में गुरुवार से किया जाएगा। इसके अगले चरण स्प्रिंग ऑनलाइन ऑक्शन का 3-4 मार्च तक आयोजन होगा। जिन पेंटिंग्स की नीलामी होनी है उनमें शेरगिल की 'ब्वॉज विद लेमंस' और 'बैटल ऑफ गंगा एंड यमुना महाभारत 12' शामिल हैं। शेरगिल ने अपनी मशहूर पेंटिंग

नीरव मोदी। फाइल

**27 फरवरी से शुरू होगी लाइव और ऑनलाइन नीलामी**

वर्ष 1935 में बनाई थी, जबकि हुसैन की कृति वर्ष 1972 की है। माना जा रहा है कि दोनों ही पेंटिंग की 12-18 करोड़ रुपये तक बोली लग सकती है। शेरगिल की पेंटिंग को पहली बार सार्वजनिक बोली के लिए उतारा जा रहा है। इसी प्रकार वीएस गायतोंडे की अनाम पेंटिंग से सात-नौ करोड़ रुपये हासिल हो सकते हैं, जिसे उन्होंने वर्ष 1972 में बनाई थी। वर्ष 1992 में बनाई गई मंजीत बावा की भगवान कृष्ण की पेंटिंग को तीन से पांच करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। राजा रवि वर्मा की एक अनाम पेंटिंग की दो-तीन करोड़ और वर्ष 1996 में बनाई गई अर्पिता सिंह की 'ट्वेंटी सेवन डक्स ऑफ मेमोरी' की 1.20-1.80 करोड़ रुपये की बोली लग सकती है। गणेश पाइन, केके हेब्बार, विश्वनाथ नागेशकर, सुधांशु चौधरी और शान भटनागर की पेंटिंग की बोली करोड़ रुपये तक हो सकती है।

रॉल्स रॉयस घोस्ट कार को लाइव नीलामी में पेश किया जाएगा। इसमें कई विशेष फीचर, अत्याधुनिक तकनीक और आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। इसकी बोली 75-95 लाख तक लग सकती है। इसी प्रकार वर्ष 2010 मॉडल पोर्श पनामरा के लिए 10-15 लाख रुपये मिल सकते हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपये की दो दर्जन लग्जरी सामग्री की भी नीलामी की जाएगी। एयगर-ला-कोट मेंस की 'रिवर्सो गिरोटोर्बिलन 2' लिमिटेड एडिशन और पटेक फिलिप नॉटिलस गोल्ड एंड डायमंड घड़ी की नीलामी से 55-70 लाख रुपये मिलने की उम्मीद है। नीलामी में कई बड़े ब्रांडों के हैंडबैग भी रखे जाएंगे। इनकी कीमत 3-6 लाख रुपये है। इसके अलावा नीरव के कीमती सामान के निजी संग्रह को भी नीलाम किया जाएगा। संयोग है कि सैफरनआर्ट ईडी के लिए नीलामी कराने से पहले मार्च 2019 में आयकर विभाग के लिए भी नीलामी का आयोजन कर चुका है।

### गिफ्ट की मधुबनी पेंटिंग

**प्रथम पृष्ठ से आगे**

हैप्पीनेस क्लास से जब वह बाहर आई तो भारत और अमेरिकी झंडा लिए बच्चों को देखकर वह काफी प्रभावित हुईं। इस दौरान वह बच्चों व वहां के शिक्षकों से घुलती-मिलती नजर आईं। मेलानिया को यादगार के तौर पर कक्षा नौ की छात्राओं संजना, नेहा, लताशा और खुशबू ने मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की। मेलानिया ने इन बच्चियों के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाई। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान के पधारो म्हारे देश गीत पर छात्राओं ने प्रस्तुति दी। इसके बाद स्टेज पर भंगड़ा नृत्य हुआ। भांगड़ा करने वाले सिख बच्चे को मेलानिया ने बुलाकर गले लगाया। नर्सरी कक्षा की एक बच्ची ने हाथ मिलाने की जगह उनका हाथ ही पकड़ लिया। पूरे आयोजन में वह बच्चों के साथ आनंदित दिखीं। इस पूरे आयोजन में स्कूल के करीब 450 बच्चों ने भाग लिया।

**कह के रहेंगे** — माधव जोशी

**31** मार्च तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पनामा और पैराडाइज पेपर्स की जांच और अभियोजन शुरू करने के लिए अपनी रिपोर्ट दाखिल कर देगा।

**2017** में पैराडाइज पेपर्स मामले में 714 कंपनियों और व्यक्तियों के नाम सामने आए थे। विदेश में खाता रखने वाली करीब 426 कंपनियां आयकर विभाग की निगाह में थीं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 26 फरवरी 2020

# किसानों की कर्जमाफी की पहली सूची को लेकर गर्माई महाराष्ट्र की सियासत

**दो टूक** ▶ नेता प्रतिपक्ष फड़नवीस ने कहा, ऐसे तो किसानों की कर्जमाफी में लगेंगे 460 दिन

## विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के सामने पहुंच गए

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र सरकार की ओर से सोमवार को कृषि कर्जमाफी योजना के तहत 15,358 लाभार्थियों की पहली सूची जारी करने के बाद राज्य में इस मसले पर सियासत गर्मा गई है। इस मसले पर मंगलवार को राज्य विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने दिनभर के लिए सदन स्थगित करने की घोषणा कर दी। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस का कहना है कि यदि राज्य सरकार इसी गति से काम करती रही तो किसानों के कर्ज माफ होने में 460 दिन लग जाएंगे।

मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही किसानों को पूर्ण कर्जमाफी दो, उनके खेत के कागज उन्हें सौंपो और महिलाओं को सुरक्षा दो जैसे नारे लगाते विपक्षी दल भाजपा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के सामने पहुंच गए। कामकाज शुरू करने में मुश्किल आती देख अध्यक्ष नाना पटोले ने 15-15 मिनट के लिए दो बार सदन स्थगित किया। उसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण पूरे दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया गया।

मुंबई में मंगलवार को विधान भवन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की अगुआई में भाजपा विधायकों ने महिलाओं को सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। एएनआइ

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शिवसेनानीत महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि मौसम की मार से पीड़ित किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये और फलोत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये देने का वादा किया गया था। यह वादा पूरा नहीं किया गया है।

फड़नवीस के अनुसार, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी किसानों को एक से डेढ़ लाख रुपये तक की मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक एक भी पैसा किसानों को नहीं मिला है। उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से कर्जमाफी, कर्जमुक्ति और चिंतामुक्त करने की घोषणा की गई थी। लेकिन अब तक कर्जमाफी के लिए सिर्फ 15,000 किसानों की सूची तैयार हो सकी है। यह राज्य सरकार की नीयत को बताता है।

इस गति से काम चला तो किसानों की कर्जमाफी में 460 दिन लग जाएंगे। तैयार सूची को भी अपूर्ण बताते हुए फड़नवीस ने विदर्भ के बुलढाणा जिले के एक गांव का उदाहरण भी दिया। जिसके अनुसार गांव में किसानों की संख्या 1,821 है, लेकिन सरकार द्वारा तैयार सूची में सिर्फ 193 किसान दर्शाए गए हैं। हंगामे का दौर विधान परिषद में भी जारी रहा। वहां नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने सरकार पर झूठे वादे कर किसानों का फंसाने का आरोप लगाया।

## झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का सहित आठ को सात साल की कैद

जासं, रांची : पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का सहित आठ के खिलाफ सीबीआइ की अदालत ने सात-सात साल की सजा मुकर्रर की है। सजा आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा बहाल होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी।

एनोस एक्का। फाइल

सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिन लोगों के खिलाफ सजा सुनाई है, उनमें एनोस एक्का के अलावा उनकी पत्नी मेनन एक्का तथा उनके भाई के अलावा रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज व इब्राहिम एक्का शामिल हैं। अदालत ने आरोपियों पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एनोस व उसके परिवार के खिलाफ आय से अधिक 16 करोड़ रुपये अर्जित करने का आरोप है।

गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआइ ने अगस्त 2010 में एनोस, उनकी पत्नी व अन्य के खिलाफ 10 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में दो चार्जशीट 27 जनवरी 2012 व 11 दिसंबर 2012 को दायर की गई थी।

# देश में पहली बार बिहार में पेश होगा ग्रीन बजट

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार एक बार फिर देश में नजीर बनेगा। इस बार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे देश को राह दिखाएगा। देश में पहली बार इस वर्ष बिहार विधानमंडल में ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। ग्रीन बजट में बिहार सरकार के सभी विभागों के पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का विवरण होगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल-जीवन-हरियाली ग्रीन बजट का महत्वपूर्ण अंश होगी। देश में पहली बार बिहार में ग्रीन बजट की पुस्तिका सदन में पेश की जाएगी।

जलवायु परिवर्तन से वर्षापात में हो रही कमी : विदित हो कि विगत वर्षो में जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में वर्षापात में कमी हुई है। इसके अलावा अत्यधिक भू-गर्भ जलदोहन के कारण दक्षिण बिहार के साथ-साथ आश्चर्यजनक रूप से उत्तर बिहार में भी भू-गर्भ जलस्तर में गिरावट हो रही है। जिसके कारण 13 जुलाई 2019 को विधान मंडल के सदस्यों की संयुक्त बैठक में आए सुझावों के आधार पर 24,524 करोड़ रुपये के व्यय से जल-जीवन-हरियाली अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह देश में इस तरह का पहला अभियान रहा। इसके तहत तालाब, पोखर, कुंओं एवं पारंपरिक जलस्रोतों आहर एवं पाइन को चिह्नित करके अतिक्रमण मुक्त किया गया। इसके बाद इनके जीर्णोद्धार के लिए कुंओं और चापाकलों के किनारे सोख्ता बनाने, जलसंग्रहण क्षेत्रों में चेकडैम, सघन पौधारोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा बचत, ड्रिप एरिगेशन आदि के लिए वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कुल 6,007.98 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान बजट में किया गया है।

**पहल**

- विधानमंडल के इसी सत्र में अलग से पेश होगा जल-हरियाली-जीवन हरियाली से जुड़ी योजनाओं का बजट
- पर्यावरण रक्षा को बिहार कर रहा नया प्रयोग, पूरे देश को दिखाएगा नई राह

### पारिस्थितिकी तंत्र पर होगा जोर

ग्रीन बजट की मदद से राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित एवं संरक्षित किया जाएगा। इसमें बिहार सरकार के सभी विभागों के वैसे योजनाओं को शामिल किया जाएगा जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों की रोकथाम में मदद मिले। इसमें राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण पर खर्च की जानेवाली राशि की जानकारी मिल सकेगी। इस बजट से राज्य के सतत विकास के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकेगा।

## 'बिहार में एनआरसी व एनपीआर पर पारित प्रस्ताव का स्वागत'

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के संस्थापक राम विलास पासवान ने बिहार विधानसभा में एनआरसी और एनपीआर को लेकर पारित प्रस्ताव का स्वागत किया है। विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के नए प्रारूप को खारिज कर दिया है।

पासवान ने कहा कि वह बिहार विधानसभा में आमसहमति से पारित उस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य में एनआरसी लागू नहीं होगा और एनपीआर को उसके 2010 के प्रारूप के आधार पर अपडेट किया जाएगा।

पासवान ने ट्वीट कर आगे कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि एनपीआर को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि देश भर में एनआरसी लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ भाजपा और लोजपा भी गठबंधन सरकार में शामिल है।

## मप्र में इमाम का वेतन पांच हजार व मोईज्जन का 4500 रुपये किया गया

नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इमाम (नमाज पढ़ाने वाले) और मोईज्जन (अजान देने वाले) के मानदेय में इजाफा करने की घोषणा की।

भोपाल में ताजुल मसाजिद के पास मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी के नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने इमाम का मानदेय 2200 से बढ़ाकर 5000 रुपये और मोईज्जन का मानदेय 1900 से बढ़ाकर 4500 रुपये करने की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तुरंत सहमति दे दी।

**सेना में धर्म शिक्षकों की भर्ती को लेकर याचिका दायर:** उधर, ग्वालियर हाई कोर्ट में उन उम्मीदवारों ने याचिका दायर की है, जिन्हें धर्म शिक्षक की लिखित परीक्षा से वंचित कर दिया था। गौरतलब है कि सेना में धर्म शिक्षकों की भर्ती होनी है। 23 जनवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा से 40 आवेदकों को यह कहते हुए वंचित कर दिया गया था कि शास्त्री की डिग्री को स्नातक की मान्यता नहीं है।

# सीएम आवास में किस हैसियत रह रहीं अरूसा आलम : भगवंत मान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रधान और सांसद भगवंत मान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को परेशानी में डाल दिया। मान ने मीडिया के जरिये कैप्टन से पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री आवास पर पाकिस्तानी नागरिक अरूसा आलम किस हैसियत से रह रही हैं? उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने की बात भी कही।

मान ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी के श्री करतारपुर साहिब संबंधी बयान पर उनका बचाव करते हुए आज सदन में कहा है कि पाकिस्तान पंजाब में आतंकी कार्रवाई को शह दे रहा है। कैप्टन साहब यह क्यों नहीं बताते कि उनके अपने घर में पाकिस्तानी नागरिक अरूसा किस हैसियत से रह रही हैं और उनके पास किस-किस शहर का वीजा है?

मान विधानसभा सत्र के दौरान गवर्नर गैलरी में बैठकर सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे थे। बाहर आने पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री

**लोकसभा में भी उठाऊंगा पाक नागरिक अरूसा के वीजा का मामला**

भगवंत मान। फाइल

आरोपों में घिरे मंत्री भारत भूषण आशु और डीजीपी दिनकर गुप्ता को बचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम (आम आदमी पार्टी) चुप नहीं बैठेंगे।

मान से जब पूछा गया कि वीजा देना भारत सरकार का काम है। आप संसद सदस्य हैं। क्या आपने लोकसभा में यह मामला उठाया? इस पर उन्होंने कहा कि हम अरूसा आलम के मामले में लंबे समय से चुप थे कि यह एक निजी मामला है, लेकिन अब चुप नहीं रह सकते। मैं लोकसभा में भी यह मामला उठाऊंगा और विदेश मंत्रालय से उनके वीजा के संबंध में भी पूछूंगा। यह भी कहा कि अरूसा के बारे में तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि वह पाकिस्तानी एजेंसी आइएसआइ की एजेंट हैं। ऐसे में यह और भी जरूरी हो जाता है।

**कैप्टन अमरिंदर डीजीपी को बचाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे**

### आप की सरकार में खोलेंगे आशु का केस

कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू का केस फिर से न खोलने के सीएम के बयान पर मान ने कहा कि यदि कैप्टन ने कोई कार्रवाई न की तो आशु के खिलाफ बंद पड़े केसों को 2022 में आप की सरकार बनने पर खोला जाएगा। उल्लेखनीय है कि एक निलंबित डीएसपी ने आशु पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया है।

# डीजीपी के बचाव में उतरे कैप्टन अमरिंदर

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह डीजीपी दिनकर गुप्ता के बचाव में उतर आए हैं। डीजीपी द्वारा करतारपुर कॉरिडोर से संबंधित बयान पर कैप्टन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इसे सुधारा जा सकता था। डीजीपी को बर्खास्त किए जाने की मांग पर अड़े विपक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान पर पूरी तरह संतुष्टि तो नहीं जताई, लेकिन सदन की कार्यवाही को चलने दिया। उल्लेखनीय है कि डीजीपी ने कहा था कि कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान जाने वाला व्यक्ति शाम तक आतंकवादी बनकर लौट सकता है।

कैप्टन ने कहा कि हमें यह भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ का एक सूत्रीय कार्यक्रम अपने पड़ोसी देशों की शांति को भंग करना भी है। जम्मू-कश्मीर के बाद अब वह पंजाब में भी इसी तरह की कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम पंजाब की शांति भंग नहीं होने देंगे। बहुत से ऐसे गुप्त दस्तावेज हैं जो मैं सदन में नहीं रख सकता, लेकिन उनकी एक झलक जरूर दिखा सकता हूं। उन्होंने बताया कि हमने आतंकियों के 32 मॉड्यूल भंग किए हैं और 154 आतंकियों को पकड़ा है। इनसे 156 पिस्टल, एके-47 राइफल, साढ़े तीन किलो आरडीएक्स, पांच सेटेलाइट फोन सेट और चार वॉकी टॉकी पकड़े हैं। इसके अलावा 30 लाख रुपये की नकली करंसी भी पकड़ी है। हाल ही में जब रावी नदी में बाढ़ आई तो पाकिस्तान से एक व्यक्ति बैग में छह एके-47 राइफल लेकर तैरकर इस पार आ गया जिसे हमने धर लिया।

कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल फोटो

**चीन में बने ड्रोन की फोटो दिखाई :** मुख्यमंत्री ने सदन में चीन द्वारा बनाए गए ड्रोन की फोटो दिखाते हुए कहा कि इसकी क्षमता भारी सामान उठाने की है। ये तो वो सामान है जो हमने पकड़ लिया है। हो सकता है कि बहुत सा ऐसा सामान हो जो हम न पकड़ पाए हों। आखिर वह सामान पंजाब में किन लोगों के पास है?

### मुख्यमंत्री बोले-करतारपुर कॉरिडोर बंद नहीं होने देंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर के खुलने को लेकर हमने प्रयास किए हैं और खुले दर्शन की अरदास पूरी हुई है। इसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दिया जाएगा। हम यह भी चाहते हैं कि करतारपुर साहिब की तरह ननकाना साहिब और पंजाब साहिब के भी खुले दर्शन हों।

### खालिस्तानी जाते हैं करतारपुर साहिब

कैप्टन ने कहा कि कई खालिस्तानी गर्मख्याली पंजाब में भी हैं और विदेश में भी बैठे हैं जो सीधे करतारपुर साहिब जाते हैं। असली खतरा उनसे है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए पाकिस्तान से सचेत रहने की जरूरत है।

### पाकिस्तान में चल रहे दर्जनों आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप

लोक इंसाफ पार्टी के विधायक बलविंदर सिंह बैंस द्वारा उठाए मुद्दे पर कैप्टन ने कहा कि गुलाम कश्मीर और पाक पंजाब में दर्जनों आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं।

# आजम सहित पत्नी और बेटे के खिलाफ कुर्की के आदेश

जागरण संवाददाता, रामपुर

दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अदालत ने कुर्की के आदेश जारी किए हैं। साथ ही एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए हैं।

आजम खां के बेटे अब्दुल्ला पर दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप है। मामले में सांसद आजम, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा, बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तीनों ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को अदालत ने तीनों की अर्जियां खारिज कर दी थीं। मंगलवार को अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि आरोपित कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिस पर कुर्की के आदेश जारी कर

आजम खां। फाइल

दिए हैं। साथ ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। अदालत अब इस मामले में 17 मार्च को सुनवाई करेगी।

दूसरी ओर, हमसफर रिसॉर्ट में सरकारी जमीन मिलाने के मामले में सांसद आजम की पत्नी और दोनों बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी उनके अधिवक्ता ने वापस ले ली है। मुकदमे में तीनों की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी।

## मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की सीबीआइ जांच होगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बागपत जिला जेल में शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने 20 अप्रैल को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। उसे एक मामले में पेशी के लिए झांसी से बागपत जिला जेल लाया गया था। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने यह आदेश मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने झांसी से बागपत तबादले और उसी दिन जेल में पिस्तौल आने के पीछे की साजिश में अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही बैलिस्टिक जांच के जरिये हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल की भी पुष्टि करने को कहा है।

माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने हत्या की साजिश की सीबीआइ जांच की मांग की थी। उनका आरोप था कि हत्या के लिए ही मुन्ना बजरंगी को एक से दूसरी जेल लाया गया था। इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए।

# फिर उठी पासपोर्ट की शर्त व फीस खत्म करने की मांग

**करतारपुर साहिब**

- पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव
- कैप्टन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा में मंगलवार को एक बार फिर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा लगाई गई पासपोर्ट की शर्त और 20 डालर फीस को माफ करने का मुद्दा उठा। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने सदन में प्रस्ताव पेश किया जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।

प्रस्ताव पर यह सहमति बनी कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने और पासपोर्ट की शर्त खत्म करने की मांग करेगा। प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री को भारतीय श्रद्धालुओं पर लगने वाली 20 डॉलर फीस घटाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की भी अपील करेगा।

विधायक गुरप्रताप सिंह वडाला ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को ये मसले केंद्र सरकार के पास उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के साथ इस मसले को उठाएं। इससे श्रद्धालुओं के हित में इसके जल्द हल होने की भूमिका तैयार होगी। प्रस्ताव में रंधावा ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को अपनी पहचान दिखाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है और 20 डॉलर फीस भी देनी पड़ती है। हमारे बहुत से ऐसे निवासी हैं, जिनके पास पासपोर्ट ही नहीं है, जिस कारण वह चाहते हुए भी दर्शनों से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल प्रक्रिया रखी गई है जो कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी रुकावट है।

## कुलदीप सेंगर की विस सदस्यता खत्म

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: उप्र के उन्नाव दुष्कर्म कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा से सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी अधिसूचना में सेंगर की सदस्यता उस दिन से ही समाप्त की गई है, जिस दिन उसे सजा सुनाई गई थी। इसके मुताबिक, 20 दिसंबर 2019 से उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया है। सेंगर को एक अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने भी निष्कासित कर दिया था। चार जून 2017 को दुष्कर्म पीड़िता ने सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सेंगर को धारा 120 बी, 363, 366 व 376 में दोषी ठहराया गया था।

**बांगरमऊ में होगा उपचुनाव:** कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद इस सीट पर जल्द ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि इस सीट पर सेंगर की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि भाजपा की ओर से इस बारे में अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं।

**असमंजस**

चुनाव लड़े या इसके समय को लेकर अदालत का रुख करे, इसे लेकर पसोपेश में है पार्टी, 29 फरवरी को होने वाली बैठक में अमित शाह ही करेंगे इस मसले का समाधान

# बंगाल में निकाय चुनाव पर उलझी भाजपा, जोह रही शाह की बाट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उलझन में पड़ी भाजपा एक बार फिर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भरोसे है। शाह भले अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष न हों, लेकिन पार्टी की चुनावी रणनीति की धुरी में अभी भी वे ही हैं। शाह 29 फरवरी की शाम को कोलकाता पहुंचेंगे और एक मार्च को शहीद मीनार मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी जनसभा से वे पार्टी कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कह सकते हैं। शाह कोलकाता पहुंचते ही बंगाल भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इसी बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी।

दरअसल इस समय प्रदेश के पार्टी नेता दो विकल्पों को लेकर उलझे हुए हैं। पहला, भाजपा सीधे चुनावी मैदान में उतरे और दूसरा, पार्टी अदालत जाकर इसके समय का विरोध करे। एक वर्ग चाहता है कि पार्टी पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बंगाल में मिली जबर्दस्त सफलता के मद्देनजर सीधे चुनाव में उतरे जबकि दूसरे वर्ग का तर्क है कि अगर अप्रैल के मध्य में निकाय चुनाव होंगे तो पार्टी को प्रचार के लिए समय नहीं मिलेगा। ऐसे में चुनाव के समय के विरोध में अदालत का रुख करना ही सही होगा। इसे लेकर बंगाल भाजपा के नेता दो वर्गों में बंट गए हैं। स्थिति कुछ ऐसी जगह आकर ठहर गई है कि अब इसका समाधान शाह के निर्णय पर निर्भर हो गया है।

इस बीच भाजपा नेता मुकुल राय ने राज्य चुनाव आयुक्त सौरव कुमार दास से मुलाकात कर उन्हें अदालत के दो निर्देश की प्रतियां सौंपी हैं। एक निर्देश में कहा गया है कि बोर्ड की परीक्षाएं चलने तक किसी तरह का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। दूसरा निर्देश यह है कि चुनाव कराने के लिए आयोग को चुनाव के दिन तक न्यूनतम 22 दिनों का समय देना पड़ेगा। अगर निकाय चुनाव 22 अप्रैल को होते हैं तो अदालत के इन दोनों निर्देशों की अवमानना हो सकती है। कारण, बंगाल में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, आइसीएससी व आइएससी की परीक्षाएं 30 मार्च को खत्म होंगी। चुनावी रण में उतरने के पक्षधर वर्ग का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा।

### अमित शाह की सभा के लिए मिल गई पुलिस से अनुमति

**कोलकाता:** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक मार्च को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में प्रस्तावित सभा की अनुमति को लेकर जारी गतिरोध मंगलवार को खत्म हो गया। आखिरकार कोलकाता पुलिस ने इसकी अनुमति दे दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी ने 20 फरवरी को कोलकाता पुलिस को पत्र सौंपकर सभा की अनुमति मांगी थी। कुछ देरी हुई लेकिन हमें अनुमति मिल गई। अब शेड्यूल के अनुसार सभा की तैयारी आगे बढ़ाई जा रही है।

अमित शाह। फाइल

यह एक मेगा इवेंट होगा। इस सभा में शाह का सीएए लागू करने के लिए अभिनंदन किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री का पदभार संभालने के बाद शाह की बंगाल की यह दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने पिछले वर्ष एक अक्टूबर को नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक सेमिनार को संबोधित किया था। पिछले हफ्ते बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कोलकाता पुलिस और जिला प्रशासन पर बिना किसी ठोस कारण के शाह की सभा की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया था।

# हाई कोर्ट ने देवस्थानम एक्ट पर सरकार से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दी है सरकार के फैसले को चुनौती

उत्तराखंड में देवस्थानम ऐक्ट पर नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के एक्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मंगलवार को स्वामी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि चारधाम व 52 अन्य मंदिरों के लिए राज्य सरकार के स्तर से बनाया गया देवस्थानम अधिनियम असंवैधानिक है। सरकार के फैसले से पुजारियों में रोष है। याची ने यह भी कहा कि पूर्व में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल ने भी इस तरह के निर्णय लिए थे, जिनके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, इनमें उन्हें जीत मिली थी। उन्होंने याचिका में यह भी अनुरोध किया है कि जब तक इस मामले में कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता, सरकार कोई अग्रिम कार्यवाही न करे। याची ने तर्क दिया कि जनहित याचिका दायर करने के चंद घंटे पहले गढ़वाल कमिश्नर को देवस्थानम बोर्ड का सीईओ नियुक्त कर कर दिया, इससे साफ है कि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है।

सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध करते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने याचिका को राजनीति और प्रचार पाने का तरीका बताया। साथ ही तर्क दिया कि अधिनियम पूरी तरह संवैधानिक है। उन्होंने याचिका को रद करने की मांग की।

15 मार्च से इंडिगो पुणे और चंडीगढ़ के बीच उड़ान शुरू करने जा रही है। इसके अलावा पुणे और इंदौर के बीच एक मई से दैनिक उड़ान शुरू की जाएगी। इंडिगो के मुताबिक, इन दोनों रूट पर बुकिंग शुरू हो चुकी है।



# बालाकोट एयरस्ट्राइक का दम, दुश्मन के हौसले हुए बेदम

नवीन नवाज, श्रीनगर

बालाकोट एयरस्ट्राइक...। केवल नाम लेते ही भारतीय सैनिकों की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। बालाकोट एयरस्ट्राइक को आज (26 फरवरी) एक साल पूरा हो गया है। इस एयरस्ट्राइक ने भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य परिदृश्य और परिभाषा को ही पूरी तरह बदलकर रख दिया है। बालाकोट ने पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, भारतीय नेतृत्व में राजनीतिक इच्छाशक्ति और दृढ़संकल्प का भी कतई अभाव नहीं। भारत दुश्मन के किसी भी दुस्साह का उसके घर में घुसकर जवाब देना जानता है। इसी असर यह हुआ कि आज पाकिस्तान कश्मीर पर दावा नहीं करता, बल्कि गुलाम कश्मीर को कैसे बचाना है, यह सोच रहा है।

**भारत ने क्यों बदली रणनीति :** पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर ने भारत की जमीन पर कई बड़े हमले किए। संसद हमला, मुंबई हमला, पठानकोट एयरबेस हमला, उड़ी हमला, लेकिन भारत हमेशा पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाता था। उड़ी हमले के बाद पहली बार भारतीय सेना ने एलओसी पार कर आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। इसके बाद जब पुलवामा हमले में 40 सैनिकों की जान गई तो पहली बार वायुसेना का इस्तेमाल किया गया और वह भी पाकिस्तान के भीतर। इस हमले में गुलाम कश्मीर में स्थित कई आतंकी कैंपों को तबाह किया गया। हालांकि, कारगिल युद्ध के दौरान भी भारतीय वायुसेना ने जीत में उल्लेखनीय भूमिका निभायी, लेकिन उसने एलओसी को पार नहीं किया था। वर्ष 1971 के बाद यह पहला मौका था जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मन देश में घुसकर कार्रवाई की। यह एक तरह से जंग का एलान करने जैसा था। इस हमले ने पाकिस्तान व उसके समर्थकों को साफ संदेश दिया कि अगर जिहादी आतंकियों के कैंप बंद नहीं किए गए तो भारत लाहौर के पास मुरीदके में स्थित लश्कर के मुख्यालय और बहावलपुर में जैश के किले को तबाह करने के लिए भी तैयार है।

### एक साल बाद

- बालाकोट ने भारत-पाकिस्तान के बीच पूरी तरह बदलकर रख दी सैन्य परिभाषा
- भारत ने दिया था संदेश, अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी बड़ी कार्रवाई करने को तैयार
- अब कश्मीर पर दावा नहीं, गुलाम कश्मीर बचाने की सोच रहा पाकिस्तान

### क्या कहते हैं विशेषज्ञ

**पाक नहीं चाहता, दोबारा बालाकोट जैसा हमला**

कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार शब्बीर ने कहा कि बालाकोट एक वॉटरशेड है। इस हमले ने पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब किया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने कोई बड़ा हमला नहीं किया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की गिरफ्तारी के बाद रिहाई भारत की एक और जीत थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अगर आप बयान देखो तो पता चलेगा कि वह कितनी बार बालाकोट जैसे हमलों से पाकिस्तान को बचाने का प्रयास कर चुके हैं।

**आतंकी जानते हैं अब कश्मीर आएंगे तो मारे जाएंगे : ढिल्लो**

श्रीनगर स्थित चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी हर शरारत और दुस्साहस पर सबक सिखाया जाता है। आज यहां आतंकी संगठनों को अपने लिए कमांडर नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान में वह जिन कमांडरों को कश्मीर के लिए तैयार करता है, उनमें से ज्यादातर कश्मीर आने को तैयार नहीं हैं, उन्हें पता है कि वह कश्मीर में मारे जाएंगे।

**आज भी महसूस होता है असर**

कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ प्रो. हरि ओम ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक बहुत अहम थी। बालाकोट हमला करीब 12 दिन बाद किया गया, मतलब यही कि पहले पूरी तरह तैयारी की गई। इसके राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले असर, भारत-पाक के बीच एक पूर्णकालिक युद्ध जैसी आशंकाओं का आकलन किया गया होगा। ऐसा फैसला लेने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और संकल्प चाहिए।

**आज भारत की आतंकवाद के प्रति स्पष्ट नीति**

रक्षा मामलों के विशेषज्ञ डॉ. अजय ने कोर कमांडर केजेएस ढिल्लो के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यह बालाकोट और देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का प्रभाव है। आज भारत की आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रति एक स्पष्ट नीति है। आज कोई आतंकी संगठन खुलकर कोई बड़ा हमला करता नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि 2016 में उड़ी हमला हुआ था। उसके बाद भारत ने गुलाम कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की, जिससे सबक लेते हुए पाक ने करीब तीन साल तक कश्मीर में कोई बड़ा हमला नहीं किया।

## रुबिया सईद अपहरण कांड में सुनवाई शुरू

जेएनएन, जम्मू : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण और एयरफोर्स के पांच अधिकारियों की हत्या मामले में आरोप तय या खारिज करने पर मंगलवार को टाडा कोर्ट जम्मू में बहस शुरू हुई। इस मामले में मुख्य आरोपित यासीन मलिक को सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। दूसरे आरोपित शौकत बख्शी को भी उत्तर प्रदेश की जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया। टाडा कोर्ट जम्मू ने तीस साल पुराने इस केस में आरोप तय या खारिज करने पर बहस शुरू करवाई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। अब कोर्ट ने बहस के लिए अगली तारीख दो मार्च निर्धारित करते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर संभव हो तो यासीन मलिक व शौकत बख्शी को अगली सुनवाई पर जम्मू में पेश किया जाए।

# पाक ने नहीं लिया सबक, बालाकोट में फिर शुरू हुई आतंकी ट्रेनिंग

**हरकतें जारी** ▶ एक दर्जन कश्मीरी मूल के आतंकियों सहित 35 को दी जा रही ट्रेनिंग

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

बालाकोट हमले के बाद खामोश रहे जैश-ए-मोहम्मद ने एक बार फिर अपनी जिहादी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में तबाह हुआ उसका बालाकोट ट्रेनिंग कैंप फिर से सक्रिय हो चुका है। सूत्रों के अनुसार, छह एकड़ में फैले इस कैंप में 35 नए जिहादियों की आतंकी ट्रेनिंग चल रही है। इनमें एक दर्जन के करीब कश्मीरी मूल के आतंकी हैं। इंडियन एयरलाइंस के अपहृत विमान को छुड़ाने के लिए अजहर मसूद संग रिहा किया गया आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लटरम भी कथित तौर पर बीते तीन माह के दौरान इस शिविर में तीन से चार बार देखा गया है।

14 फरवरी 2019 को जैश के आतंकी आदिल डार ने जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर लिथपोरा (पुलवामा) में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हुए थे। हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश के एक प्रमुख जिहादी कैंप को निशाना बनाया। दावा किया जाता है कि वायुसेना की कार्रवाई के समय कैंप में

पिछले वर्ष पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को गुलाम कश्मीर में घुसकर आतंकी कैंपों पर हमला किया था। बुधवार को एयरस्ट्राइ का एक साल पूरा हो जाएगा। भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए मुस्तैद है। मंगलवार को श्रीनगर के लाल चौक में तैनाम सुरक्षाकर्मी। जागरण

मौजूद 300 के करीब आतंकी और उनके सरगना मारे गए थे। बहावलपुर स्थित मुख्यालय के बाद पाकिस्तान में जैश का सबसे बड़ा आतंकी कैंप बालाकोट में ही है। इसमें आतंकी ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था है। इनकी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान के तीन पुराने जिहादी कमांडरों के अलावा पाकिस्तानी सेना के दो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इस कैंप में एक बड़ा मदरसा भी है।

**कैंप में एक बार दिखा मसूद अजहर :** सूत्रों ने बताया कि मसूद अजहर दिसंबर माह के दौरान ही एक बार इस ट्रेनिंग कैंप में देखा गया है। उसका करीबी समझा जाने वाला अल उमर मुजाहिदीन का चीफ कमांडर मुश्ताक लटरम तीन-चार बार बालाकोट शिविर में गया है। मसूद अजहर का बेटा अपने चाचा राउफ असगर के साथ कई बार बालाकोट में देखा गया है। मुश्ताक लटरम श्रीनगर में डाउन-टाउन का रहने वाला है। बालाकोट में ट्रेनिंग ले रहे कश्मीरी आतंकियों को उसने ही वहां पहुंचाया है।

**पाकिस्तानी सेना के सेफ हाउस में है बीमार अजहर :** सूत्रों ने बताया कि मसूद अजहर किडनी और रीढ़ की हड्डी के रोग से पीड़ित है। उसे पाकिस्तानी सेना ने बहावलपुर से कुछ ही दूरी पर अपने एक सेफ हाउस में रखा है। वह नए लड़कों में जिहादी मानसिकता पैदा करने के लिए नियमित तौर पर वीडियो कांफ्रेंस करता है। मसूद अजहर के बीमार होने के चलते आतंकी गतिविधियों का जिम्मा राउफ असगर ने संभाल रखा है। असगर के दो बेटे तल्हा रशीद और उस्मान हैदर कश्मीर में सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए हैं।

**जैश की चाबी मसूद के कुनबे के पास :** मसूद अजहर का पूरा कुनबा ही जिहादी है। उसका छोटा भाई मोहम्मर तारिक अनवर आतंकियों की भर्ती का जिम्मा संभालता है। उसका एक भाई इब्राहिम अजहर अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा के साथ मिलकर जैश की गतिविधियों को संचालित करता है। उसका सबसे छोटा भाई मोहम्मद जहांगीर अकबर तल्हा जैश के नए लड़कों को संभालता है। मसूद अजहर का एक करीबी रिश्तेदार बालाकोट में जब्बा टाप कैंप का प्रभारी है।

## कश्मीर में तीन दिन में बहाल हो सकती है ब्रॉडबैंड सेवा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर घाटी में बंद ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को अगले 72 घंटों में बहाल करने की तैयारी है। बीएसएनएल ने प्रतिबंधित साइटों और वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक को सुनिश्चित बनाने के लिए फायरवॉल का अंतिम ट्रायल शुरू कर दिया है।

गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में 5 अगस्त 2019 को प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी थी। जनवरी माह में आम उपभोक्ताओं के लिए सिर्फ मोबाइल पर 2जी इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया है। फिलहाल ब्रॉडबैंड सेवा सिर्फ सरकारी कार्यालयों में और सुरक्षा एजेंसियों के क्लीयरेंस के बाद कुछ अन्य सस्थानों को उपलब्ध कराई गई है।

आइजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा था कि अगर बीएसएनएल समेत इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां वीपीएन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने में समर्थ फायरवॉल और सॉफ्टवेयर विकसित कर लेती हैं तो हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को बहाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस का मकसद सिर्फ इंटरनेट के दुरुपयोग को रोक कश्मीर में शांति व सुरक्षा का माहौल बनाए रखना है।

बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अत्याधुनिक फायरवॉल का ट्रायल चल रहा है ताकि प्रतिबंधित इंटरनेट साइटों को पूरी तरह ब्लॉक किया जा सके। ट्रायल पूरा होते ही आम उपभोक्ताओं के लिए ब्राडबैंड सेवा शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद करनी चाहिए कि अगले तीन दिन में यहां ब्रॉडबैंड सेवा बहाल हो जाएगी।

## 'अपनी पार्टी' हो सकता है नए सियासी संगठन का नाम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नए सियासी संगठन के गठन को लेकर जल्द स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर मार्च के पहले सप्ताह इस संगठन का एलान हो जाएगा। फिलहाल, इसके गठन में जुटे नेताओं में इसके नाम को लेकर मंथन चल रहा है। संभावित नाम 'अपनी पार्टी' हो सकता है। संगठन के संविधान को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बता दें कि उभर रहे नए सियासी संगठन को तैयार करने में पूर्व वित्तमंत्री सईद अल्ताफ बुखारी गत अक्टूबर से सक्रिय हैं। पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस समेत अन्य कई दलों के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता नए सियासी संगठन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अल्ताफ बुखारी को बीते साल पीडीपी से निष्कासित किया गया था।

अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम जिस सियासी संगठन को सामने ला रहे हैं, वह पूरी तरह से जम्मू-कश्मीर के लोगों के हितों के लिए होगा। यह लोगों के मुद्दों को हल करने का प्रयास करेगा। फिलहाल हम इसका संविधान तैयार कर रहे हैं। उसके प्रारूप को लगभग तैयार कर लिया गया है। इस पर विचार विमर्श के लिए जल्द ही सभी वरिष्ठ साथियों की एक बैठक होगी। संगठन के नाम का जिक्र किए जाने पर उन्होंने कहा कि नाम को तय किया जाना है, यह लोगों की अपनी पार्टी होगी।

**क्या होंगे पार्टी की मुख्य मांगे :** बताया जा रहा है कि सियासी संगठन में शामिल होने जा रहे सभी नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, डोमिसाइल के प्रावधान, रोजगार और विकास को ही अपना एजेंडा बनाने का संकेत दिया है।

### राजनीतिक हलचल

- संगठन के संविधान के प्रारूप को दिया जा रहा अंतिम रूप
- मार्च के पहले सप्ताह हो सकता है एलान, बैठक जल्द

**बेग की हां का इंतजार :** इसके अलावा नए सियासी संगठन में पूर्व उपमुख्यमंत्री और पीडीपी के संरक्षक मुजफ्फर हुसैन बेग को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके हां-ना पर ही नए सियासी संगठन में उनकी भूमिका तय होगी।

**रंग ला रहा है अल्ताफ का प्रयास :** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के बाद नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीपुल्स कांफ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी सरीखे दलों की राजनीतिक गतिविधियां लगभग थम चुकी हैं।

पीडीपी के अधिकांश नेताओं ने संगठन छोड़ दिया है या फिर उन्हें संगठन से निकाला जा चुका है। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के कई नेता भी अपने नेतृत्व की कश्मीर नीतियों से तंग आकर संगठन से किनारा कर अपने लिए नए अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे में अल्ताफ बुखारी ने एक नया सियासी संगठन बनाने की कवायद शुरू की थी। उनका यह प्रयास अब रंग लाता नजर आ रहा है।

## ककड़याल आतंकी हमले में दो पर तय किए गए आरोप

जेएनएन, जम्मू

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू संभाग के ककड़याल में 13 सितंबर 2018 को हुए आतंकी हमले में एनआइए की जम्मू की विशेष अदालत ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दो मददगारों मोहम्मद इकबाल राथर व रियाज अहमद के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ धारा 307, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, फॉरेनर एक्ट व इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं।

एनआइए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि दोनों आरोपित जैश से जुड़े थे और सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में अपने सरगनाओं से लगातार संपर्क में थे। 12 सितंबर 2018 की सुबह करीब साढ़े चार बजे उन्होंने पाकिस्तान से आए तीन प्रशिक्षित आतंकवादियों को रिसीव किया जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। इन आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में गोला-बारूद था। दोनों आरोपितों ने इन तीनों आतंकवादियों को एक ट्रक में बिठाया, जिसमें पहले से ही वॉल पुट्टी के 900 बैग लदे थे। ये लोग जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ निकले। आतंकवादियों की पहचान छिपाने के लिए आरोपितों ने उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त भी किया था। मोहम्मद इकबाल स्वयं ट्रक चला रहा था। बन टोल प्लाजा के निकट पहुंचने पर वह आल्टो कार में आ गया और ट्रक रियाज चलाने लगा। मोहम्मद इकबाल स्वयं भी कार में ट्रक के साथ चल रहा था, ताकि आतंकवादियों को सुरक्षित श्रीनगर तक पहुंचाया जा सके। एनआइए की चार्जशीट के मुताबिक झज्जर कोटली पुल के निकट साईं कैफेटेरिया के पास पुलिस ने ट्रक को जांच के लिए रोका तो उसमें छिपे आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेरीकल्चर विभाग का एक गार्ड जख्मी हो गया। फायरिंग करते हुए आतंकवादी ककड़याल के जंगलों में भाग गए। अगले दिन सुरक्षाबलों ने तीनों आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ था। सुरक्षाबलों ने इसी दौरान दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

## सरपंच के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू से करीब 25 किलोमीटर दूर घरोटा के पास पड़ने वाली बरन पंचायत (पाट्टा खू) में मंगलवार को पौ फटते ही करीब पांच-छह हथियारबंद लोगों ने सरपंच दिलबाग सिंह के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से कमरे में सो रहे सरपंच के मौसेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरपंच घायल हो गए। भागते-भागते हमलावरों ने सरपंच की बहन को भी गोली मार दी। वह भी गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज जीएमसी में चल रहा है और सरपंच को दूसरे राज्य के निजी अस्पताल ले जाया गया। गोलीबारी में सरपंच के पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई। घायल सरपंच के बहन ने कहा कि चंचल बाबा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हमला किया है। पुलिस ने तत्काल आधा दर्जन से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक राजौरी जिले के लंबेड़ी के रहने वाले अधेड़ कश्मीर सिंह अपने मौसेरे भाई सरपंच दिलबाग सिंह के घर बरन पंचायत के पाट्टा खू गांव आया हुआ था। सरपंच के घर में इनवर्टर से मात्र एक बल्ब जल रहा था। तभी पांच से छह हथियारबंद लोग सरपंच के घर में घुस आए।

## पाक ने अब ऐतिहासिक साईं मीरा बख्श दरगाह पर दागे गोले, दो घायल

संवाद सहयोगी, पुंछ

- एलओसी के करीब स्थित दरगाह को पहुंचा नुकसान
- हर धर्म के लोग आते हैं माथा टेकने, बीस दिन पहले शाहपुर में भी पाक ने मस्जिद को बनाया था निशाना

पाकिस्तानी सेना ने दिखा दिया कि उसे आम नागरिकों व धार्मिक स्थलों से कोई सरोकार नहीं और वह अपनी बौखलाहट निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को पुंछ के गुंत्रियां इलाके में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब स्थित ऐतिहासिक साईं मीरा बख्श दरगाह पर भारी मोर्टार दागे। इससे दरगाह को नुकसान पहुंचा और दो लोग भी घायल हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया।

करीब बीस दिन पहले भी पाकिस्तानी सेना ने शाहपुर में मस्जिद को निशाना बनाकर मोर्टार दागे थे, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई थी। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने से स्थानीय लोगों में पाकिस्तान के प्रति काफी रोष है। गुंत्रियां इलाके में स्थित जिस एतिहासिक साईं मीरा बख्श दरगाह को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, वहां कभी सीमा पार से भी लोग माथा टेकने आते थे। इस दरगाह में हर धर्म

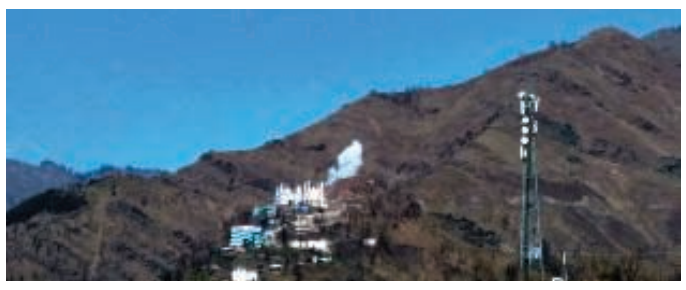

पुंछ के गुंत्रियां इलाके में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब स्थित ऐतिहासिक साईं मीरा बख्श दरगाह पर पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार के बाद उठता धुआं। जागरण

के लोग सजदा करने आते हैं। पाकिस्तानी सेना ने दोपहर करीब एक बजे पहले पुंछ के शाहपुर सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी। इसमें एक युवक करामत हुसैन पुत्र नजीर हुसैन निवासी शाहपुर भी घायल हो गया। भारतीय सेना ने जब जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान सेना ने गुंत्रियां इलाके में स्थिति ऐतिहासिक साईं मीरा बख्श दरगाह को निशाना बना कर मोर्टार दागने शुरू कर दिए। एक मोर्टार दरगाह की छत पर पड़ा, जिससे छज्जे को नुकसान पहुंचा और वहां पर सजदा करने आया मुश्ताक अहमद निवासी सुरनकोट घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। जिला आयुक्त राहुल यादव ने अस्पताल पहुंचकर घायलों को रेड क्रास फंड से आर्थिक सहायता दी।

## आतंकी सरगनाओं से संपर्क बना रहे युवक को पकड़ा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : पाकिस्तान में आतंकी सरगनाओं से संपर्क बनाने के लिए वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे गांदरबल के युवक को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

पकड़ा गया युवक कट्टर जिहादी मानसिकता का शिकार है। वह आइएस जैसे खूंखार आतंकी संगठन की विचारधारा से प्रभावित है। फिलहाल, उससे पूछताछ जारी है। एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल ने पकड़े गए युवक की पहचान को गुप्त रखते हुए उसके खिलाफ खीरभवानी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वह कई दिनों से वीपीएन के जरिये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था। सूत्रों से इसकी गतिविधियों की सूचना मिलने पर निगरानी शुरू की गई। छानबीन के दौरान पता चला कि यह युवक पाकिस्तान में बैठे विभिन्न जिहादी कमांडरों से संपर्क में है। उसके फेसबुक की निगरानी की गई तो पता चला कि वह जल्द ही जिहादी संगठन का हिस्सा बनने वाला है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान पता चला कि पकड़ा गया युवक सोशल मीडिया पर लगातार आपत्तिजनक तस्वीरें और सामग्री अपलोड कर रहा था। वह वाट्सएप पर ऐसे कई समूहों का हिस्सा था, जो वादी के हालात पर अफवाहें फैलाने, युवाओं को धर्मांध जिहादी बनाने, हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा करने में सक्रिय हैं। वह 15 अलग-अलग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान स्थित उसके हैंडलर ने शोपियां में एक आतंकी गुट के साथ उसका संपर्क कराया था। वह जल्द ही जिहादी संगठन का सक्रिय सदस्य बनने वाला था।

एसएसपी ने बताया कि समय रहते यह युवक पकड़ा गया जिससे उसकी जान बच गई। वह बेसहारा है और गरीब परिवार से संबंध रखता है। उन्होंने कहा कि इस युवक से मिले सुरागों के आधार पर हमने गांदरबल, शोपियां में सक्रिय आतंकियों व उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़े गए युवक की काउंसलिंग भी की जा रही है।

### हालात

अगस्त से खाली हैं एएफटी लखनऊ बेंच की तीनों कोर्ट, जवानों, सैन्य अफसरों, जेसीओ व पूर्व सैनिकों को मिल रही सिर्फ तारीख

## मुकदमों की जंग में हार रहे सैनिक

जागरण संवाददाता, लखनऊ

करीब 75 साल के पूर्व सैनिक ध्रुवजीत सिंह गाजीपुर जिले से हर महीने इस उम्मीद से सशस्त्र बल अधिकरण लखनऊ आते हैं कि शायद उनको न्याय मिल सकेगा। अधिकरण पहुंचने पर उनको सिर्फ तारीख मिल रही है। मंगलवार को जब वह अधिकरण पहुंचे तो वह ठीक से चलने की स्थिति में भी नहीं थे।

ध्रुवजीत सिंह की तरह उप्र, उत्तराखंड और झारखंड के करीब तीन हजार फरियादियों को पिछले सात महीने से सिर्फ तारीख ही मिल रही है। यहां तीनों बेंच खाली पड़ी हैं। उनके न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों की तैनाती जनवरी में होने की उम्मीद थी। लेकिन, इस प्रक्रिया की तारीख भी बढ़ गई है। दरअसल, सेना के तीनों विंग के जवानों, जेसीओ, अफसरों के साथ पूर्व सैनिकों के बड़ी संख्या में मामले हाई कोर्ट में लंबित थे। इसे देखते हुए अलग से एक अधिकरण बनाया गया। लखनऊ में मध्य कमान के अंतर्गत रीजनल बेंच सात नवंबर 2009 को स्थापित की गई। हाई कोर्ट से मामले अधिकरण को ट्रांसफर हुए जिन पर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी आए। परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद के परिवार की पेंशन दुरुस्त करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय एएफटी ने दिए थे। कभी पांच हजार मामले एएफटी में लंबित थे जो अब तीन हजार हो गए हैं। अधिकरण में सामान्य व दिव्यांगता पेंशन, सर्विस, कोर्ट मार्शल, डिस्चार्ज, प्रमोशन, वेतन, सेवा बर्खास्तगी और एसीआर कैटेगरी के तीन हजार मामलों पर अगस्त से एक भी सुनवाई नहीं हुई है। इन मामलों में सिर्फ तारीख मिल रही है।

**सिर्फ रजिस्ट्रार कोर्ट :** अधिकरण में केवल रजिस्ट्रार कोर्ट ही काम कर रहा है जहां अपील से जुड़े कामकाज ही हो रहे हैं। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान यह प्रक्रिया पूरी होने से आदेश के अनुपालन में तेजी आएगी।

**ऐसे खाली हो गई कोर्ट**

2017 में सेवानिवृत्त न्यायधीश अब्दुल मतीन के सेवानिवृत्त होने के बाद दो बेंच चल रही थी। इसके चार महीने बाद फरवरी 2018 में न्यायधीश डीपी सिंह सेवानिवृत्त हुए। अधिकरण की एकमात्र बेंच से 14 अगस्त 2019 को न्यायधीश एसवीएस राठौर से सेवानिवृत्त हो गए। उनके साथ प्रशासनिक सदस्य को प्रिंसिपल बेंच दिल्ली का कार्यभार दे दिया गया।

**ज्ञापन भेजा**

एएफटी बार एसोसिएशन की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा गया है। इस ज्ञापन में तीनों बेंच के लिए जल्द न्यायिक व प्रशासनिक सदस्यों की तैनाती की मांग की गई है। एसोसिएशन के महासचिव विजय कुमार पांडेय ने बताया कि सात महीने से नए मामले भी फाइल नहीं हो पा रहे हैं। पुराने मामलों में तीन फरियादियों की मौत हो चुकी है।

## जनरल नरवाने सुरक्षा हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- कोर मुख्यालय में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ की बैठक

थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तान की ओर से जंगबंदी के उल्लंघन से पैदा हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने कोर मुख्यालय में बैठक कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया।

सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को जनरल नरवाने के कश्मीर दौरे के कार्यक्रम में अंतिम समय में कुछ बदलाव किया गया है। वह सुबह नहीं दोपहर बाद करीब चार बजे श्रीनगर पहुंचे। चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो के नेतृत्व में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने टेक्नीकल एयरपोर्ट श्रीनगर पर उनका स्वागत किया। इसके बाद वह हेलीकाप्टर से कोर मुख्यालय पहुंचे। थल सेनाध्यक्ष ने कोर मुख्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो और अन्य वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ बैठक कर वादी के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव नवनीत ने जनरल नरवाने के कश्मीर दौरे की पुष्टि करते हुए बताया कि सेना प्रमुख बुधवार को वादी के समग्र हालात, आतंकरोधी अभियानों और एलओसी की मौजूदा स्थिति पर बैठक करेंगे। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जनरल नरवाने उत्तरी कश्मीर में अग्रिम चौकियों का दौरा करने के अलावा दक्षिण कश्मीर स्थित एक सैन्य प्रतिष्ठान भी जा सकते हैं। बालाकोट एयरस्ट्राइक के एक साल पूरा होने पर जनरल एमएम नरवाने का कश्मीर दौरा बहुत अहम माना जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने मंगलवार को दिल्ली के मोतीबाग स्थित सर्वोदय को-एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास देखी। उन्होंने बच्चों से बातें भी कीं ● एपी

ट्रंप और मेलानिया ने मंगलवार को राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की ● एपी

ट्रंप दंपती ने राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वहां मालाबार शाहबलूत का एक पौधा भी लगाया ● एएनआइ

पति जेरेड कुशनर के साथ सिल्क शेरवानी में इवांका हैदराबाद हाउस पहुंचीं। जेरेड व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं ● प्रेट्र

## ट्रंप की यात्रा पर विदेशी मीडिया की मिलीजुली प्रतिक्रिया

**अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कई ने इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों को आगे ले जाने वाला बताया तो कई ने व्यापार समझौते के नहीं होने को लेकर इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं।**

### चीन से आगे निकलेगा भारत

The Washington Post

इस यात्रा को लेकर वाशिंगटन पोस्ट ने लाइव अपडेट्स के जरिए अपने पाठकों को ट्रंप की भारत यात्रा से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराई। इसमें हैनरी ओल्सन ने 'ट्रंप की भारत यात्रा बेहद अब तक की सबसे महत्वपूर्ण विदेश यात्रा हो सकती है' शीर्षक से लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप की यात्रा ताजमहल के सामने फोटो से कहीं ज्यादा है। साथ ही लिखा है कि वह 2027 तक चीन से आगे निकल जाएगा।

### तस्वीरों के लिए यादगार यात्रा

CNN

ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर सीएनएन के केविन लिप्टेक ने 'बिना किसी बड़े समझौते के ट्रंप की यात्रा समाप्त' शीर्षक लेख में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी बड़े व्यापार या सुरक्षा समझौते के भारत की अपनी दिखावटी राजकीय यात्रा समाप्त की। उन्होंने अपने लेख में ट्रंप की आलोचना की। साथ ही लिखा कि ट्रंप की यात्रा मुख्यत: इसकी तस्वीरों के लिए याद रखी जाएगी।

### तिलमिलाया पाकिस्तान

DAWN

डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए, लेकिन अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान को भूल गए। आम तौर पर भारत की यात्रा पर आने वाले हर अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान का भी दौरा करते रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इस बार नई शुरुआत की है। इससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन ने 'भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर मध्यस्थता करने को तैयार हूं, दिल्ली में बोले ट्रंप' शीर्षक की खबर को प्रमुखता दी है।

### नाम लेने में लड़खड़ाए

The Atlantic

अमेरिकी पत्रिका 'द अटलांटिक' ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के कार्यक्रम 'नमस्ते ट्रंप' पर टिप्पणी करते हुए इसे 'हाउडी मोदी' का सीक्वल बताया है। इसने आगे लिखा है कि ट्रंप ने हिंदी के कुछ शब्द बोलने की कोशिश की और जिस शहर में गए थे, उसका नाम लेने में ही लड़खड़ा गए। हालांकि वह जिस भीड़ के लिए भारत गए थे, वह उन्हें मिल गई।

### अमेरिका चुनाव रैली जैसा था नजारा

THE AUSTRALIAN

'द आस्ट्रेलियन' ने ट्रंप के भारत दौरे पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति का भारत में शानदार स्वागत हुआ। लोग उनकी झलक पाने को बेताब थे। मोटेरा स्टेडियम में एक लाख लोगों की भीड़ के सामने ऐसा लग रहा था कि ट्रंप मिडवेस्ट अमेरिका में चुनावी रैली में हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की। इसके अलावा ट्रंप ने कुछ खास भारतीय हस्तियों के नाम लिए। हालांकि हिंदी नामों के उच्चारण को लेकर वह जूझते रहे।

# कोरोना से लड़ेंगे भारत-अमेरिका

## ट्रंप-मोदी में हुई बात, अमेरिका ने भारतीय जनरिक दवाओं के लिए खोला बाजार

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता में कोरोना वायरस भी अहम मुद्दा रहा। पूरी दुनिया के लिए नए खतरे के रूप में सामने आए कोरोना वायरस से निपटने के लिए दोनों नेताओं ने साझा प्रयास करने पर सहमति जताई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) चेतावनी दे चुका है कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर सकता है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच भारतीय जनरिक दवाओं तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों व दवाओं के लिए अमेरिकी बाजार खोलने पर समझौता हुआ है।

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर संतोष जताया कि भारत और अमेरिका अभी तक कोरोना को रोकने में सफल रहे हैं। लेकिन चीन के बाहर ईरान, इराक, इटली, दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों में इसके तेजी से फैलने को देखते इससे निपटने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। ध्यान देने की बात है कि संक्रामक बीमारियों से निपटने और उसके लिए टीका तैयार करने के लिए भारत अमेरिका के बीच पहले से सहयोग चल रहा है। गांधी-रीगन विज्ञान व तकनीक समझौते के तहत दोनों देश कई संक्रामक बीमारियों के टीके के इजाद के लिए संयुक्त अनुसंधान और शोध कर रहे हैं। अब इसमें कोरोना को भी शामिल किया जा सकता है।

**महंगी दवा अमेरिका में रही है बड़ा मुद्दा :** वहीं चिकित्सा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हुई समझौते से भारतीय जनरिक दवाओं के लिए अमेरिकी बाजार खोलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल महंगी चिकित्सा अमेरिकियों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है और ट्रंप अगले राष्ट्रपति चुनाव में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकते हैं। वहीं दुनिया की कुल जनरिक दवाओं का 20 फीसद निर्माण करने वाली भारतीय दवा कंपनियों के लिए बड़ा बाजार मिल जाएगा। समझौते के तहत अमेरिका जनरिक दवा बनाने वाली भारतीय कंपनियों को अपने यहां के सख्त नियम-कायदे और मानकों के पालन में मदद करेगा। इससे भारतीय कंपनियों को उच्च क्वालिटी की जनरिक दवाएं बनाने में महारत हासिल होगी। यह भारतीय ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा कि क्योंकि अमेरिका को दवा आपूर्ति करने वाली कंपनियां भारतीय ग्राहकों के लिए भी उच्च क्वालिटी की दवाएं बनाएंगी।

चिकित्सा क्षेत्र में दूसरे समझौते के तहत अमेरिका ने आंशिक रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति और दवाओं को मान्यता दे दी है। इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और दवाएं अब अमेरिका में उपलब्ध हो सकेंगी। अभी तक भारतीय पारंपरिक दवाओं और चिकित्सा पद्धतियों को अमेरिका में मान्यता नहीं थी और उन्हें फूड सप्लीमेंट के रूप में अमेरिका में बेचा जाता था। जाहिर है आयुर्वेद समेत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए यह बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है।

वहीं दूसरी ओर भारत ने मानसिक रोगों के उपचार के लिए कमजोर चिकित्सा प्रणाली को दूर करने के लिए अमेरिकी अनुभवों का लाभ उठाएगा। भारत में मानसिक बीमारी एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है। जबकि अमेरिकी संस्थानों ने इस संदर्भ में काफी व्यापक अध्ययन किया है। यह अमेरिका में हेल्थ केयर का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है।

**चिकित्सा क्षेत्र में चल रहे हैं कई सहयोग कार्यक्रम :** दरअसल भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही चिकित्सा क्षेत्र में कई सहयोग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत में अमेरिका के सहयोग से ग्लोबल डिजीज डिटेक्शन सेंटर चलाया जा रहा है। टीकाकरण के लिए भी भारत में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके तहत संक्रामक रोगों के लिए टीका ईजाद करने में संयुक्त तौर पर रिसर्च कर रहे हैं। आम जनता को किफायती कीमत पर रोगों की जांच सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी दोनो देशों के बीच सहयोग चल रहा है।

राष्ट्रपति भवन में डोनाल्ड ट्रंप व मेलानिया का स्वागत करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साथ में मौजूद पत्नी सविता कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ● ध्रुव कुमार

## इवांका ने सिल्क शेरवानी में लिया देसी अवतार

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने भी देसी अवतार लिया है। इवांका ने भारत दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को भारतीय फैशन डिजाइनर अनीता डोगरे की डिजाइन की गई सिल्क की शेरवानी पहनी।

राष्ट्रपति भवन में ट्रंप के स्वागत समारोह में इवांका ने मुर्शिदाबाद के हाथ के काम वाली सिल्क की सफेद शेरवानी पहनी। फैशन डिजाइनर अनीता ने बताया कि यह शेरवानी क्लासिक और हमेशा चलन में रहने वाली है। यह स्टाइल उन्होंने बीस साल पहले शुरू की थी और आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती है। डोगरे ने कहा कि सिल्क की शेरवानी में आज भी वही करिश्मा है, फिर चाहे वह किसी भी रंग की हो।

मेलानिया ने विगत सोमवार को भारतीय टेक्सटाइल की विरासत को बनारसी हरी बेल्ट से सलामी दी थी। उन्होंने सफेद रंग का क्रेप का बना जंप सूट पहना था। मंगलवार को उन्होंने डिजाइनर हरेरा की कॉटन-सिल्क मिक्स्ड ड्रेस पहनी। सफेद रंग की ड्रेस पर लाल रंग की बेल्ट और सफेद जूते पहने थे। हरेरा संभवतः अमेरिका की सभी प्रथम महिलाओं की पसंद रही हैं। उन्होंने जैकलीन कैनेडी से लेकर लॉरा बुश और मिशेल ओबामा की ड्रेस भी बनाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गहरे नीले सूट पर लाल रंग की टाई लगाई थी। मंगलवार की रात राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में मेलानिया ने गुलाबी रंग का सोबर ढीला गाउन पहना था। वहीं इवांका भी सफेद रंग पर बेल और लाल गुलाब बना फिटिंग वाला गाउन पहना था। ट्रंप गहरे नीले सूट और धारीदार नीली टाई में नजर आए।

# राष्ट्रपति भवन में ट्रंप को दी गई 21 तोपों की सलामी

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप के शानदार स्वागत के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत दौरे के दूसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के साथ इस अवसर पर ट्रंप की बेटी व सलाहकार इवांका, दामाद जेरेड कुशनर और अमेरिकी प्रशासन के कई वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे।

डोनाल्ड ट्रंप के लिए राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रंप का स्वागत किया। जैसे ही ट्रंप दंपती अपनी बीस्ट कार से राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद ट्रंप को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तीनों सेना के बाइक सवार ट्रंप के काफिले को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे।

राष्ट्रपति कोविंद ने ट्रंप और उनकी पत्नी की अगवानी की और ट्रंप को भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मिलवाया। ट्रंप की अगवानी के समय पीएम मोदी भी मौजूद थे। मोदी ने राष्ट्रपति भवन में ट्रंप का सभी मेहमानों से परिचय करवाया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया के साथ राष्ट्रपति कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद के साथ-साथ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति भवन में गॉर्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी से शानदार स्वागत किया गया। ● एएफपी

## डिनर बहिष्कार से असहज होगी कांग्रेस

**सियासत**

- राष्ट्रपति देते हैं विदेशी मेहमान के स्वागत में डिनर पार्टी
- पार्टी अध्यक्ष को बुलाने की नहीं रही है परंपरा

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली:** राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत डिनर का बहिष्कार कांग्रेस को ही असहज कर सकता है। दरअसल जिस तरह कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के निमंत्रण को सिर्फ इस वजह से ठुकराया कि उसमें कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया है, तो वह परिवारवाद की भावना को बुलंद करता है। वहीं विदेशी मेहमान के सामने यह आचरण सवाल खड़ा करता है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही यह आवाज उठने लगी है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। जाहिर तौर पर गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष का संकेत दिया जा रहा है।

राष्ट्रपति के डिनर में कांग्रेस से तीन नेताओं का आमंत्रित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता के विपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। यह और बात है कि अधीर रंजन के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। वह लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं, सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं। खैर, सबसे पहले विवाद भी चौधरी ने ही शुरू किया। उन्होंने आपत्ति जताई कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया है। लिहाजा वह भी नहीं जाएंगे।

परंपरा के अनुसार ऐसे भोज में किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया जाता है। कांग्रेस के दस साल के कार्यकाल में जार्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा भारत आए थे और उनके सम्मान में आयोजित भोज में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष को निमंत्रित नहीं किया गया था। वर्ष 2015 में जब बराक ओबामा दोबारा आए थे तो जरूर सोनिया गांधी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन तब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे और व्यक्तिगत मित्रता के कारण उन्हें बुलाया गया था।

बताया जाता है कि चौधरी के बयानों के बाद कांग्रेस के बाकी दो नेताओं ने भी डिनर से दूर रहने का फैसला किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य का कारण बताया जबकि आजाद पहले निमंत्रण स्वीकार कर चुके थे लेकिन बाद में खेद जता दिया।

## मोदी-ट्रंप मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम

**अहमियत**

- अमेरिकी सांसद बोले, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण
- ट्रंप का भव्य स्वागत दोनों देशों के रिश्तों का उदाहरण

**वाशिंगटन, प्रेट्र :** राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह कहना है अमेरिका के सांसदों का।

2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी की दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे सीनेटर टेड क्रूज का कहना है कि भारत एक मित्र, एक सहयोगी और इस पृथ्वी का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्रूज ने ट्वीट किया, 'पिछले साल टेक्सास में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर मुझे गर्व हुआ था, जहां मैंने भारत-अमेरिकी मित्रता की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।' सांसद पेट ओल्सन ने कहा, व्यापार और कूटनीति में अमेरिका के सबसे बड़े साझेदारों में से एक भारत में ट्रंप का भव्य स्वागत देखकर बहुत अच्छा लगा। दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी के साथ ही अब इस ऐतिहासिक यात्रा के नतीजों का इंतजार है। रिपब्लिकन नेता केविन मैककर्थी ने फॉक्स न्यूज से कहा कि भारत में ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत दोनों देशों के बीच के मधुर और मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। ट्रंप की यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे, जिससे दुनिया को भी मजबूती मिलेगी। सीनेटर जेम्स लैंकफोर्ड ने कहा कि दुनिया भर में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए व्यापार के साथ ही साथ सैन्य क्षेत्र में भारत-अमेरिका के बीच मजबूत संबंध अहम हैं। परामर्श सेवा प्रदाता कंपनी साउथ एशिया बीजीए के प्रबंध निदेशक पर्सिस खंबाटा ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे।

**स्वागत भोज** मेन्यू पर थी खुद पीएम मोदी की नजर, डिनर पर ट्रंप बोले-'मैं भारत से प्यार और भारतीयों की इज्जत करता हूं'

# सुरीले माहौल में ट्रंप को परोसे गए लजीज व्यंजन

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली:** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के भारत दौरे के दौरान खानपान के बेहतरीन इंतजाम के साथ उनकी पंसद का पूरा ख्याल रखा गया। दिल्ली में दिया गया लंच और डिनर इनमें सबसे खास था। बताते हैं कि इन व्यवस्थाओं पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी पूरी नजर रखे हुए थे। ट्रंप की पसंद को देखते हुए मोटेरा में तो 18 प्रकार की केवल आइसक्रीम थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति के दो दिनी दौरे की शुरुआत सोमवार को अहमदाबाद से हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें एक लंच मोटेरा (अहमदाबाद) में दिया था। और दूसरा लंच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जहां औपचारिक वार्ता भी हुई थी। सारंगी और संतूर की जुगलबंदी के बीच इस शानदार लंच की शुरुआत हुई। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनका परिवार, अमेरिकी अधिकारी और करीब सौ खास मेहमानों को बुलाया गया था। जबकि डिनर का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया था। 130 हेक्टेयर में फैले जगमगाते राष्ट्रपति भवन में मंगलवार की रात दरबार हॉल में स्वागत सत्कार से अभिभूत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'यह दो दिन उनके लिए बेहद खास थे। मैं भारत से प्यार करता हूं और भारतीयों की इज्जत करता हूं। हम वापस आएंगे।' इसके जवाब में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, 'पिछले दो दिन भारत के लिए भी बेहद खास रहे। चूंकि अमेरिका-भारत के संबंध बेहद गहरे हैं। भारत अमेरिका को लंबी अवधि का मित्र और स्वाभाविक साझीदार मानता है।'

ट्रंप के सम्मान में दिल्ली में दिए गए लंच और डिनर का मेन्यू लगभग एक जैसा ही था। डिनर में कुछ अमेरिकन डिश भी शामिल थे। इस पूरे क्रम में प्रधानमंत्री परोसे जाने वाले खाने को लेकर कितने सतर्क थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हैदराबाद हाउस के लंच के लिए जब उन्होंने छोटा मेन्यू देखा जिसमें मेन कोर्स में महज दो या तीन आइटम थे तो उन्होंने कहा, 'देखना कोई भूखा न रह जाए।'

**बजे ये संगीत :** लंच की शुरुआत गांधीजी के प्रिय भजन वैष्णव जन से हुई। बाद में जगजीत सिंह की गजल 'मेरा गीत अमर कर दो व सत्यम शिवम सुंदरम' आदि पेश किए गए। समापन छूकर मेरे मन को से हुआ। कार्यक्रम में रवींद्र नाथ टैगोर का गीत 'एकटुकु छोया लागे' और नुसरत फतेह अली खान का हिट गीत 'भर दो झोली मेरी' जैसे गीत भी बजाए गए। जबकि राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के वक्त एरिक क्लैप्टन, एल्टन जॉन, राड स्टीवर्ट जैसे मशहूर गायकों के गाने बजे। इक प्यार के नगमा है जैसे हिंदी गानों की धुन भी बजी। मेहमानों में पीएम मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और संगीतकार एआर रहमान आदि मौजूद रहे।

### लंच और डिनर का मेन्यू

**शाकाहारी :** अनानास सन्सव (सरसों के साथ अनानास), पंच फोरन कटहल, दाल रायसीना, जीरा वन, छाक छेना कबाब, दम गुच्ची मटर, अंकुरित सब्ज का अर्क, भरवां गुच्ची, केसर के फूलों की ग्रेवी, छुआरा हलवा, रबड़ी, मालपुआ, खुमानी मिलि फुली, वर्क वाली अंजीर आइसक्रीम।

**मांसाहारी :** नारा नुक्ति, गुलाबी मछली, तुलसी चटनी, तार मुर्ग, दम गोश्त बिरयानी, देग की बिरयानी, रान आली शान (मैरिनेटेड लैंब) आदि।

दावत के लिए जाते ट्रंप दंपती ● एएफपी

## बच्चों का साथ...

अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप दिल्ली सरकार के एक सर्वोदय को-एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दौरे के वक्त दो बच्चों की अंगुलियां थाम कर चहलकदमी करती दिखीं। ● एपी

# कश्मीर बड़ी समस्या, मदद को तैयार : ट्रंप

## कूटनीतिक पहल ▶ भारत ने कश्मीर में हो रहे सकारात्मक बदलावों के बारे में बताया

### कहा, राज्य में विकास करने पर हमारा पूरा फोकस

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

उम्मीद के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच हुई शिखर वार्ता में कश्मीर का मुद्दा उठा और इसके तमाम पहलुओं पर बात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता करने का सीधे तौर पर कोई ऑफर तो नहीं आया है, लेकिन उन्होंने इस समस्या के समाधान में हर तरह की मदद करने की बात जरूर कही है। साथ ही पाकिस्तान को भी आतंकवाद से लड़ने में मदद करने की बात कही। खास तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ अपने रिश्तों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर का समाधान निकालने के लिए वह उन पर भी दबाव बना रहे हैं।

माना जा रहा है कि मोदी की तरफ से उनको कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद वहां हो रहे सकारात्मक बदलावों के बारे में बताया गया है। ट्रंप के रवैये से साफ था कि वह एक तरफ रणनीतिक साझीदार भारत के साथ जुड़े हितों और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के साथ होने वाले समझौते में पाकिस्तान की जरूरत को देखते हुए सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं।

द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में ट्रंप ने कहा, 'हमने पाकिस्तान पर बात की है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से मेरे बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह (पाक समर्थित आतंकवाद) एक समस्या है। बड़ी समस्या है। वह (पाकिस्तान) इस पर काम कर रहा है। मेरी इस बारे में भी पीएम मोदी से काफी विस्तार से बात हुई है। भारत एक बहादुर देश है और इसके पीछे हटने का सवाल नहीं है। मैंने कहा है कि मुझसे जो भी बन पड़ेगा मदद के लिए वह मैं करूंगा। क्योंकि दोनों नेताओं के साथ मेरे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। वैसे पाकिस्तान में काफी समस्या है, जिसमें मैं मदद करना चाहता हूं। कश्मीर भी एक बड़ी समस्या है, जो दोनों देशों के लिए कांटा बना हुआ है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं।'

दोनों नेताओं की बातचीत में कश्मीर का मुद्दा उठने की तसदीक विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने भी की। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर सकारात्मक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने साफ तौर पर बताया कि कश्मीर में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। राजनयिकों के दो दल वहां जा चुके हैं, जिनमें अमेरिकी राजदूत भी शामिल थे। कश्मीर में विकास करने पर हमारा पूरा फोकस है। सनद रहे कि ट्रंप की तरफ से पहले कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने की बात हुई है, जिसे भारत स्पष्ट तौर पर नकार चुका है। मोदी सितंबर, 2019 में वाशिंगटन में ट्रंप से अपनी मुलाकात में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कश्मीर के साथ एक ही समस्या है और वह है पाक के समर्थन से चलाया जा रहा आतंकवाद।

मोदी और ट्रंप के बीच अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठा। अमेरिका दो दिन बाद ही 27 फरवरी को तालिबान के साथ एक समझौता करने जा रहा है। इसको लेकर भारत की चिंता है कि कहीं अफगानिस्तान में पाक समर्थित तालिबान के आने से कश्मीर में आतंकवाद और न भड़क जाए। ट्रंप ने कहा कि मोदी ने अफगास्तिान समझौते पर प्रसन्नता जाहिर की है। मुझे लगता है कि दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी यह डील होते देखना चाहता है। इस समझौते का सभी स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका की मंशा एक वैश्विक पुलिस बनने की अब नहीं है।

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मंगलवार को संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एएनआइ

### पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने सीमा पार आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की है। उन्होंने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उसकी धरती का इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए नहीं किया जाए। उन्होंने मुंबई और पठानकोट हमले समेत अन्य आतंकी घटनाओं के अपराधियों को न्याय दिलाने में तेजी लाने की मांग की। उन्होंने अल-कायदा, आइएस, जैश-ए-मुहम्मद, लश्कर-ए-तय्यबा, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क और डी-कंपनी समेत सभी आतंकी संगठनों और इसके सहयोगियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की।

### 'किसी देश से चुनावी मदद नहीं चाहता'

नई दिल्ली, रायटर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि कोई भी देश नवंबर में होने जा रहे चुनाव को जीतने के लिए उनकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक शीर्ष खुफिया अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों से कहा था कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था ताकि ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिल सके।

दो दिवसीय भारत यात्रा की समाप्ति पर ट्रंप पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अमेरिकी सांसदों को उपरोक्त ब्रीफिंग के बाद ट्रंप ने कार्यकारी खुफिया प्रमुख जोसेफ मेगोइर को पद से हटाकर उनके स्थान पर अपने विश्वस्त को नियुक्त कर दिया था। प्रेस कांफ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि मेगोइर को शीर्ष खुफिया कार्य से हटा दिया गया था, उन्होंने कहा कि कानून की वजह से उन्हें बदलना जरूरी था। ट्रंप ने कहा कि वह खुफिया प्रमुख पद के लिए नाम की घोषणा शीघ्र ही करेंगे। हालांकि इस नियुक्ति के लिए उन्हें अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से मंजूरी हासिल करनी होगी। ज्ञात हो कि अमेरिकी खुफिया समुदाय का आकलन है कि रूस ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप किया था, हालांकि रूस ने इस आकलन को खारिज किया है।

### 'मैं कभी विंस्टीन का प्रशंसक नहीं था'

नई दिल्ली, प्रेट्र : हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वे विंस्टीन को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कभी भी विंस्टीन के प्रशंसक नहीं थे। मिशेल ओबामा और हिलेरी क्लिंटन जैसे डेमोक्रेट पार्टी के नेता उसके प्रशंसक थे। ट्रंप ने कहा कि वह विंस्टीन को थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन अच्छी तरह से नहीं।

# चीन पर लगा निशाना लेकिन संभलकर

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- मोटेरा स्टेडियम से लेकर संयुक्त बयान तक में चीन पर परोक्ष वार
- 5जी को लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश

यह कोई छिपी बात नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक गठबंधन के पीछे एक बड़ी वजह चीन भी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो दिनों के भारत दौरे के दौरान कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने चीन पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी हालांकि उनका रवैया पहले से ज्यादा संयमित था। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में पहले ट्रंप ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारत ने खुलेपन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आर्थिक शक्ति के तौर पर खुद को स्थापित किया है उन देशों की तरह नहीं जो अंकुश लगाकर रखते हैं। मोदी के साथ बातचीत में उन्होंने 5जी का मुद्दा उठाया और इसके जरिये चीन पर निशाना साधा। इसी तरह देर रात जब भारत और अमेरिका का संयुक्त बयान जारी किया गया तो उसमें भी हिंद-प्रशांत का जिक्र किया गया, लेकिन चीन का सीधे तौर पर नाम लेने से गुरेज किया गया।

संयुक्त बयान में दोनों देशों ने अपनी पुरानी नीति को आगे बढ़ाते हुए हिंद-प्रशांत सागर क्षेत्र को एक मुक्त, खुला, शांतिपूर्ण, समृद्धशाली और सभी के लिए एक समान अवसर वाला क्षेत्र बनाने की बात कही है। इसके लिए दोनों देशों ने और गहरी साझेदारी स्थापित करने की बात कही है जिसके केंद्र में आसियान के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून और गुड गवर्नेंस का सम्मान करना, हर तरह के जहाजों के आसानी से आवागमन और सभी को कारोबार करने की सुविधा की बात कही गई है। दक्षिण चीन सागर का जिक्र करते हुए भारत-अमेरिका ने इस क्षेत्र में विवादों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सुलझाने की बात कही है और यहां एक आचार संहिता बनाने की बात कही है। अमेरिका ने इस बात की प्रशंसा की है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में किस तरह से सुरक्षा स्थापित करने वाली शक्ति बना है। हिंद महासागर में धीरे-धीरे पैर फैलाने में जुटे चीन को यह बात नागवार गुजर सकती है। दोनों देशों ने यह भी कहा है कि दोनों देश इस समूचे क्षेत्र में पारदर्शी तरीके से ढांचागत परियोजनाओं को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें विकसित करने में भी सहयोग करेंगे।

इस संदर्भ में दोनों देशों ने ब्लू डॉट इकोनॉमी का कांसेप्ट दिया है। मोदी और ट्रंप के बीच इस बारे में विस्तार से बात हुई है। यह कांसेप्ट कम आय वर्ग वाले देशों में ढांचागत सुविधाओं के विकास में कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाली एजेंसियों के अधिकार व कर्तव्यों का पारदर्शी तरीके से निर्धारण करेगा। यह एक तरह से विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा ताकि गरीब देशों के विकास के लिए कर्ज देने का एक सम्मानजनक माध्यम विकसित किया जा सके। माना जा रहा है कि चीन के कर्ज के बोझ तले कई देशों के दब जाने की बात सामने आ रही है उसे देखते हुए इस कांसेप्ट की शुरुआत की गई है। पाकिस्तान व श्रीलंका में भी चीन के बढ़ते कर्ज को लेकर चिंताएं जताई जाने लगी हैं।

संयुक्त बयान से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीडिया के सामने बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि 5जी का इस्तेमाल संचार व विकास के लिए होना चाहिए किसी चीज को छिपाने या दूसरे को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। सनद रहे कि अमेरिका चाहता है कि भारत चीन की कंपनी हुवेई का 5जी का इस्तेमाल नहीं करे। अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा चुका है।

# अमेरिकी जनमानस में भी ट्रंप दंपती के शाही स्वागत की मची धूम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा पर भारी भीड़ के हुजूम के साथ हुए उनके स्वागत को कुछ लोग प्रचार तमाशा बताकर भले ही नजरअंदाज कर रहे हों मगर अमेरिका में इसकी जबरदस्त धूम है। अहमदाबाद में हुए ट्रंप के अभूतपूर्व शाही इस्तकबाल ने अमेरिकी जनमानस ही नहीं वहां के थिंक-टैंक को भी हतप्रभ कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के कूटनीतिज्ञ तो ट्रंप के स्वागत में उमड़े जनसैलाब की तस्वीर को भारत-अमेरिका के भविष्य के प्रगाढ़ रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कुंजी तक मान रहे हैं।

नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में मोटेरा स्टेडियम में जुटी एक लाख से अधिक लोगों की भीड़ हो या अहमदाबाद एयरपोर्ट से स्टेडियम तक के 22 किलोमीटर के पूरे रास्ते ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया के स्वागत में उमड़े हजारों लोगों की अनोखी तस्वीरें अमेरिकी मीडिया में छायी हुई हैं। दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐसा धमाकेदार स्वागत शायद ही कभी हुआ होगा। ट्रंप-मेलानिया के प्रति भारतीयों के दर्शाए प्यार और लगाव ने अमेरिकी जनता के दिलो-दिमाग को छू लिया है और बेशक दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को भविष्य में यह नई ऊंचाई देगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने खुद मोदी-ट्रंप बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेस में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के असाधारण स्वागत से भारत-अमेरिका के लोगों का आपसी जुड़ाव ज्यादा मजबूत होगा। हमारे दोनों देशों के नागरिकों के आपसी जुड़ाव को और सुदृढ़ कराना राष्ट्रपति ट्रंप के इस दौरे का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू रहा। श्रृंगला ने कहा कि अमेरिकी थिंक-टैंक, जनमानस, सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के लेख में अमेरिकी राष्ट्रपति का इस तरह से हुए सम्मान-स्वागत की चर्चा है। लाखों लोगों के इस तरह स्वागत में उमड़ने की घटना केवल तस्वीर नहीं बल्कि भविष्य में पीपुल टू पीपुल संबंधों को गहराई देने की कुंजी है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह ने भी कहा कि ट्रंप दंपती के अद्भुत स्वागत की अमेरिका में जबरदस्त चर्चा है और इसीलिए अब भारत-अमेरिका रिश्तों को 'अपराजेय साझेदारी' माना जा रहा है।

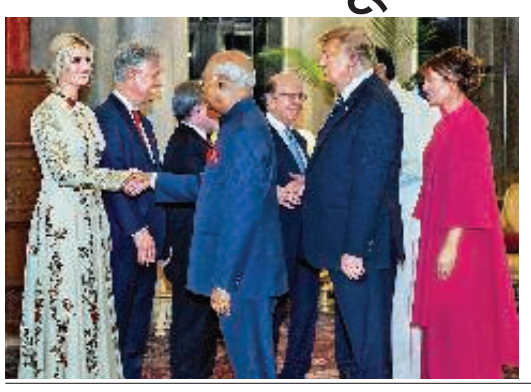

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष रात्रिभोज के दौरान इवांका ट्रंप का स्वागत करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। साथ में हैं ट्रंप दंपती। इवांका ने इस दौरान अनारकली से प्रेरित गाउन पहन रखा था। रायटर

### सीएनएन के पत्रकार से राष्ट्रपति की नोकझोंक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी चैनल सीएनएन के विवादित पत्रकार जिम अकोस्टा के बीच मंगलवार की शाम प्रेस कांफ्रेंस के दौरान तीखी बहस हो गई। पत्रकार के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विदेशी दखल खारिज करने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज चैनल की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा दिया। उसी के बाद अकोस्टा ने ट्रंप से राष्ट्रीय खुफिया विभाग के नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति पर सवाल दागा। पत्रकार जिम अकोस्टा ने कहा कि ट्रंप ने ऐसे अधिकारी को चुना है जिसे इंटेलिजेंस का कोई अनुभव ही नहीं है। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी देश से कोई मदद नहीं चाहिए और ना ही उन्होंने किसी देश को कोई मदद दी है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप और अकोस्टा के बीच पहले भी कई बार तल्खी भरी झड़प हो चुकी है। वर्ष 2018 में इसीलिए व्हाइट हाउस ने जिम अकोस्टा को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद अकोस्टा ने मानहानि का दावा व्हाइट हाउस पर ठोंका था।

# वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद के खतरे को समझने लगा है अमेरिका

अनिल भारद्वाज, गुरुग्राम

वैश्विक इस्लामिक आतंक के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को सेना के पूर्व अधिकारियों ने दूरगामी प्रभाव वाली नीति करार दिया है। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि वैश्विक इस्लामिक आतंक को अब अमेरिका समझने लगा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान के बाद इस्लामिक आतंक को कुचलने की लड़ाई मजबूत होगी। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि भारत दशकों से वैश्विक आतंक की बात करता आ रहा है, लेकिन पहले दुनिया में कोई नहीं मान रहा था। आज हर देश किसी न किसी रूप में आतंक से ग्रस्त है और अमेरिका वैश्विक आतंक पर बात करने लगा है।

आतंक को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया है, जिसका असर भी हुआ है। आज आतंकी फंडिंग के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की पाकिस्तान के सिर पर काली सूची में शामिल होने की तलवार लटकी हुई है। वहीं, अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान से समझौता करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। अगर तालिबान दोबारा मजबूत होता है तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अमेरिका को समझना होगा कि अब भारत में आतंक से समझौता करने वाली सरकार नहीं है।

– मेजर जनरल (रिटा.) डॉ. जीडी बख्शी

हमें उन बातों पर नहीं जाना है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या कर रहा है। आतंक से दो तरह की लड़ाई होती है एक सैन्य कार्रवाई और दूसरा उसके खिलाफ बोलने वालों की संख्या। भारत वर्षों से आतंक के बारे में बोल रहा था और कोई सुन नहीं रहा था। आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश स्वयं बोल रहा है कि इस्लामिक आतंक है। इससे भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी और यह भारत की जीत है।

– मेजर जनरल (रिटा.) पीके शर्मा

भारत में कहा जाता है कि आतंक का धर्म नहीं होता है, जबकि सच्चाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। उन्होंने बोला और दुनिया को बताया है कि इस्लामिक आतंक है। सच्चाई से भागने के बजाय, दुनिया को सामना करना चाहिए। ट्रंप का भारत की धरती से इस्लामिक आतंक के खिलाफ बोलना भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई को बल मिला है। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर आतंक से लड़ने पर जोर दिया है।

– ब्रिगेडियर (रिटा.) एएल संदल

# भारत को हथियार बेचने पर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप की आलोचना की

वाशिंगटन, प्रेट्र: राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार बर्नी सैंडर्स ने भारत को हथियार बेचने के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। सोमवार को उन्होंने कहा कि हथियार बिक्री की जगह अमेरिका को भारत के साथ धरती बचाने की खातिर जलवायु परिवर्तन से निपटने में साझेदारी करनी चाहिए। सैंडर्स नेवादा और न्यू हैंपशायर की प्राइमरी जीत चुके हैं जबकि आयोवा का परिणाम अभी नहीं आया है।

भारत के दो दिवसीय दौरे पर आए ट्रंप ने सोमवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भारत के साथ तीन अरब डॉलर के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करने की बात कही थी। मंगलवार को इस समझौते को अमलीजामा पहना भी दिया गया। सैंडर्स ने कहा, 'रेथियॉन, बोइंग और लॉकहीड को संपन्न बनाने के लिए तीन अरब डॉलर के हथियार बेचने के बजाए अमेरिका को भारत के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझेदारी करना चाहिए।'

# महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित दिखे ट्रंप और मेलानिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- राजघाट पर विजिटर बुक में लिखा, अमेरिका की जनता मजबूती से भारत के साथ

मंगलवार सुबह 10.30 बजे राजघाट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्नी मेलानिया के साथ पहुंचे। चारों तरफ पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का तांता लगा हुआ था। मुस्कराते हुए ट्रंप और मेलानिया द बीस्ट कार से उतरे। दोनों की अगवानी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। इसके बाद तीनों समाधि स्थल की ओर बढ़ चले। ट्रंप दंपती के हाव-भाव इस दौरान उत्सुकता भरे थे।

चारों तरफ राजघाट की हरियाली और शांति को दोनों महसूस कर रहे थे। ट्रंप और मेलानिया ने समाधि स्थल पर पुष्प चक्र चढ़ाने के बाद आंखें बंदकर दो मिनट का मौन धारण करते हुए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा के दौरान ट्रंप और मेलानिया को देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे दोनों भाव-विभोर हो गए हों। समाधि स्थल से हटने से पहले एक बार फिर दोनों ने कुछ सेकेंड का मौन रखा। मेलानिया ने तो जाते-जाते हाथ जोड़कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नमन भी किया।

बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने राजघाट विजिटर बुक में संदेश लिखा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा-'अमेरिका की जनता मजबूती से भारत के साथ खड़ी है। महात्मा गांधी की भी यही दृष्टि थी। यह मेरे लिए बहुत आदर की बात है।' ट्रंप के इतना लिखते ही यह मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजघाट पर मौजूद लोगों को तो एहसास हो ही रहा था कि ट्रंप भारत आकर बेहद प्रसन्न हैं, मगर वह इतनी बड़ी बात लिख देंगे इसकी अपेक्षा नहीं थी।

**रोपा मालाबार शाहबलूत का पौधा :** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजघाट पर मालाबार शाहबलूत का पौधा रोपा। हालांकि, एक दिन पहले तक पौधा रोपने का कार्यक्रम नहीं था, मगर अंत समय में विदेश मंत्रालय ने इसके लिए राजघाट समाधि कमेटी को इसका इंतजाम करने को कहा।

राजघाट विजिटर बुक में संदेश लिखने के बाद ट्रंप दंपती पौधा रोपने वाले स्थल पर पहुंचे। यहां पहले से मालाबार शाहबलूत को गड्ढे में रखा जा चुका था। दंपती ने बेलचा से इसमें मिट्टी डाली और आगे बढ़ गए।

**ओबामा से तुलना :** उनके पौधारोपण की तस्वीरें भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। लोग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की राजघाट पर पौधारोपण करने के तरीके से उनकी तुलना करने लगे। ओबामा वर्ष 2015 में भारत आए थे। तब वे राजघाट गए थे और वहां ज्ञानवृक्ष पौधा लगाया था। ओबामा ने न सिर्फ मिट्टी डाली थी, बल्कि खुद बैठकर पौधा लगाया था और पौधे को पानी भी दिया था।

# तापसी पन्नू की फिल्म 'थप्पड़' मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री

नईदुनिया, इंदौर: तापसी पन्नू अभिनीत हिंदी फिल्म 'थप्पड़' को मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स में छूट देने का एलान किया है। सरकार की घोषणा के बाद राज्य कर विभाग ने फिल्म को तीन महीने के लिए एसजीएसटी से छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। अनुभव सिन्हा की निर्देशन में बनी फिल्म में घरेलू हिंसा का मुद्दा उठाया गया है। फिल्म 28 फरवरी को रिलीज होगी।

सरकार के निर्णय और आदेश जारी होने के बाद राज्य कर विभाग ने सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स को निर्देशित किया है कि फिल्म देखने आने वाले दर्शकों से टिकट पर एसजीएसटी (स्टेट जीएसटी) न वसूलें। अभी फिल्म की टिकट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इसमें से आधा हिस्सा एसजीएसटी का होता है। प्रदेश सरकार इसी कर में छूट प्रदान कर रही है। इससे पहले दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को भी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया था।

तापसी पन्नू फाइल

गौरतलब है कि दीपिका ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसी तरह फिल्म थप्पड़ में अभिनय कर रही तापसी पन्नू भी जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई का विरोध करने के लिए चर्चा में आ चुकी हैं।

# दबंगों के खौफ से बरेली में अनुसूचित जाति के परिवार ने छोड़ा गांव, तनाव

जागरण संवाददाता, बरेली

उप्र के बरेली स्थित बिशारतगंज के मझगवां में दबंगों से परेशान होकर अनुसूचित जाति के दो भाइयों के परिवार ने गांव छोड़ दिया है। इससे गांव में तनाव है। एसएसपी शैलेश पांडेय ने बताया कि पुलिस ने मारपीट के आरोपितों पर कार्रवाई की है। घर छोड़कर जाने वाले पक्ष ने हत्या की फर्जी सूचना दी थी, जिस पर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। वे गांव छोड़कर क्यों चले गए, इसकी जांच कराई जाएगी।

मझगवां निवासी जयप्रकाश सागर अपने भाई नरेंद्र के साथ रहते हैं। जयप्रकाश सब्जी की दुकान लगाते हैं, जबकि नरेंद्र मजदूरी करते हैं। ढाई महीने पहले सब्जी के लेन-देन को लेकर घर के सामने रहने वाले विद्याराम व सोहनलाल कश्यप से जयप्रकाश का विवाद हो गया था। तभी से दोनों पक्षों में मनमुटाव था। 21 फरवरी को जयप्रकाश की पोती के नामकरण में साउंड सिस्टम चल रहा था। आरोप है कि विद्याराम व सोहनलाल ने उसे जबरन बंद करा दिया था।

जयप्रकाश के बेटे सत्यवीर ने विरोध किया तो उसे पीटा। शिकायत पर 22 फरवरी को पुलिस ने दोनों आरोपितों पर शांतिभंग की कार्रवाई की। जयप्रकाश का कहना है कि उसी रंजिश में सोमवार को दूसरे पक्ष के कई लोग घर में घुस आए और मारपीट की, एक कोने में आग भी लगा दी। शिकायत पर पुलिस ने हमें ही पीटकर चुप करा दिया।

मजबूरन रात में अपने व भाई नरेंद्र के परिवार के 15 सदस्यों के साथ ससुराल चौबारी चले आए। दूसरी ओर विवाद दो जातिगत पक्षों के बीच होने से तनाव की स्थिति है। आरोपित विद्याराम व सोहनलाल का कहना है कि आरोप मनगढ़ंत हैं। ग्राम प्रधान, मझगवां दामोदर यादव का कहना है कि दोनों पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा है। सोमवार को सुलह कराने की तैयारी थी मगर मुझे शहर जाना पड़ गया। देर रात लौटा तो पता चला कि जयप्रकाश पलायन कर गए हैं।

> 21 फरवरी को विवाद होने पर कार्रवाई की गई थी। दूसरे दिन जयप्रकाश के बेटे ने पिता की हत्या और आग लगने की फर्जी सूचना दी थी। पुलिस उस वक्त भी तुरंत पहुंची मगर वहां सब ठीक था। उसके बाद भी कोई घर छोड़कर चला जाए तो क्या किया जा सकता है।
>
> –राजेश कुमार, इंस्पेक्टर, बिशारतगंज।

# ग्रेनो में स्कूल ने 70 छात्रों को दो घंटे तक बनाए रखा बंधक

मनीष तिवारी, ग्रेटर नोएडा

छात्रों को नियमों व मानवता का पाठ पढ़ाने वाले स्कूल खुद इसके प्रति कितने संजीदा हैं, इसकी बानगी उप्र के ग्रेटर नोएडा (ग्रेनो) स्थित अल्फा एक सेक्टर के सेंट जोसफ स्कूल में मंगलवार को देखने को मिली। फीस न जमा करने वाले करीब 70 छात्रों को स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा देने से रोक दिया। इतना ही नहीं, छात्रों को हॉल में ले जाकर बंद कर दिया गया। छात्र रोते हुए मिन्नतें करते रहे कि उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाए, फोन पर परिजनों से बात करने की इजाजत दी जाए। लेकिन पत्थर दिल स्कूल प्रबंधन नहीं पसीजा। छात्रों को लगभग दो घंटे तक बंद रखा गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों को छोड़ा गया। छोटे बच्चे रोते हुए घर पहुंचे। जिसके बाद स्कूल पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। स्कूल प्रबंधन को खरी-खोटी सुनाई। स्कूल में हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। स्कूल के प्रधानाचार्य फादर आलविन पिंटू ने अभिभावकों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। जिन छात्रों की परीक्षा छूट गई उन्हें पिछले दो टर्म में मिले नंबरों के औसत के आधार पर नंबर देने का आश्वासन दिया। अभिभावकों ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल व मानवाधिकार में करने की बात कही है।

अभिभावक रनधीर ने बताया कि फीस न जमा करने पर स्कूल ने बच्चे को एक कक्षा में बंधक बना कर रखा। बच्चा रोते हुए घर पहुंचा। स्कूल की यह कार्रवाई बहुत ही दुखद है। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभिभावक आफताब आलम ने बताया कि अभी परीक्षाएं चल रही हैं। फीस फरवरी के अंत तक जमा होनी है। स्कूल ने बच्चे को दो घंटे तक एक कमरे में बंद कर रखा। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा जो हुआ गलत था, उसका दुख है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 26 फरवरी 2020

दैनिक जागरण

पैसे को भगवान बना लेंगे, तो यह आपको शैतान की तरह सताएगा

# मित्रता का नया अध्याय

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा बयान और फिर अपनी प्रेस कांफ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों और भारत से संबंधित मसलों पर जो कुछ कहा उससे यही रेखांकित हुआ कि वह भारत-अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने को तत्पर हैं। यही कारण रहा कि एक ओर जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई वहीं दूसरी ओर उन मसलों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी भी नहीं की जिन्हें नाजुक मान लिया गया था। सच तो यह है कि यह मान्यता भी मीडिया के एक खास हिस्से की ओर से गढ़ी गई थी और उसी के द्वारा यह माहौल बनाया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकता संशोधन कानून, कश्मीर आदि के मामले में भारत को सवालों से घेर सकते हैं। उन्होंने न केवल इस कृत्रिम माहौल को ध्वस्त किया, बल्कि साफ तौर पर कहा कि भारत में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को उचित ही भारत का आंतरिक मामला करार दिया। इससे कुछ लोगों को निराशा हुई होगी, लेकिन सच तो यही है कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत को भी अन्य देशों की तरह अपने नागरिकता कानून का निर्धारण करने का अधिकार है। इस कानून में संशोधन को लेकर देश के साथ विदेश में झूठ का एक पहाड़ अवश्य खड़ा किया गया है, लेकिन इससे यह सच्चाई बदलने वाली नहीं है कि यह कानून नागरिकता प्रदान करने का है, न कि छीनने का।

इस पर आश्चर्य नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हिंसा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। वास्तव में यही उचित भी था और अपेक्षित भी। जो यह उम्मीद लगाए थे कि कश्मीर में दिलचस्पी दिखाते रहे अमेरिकी राष्ट्रपति वहां के हालात को लेकर कुछ नया कहेंगे उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी होगी। निःसंदेह केवल उसे ही महत्व नहीं दिया जा सकता जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। इसी के साथ इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने किन समझौतों को आकार दिया? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है तीन अरब डॉलर का रक्षा समझौता। यह सही है कि व्यापार को लेकर समझौता नहीं हो पाया, लेकिन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह उम्मीद जताई कि जल्द ही बड़ा समझौता हो सकता है। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई का वह संकल्प लिया जो पहले भी लिया जा चुका है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान में भारतीय हितों का ध्यान रखने की बात कही। वास्तव में इन्हीं कारणों से ट्रंप की भारत यात्रा आपसी संबंधों को और मजबूती देने वाली कही जाएगी।

# ममता की चुनावी मुहिम

बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाताओं को साधने को चौतरफा प्रयास कर रही हैं। शिक्षा जगत को लेकर उनके दो फैसलों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार ने एक तरफ सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है और दूसरी तरफ पिछले साल हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षा (उच्च माध्यमिक) में कम अंक मिलने से असंतुष्ट छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के खुद निरीक्षण करने की अनुमति दे दी है। पिछले साल 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले बहुत से छात्र अब मतदाता हो गए हैं और जो नहीं हुए, वे भी 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएंगे। ममता सरकार ने एक तरह से उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे सभी छात्रों को साधने की पहल की है। बंगाल में छात्रों और युवाओं ने हमेशा माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएए एवं एनआरसी विरोधी आंदोलनों में भी विश्वविद्यालयों के छात्रों के अलावा माध्यमिक स्तर के ज्यादातर छात्र भी राज्य सरकार के समर्थन में दिख रहे हैं। 28 फरवरी, 2020 तक की समय सीमा तय करते हुए कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं के स्वयं निरीक्षण के लिए आवेदन किया था, वे इस तिथि तक परिषद कार्यालय में आकर उन्हें देख सकते हैं। पहले छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा उचित अपील के बाद कर सकते थे, लेकिन स्वयं निरीक्षण करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 20 फरवरी को जारी अधिसूचना में सभी आवेदकों से कहा गया है कि जो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का स्वयं निरीक्षण करना चाहते हैं, उन्हें परिषद कार्यालय आना होगा। 2019 की उच्च माध्यमिक परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने कम अंक मिलने की शिकायत की थी। जुलाई में घोषणा की गई थी कि मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं का खुद निरीक्षण करने की छात्रों को अनुमति दी जाएगी। इधर शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने जानकारी दी कि जनवरी 2016 के पहले सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के पेशन में वृद्धि की गई है। जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों की आयु 80 से 85 वर्ष के बीच है, उनकी मूल पेंशन में 20, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु वालों के मूल पेंशन में 30 फीसद की वृद्धि होगी। सरकार अपने इन फैसलों का प्रचार करने में भी जुट गई है। निःसंदेह यह एक अच्छे-खासे वर्ग को साधने का बड़ा प्रयास है।

# छोड़नी होगी मध्ययुगीन मानसिकता

शंकर शरण

इतिहास और वर्तमान, दोनों में ताकत की विफलताएं, हिंसा के परिणाम और उसकी सीमाएं देखी जा सकती हैं

अवधेश राजपूत

एआइएमआइएम के नेता वारिस पठान द्वारा समुदायिक बल का गुमान दिखाने से उनके सेक्युलर-वामपंथी समर्थक ही झेंपे, क्योंकि वे मुसलमानों के बारे में कुछ और बातें कहते रहते हैं। इसी पार्टी के अकबरुद्दीन ओवैसी तो कई बार अपनी 15 मिनट वाली धमकी दोहरा चुके हैं कि हम पच्चीस करोड़ हैं और तुम सौ करोड़ हो, लेकिन पंद्रह मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तब देख लेंगे कि किस में कितना दम है।' ऐसी भावना कई मुस्लिम नेता जब तब प्रकट करते रहते हैं। ये सार्वजनिक रूप से सरकार, सेना, न्यायपालिका को भी धमकी देते हैं। हाल में ऐसे भाषणों के तमाम वीडियो वायरल हुए हैं।

सबमें एक तत्व समान है-ताकत का घमंड। यह लगभग सौ साल से चल रहा है। कलकत्ता में मुस्लिम लीग के 'डायरेक्ट एक्शन' (1946) के बाद जिन्ना ने कांग्रेस को धमकी दी थी कि और नहीं तो 'केवल हिंदुओं को कत्लेआम और विनाश से बचाने के लिए' देश-विभाजन करो। उससे पहले 1924 में मौलाना अकबर शाह खान ने महामना मदनमोहन मालवीय को 'पानीपत का चौथा युद्ध' आयोजित करने की चुनौती दी थी। मौलाना ने यहां तक घमंड दिखाया कि वह लड़ने के लिए साधारण मुसलमान ही लाएंगे, पठान या अफगान नहीं। उसी दौर में निजामुद्दीन दरगाह के सूफी विद्वान ख्वाजा हसन निजामी ने कहा था, 'मुसलमानों ने हिंदुओं पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया है इसलिए उनका इस देश पर एकाधिकार है। हिंदुओं में शासन की क्षमता नहीं। मुसलमानों ने शासन किया है, मुसलमान ही शासन करेंगे।'

महात्मा गांधी द्वारा 'भारत के रत्न' और 'परिशुद्ध आत्मा' कहे जाने वाले मौलाना मुहम्मद अली ने गांधीजी के ही बारे में ओछी बातें कही थीं। उन्होंने गांधीजी को मुसलमान बना कर उनका 'उपकार' कर देने का भी दंभ दिखाया था। जबकि तब गांधीजी उन्हीं की राजनीतिक मदद कर रहे थे। स्वतंत्र भारत में भी अनेक नेताओं में वही मानसिकता है। ओवैसी के अलावा भी कई मुस्लिम नेताओं को अपने बल के अलावा बड़े अंतरराष्ट्रीय समुदाय होने का भी गुमान है। एक बार सैयद शहाबुद्दीन ने धमकी दी थी कि 'अरब देशों से कह कर भारत को तेल की आपूर्ति बंद करा देंगे।' लंबे समय से चल रही इस मानसिकता की मूल ग्रंथि ताकत का गुरूर है। दुर्भाग्यवश गांधीजी से लेकर आज तक हमारे नेताओं ने इस पर विचार नहीं किया। या तो वे इसे क्षुद्र बात समझते रहे या मुस्लिम नेताओं की मनुहार कर मित्र बनाने की कोशिश करते रहे। इससे कोई लाभ न हुआ। उलटे दोनों समुदायों के बीच अस्वस्थकर भावनाएं बनती रहीं। ग्रंथि जहां हो वहीं इलाज आवश्यक होता है। उपेक्षा से वह गांठ अपनी जगह जड़ीभूत रहती है। निःसंदेह धमकी का जबाव धमकी से देने की जरूरत नहीं। शांत वैचारिक उत्तर भी एक प्रतिकार है। इतिहास और वर्तमान, दोनों में ताकत की विफलताएं, हिंसा के परिणाम और उसकी सीमाएं देखी जा सकती हैं। ओवैसी और वारिस पठान जैसे मुस्लिम नेता झूठे गुमान में विविध देशों, क्षेत्रों में दूसरों की शांति प्रियता का गलत अर्थ निकालते हैं।

विश्व में स्पेन के अलावा भारत ही है जहां इस्लामी सत्ता बनने के बाद भी हराकर खत्म कर दी गई। यहां 600 साल राज की भी असलियत यह है कि अकबर के पहले कोई मुस्लिम सल्तनत ज्यादा टिक न सकी। अकबर की भी इसलिए टिकी, क्योंकि उसने राजपूतों से सुलह कर ली थी। जैसे ही औरंगजेब ने कट्टरता दिखाई तो जल्द मुगल साम्राज्य ही खत्म हो गया। यह अंग्रेजों के जमने से पहले स्थानीय हिंदू लड़ाकों ने कर दिया था। दुनिया की देखें तो सबसे बड़ा तुर्क-ऑटोमन मुस्लिम साम्राज्य भी भारत के कई हिंदू शासकों के साम्राज्य से छोटा था। ललितादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चोल, विजयनगर आदि कई के राज्य बहुत विस्तृत और सदियों तक शान से बने रहे थे। खुद मुहम्मद साहब द्वारा खड़ा किया गया इस्लामी अरब राज्य जल्द दूसरों द्वारा जीत लिया गया था और फिर 20वीं सदी के चौथे दशक में ही अरब लोग खड़े हो सके थे। तब भी सबसे प्रमुख इस्लामी स्थानों की रक्षा आज अमेरिकी संरक्षण में हो रही है।

तेल की अकूत आर्थिक ताकत मिलने के बाद भी तमाम मुस्लिम देशों की सेनाएं मिल कर एक अमेरिका को नहीं हरा सकतीं। छोटे से इजरायल पर पांच-पांच मुस्लिम देशों का संयुक्त आक्रमण भी दो बार बुरी पराजय में बदला। छह गुनी बड़ी सेना और संसाधन आदि मिल कर भी उस इजरायल का कुछ नहीं बिगाड़ सके, जिसकी पूरी आबादी मात्र बीस लाख थी। पाकिस्तान के भी भारत पर चार-चार हमले हार में बदले। यहां तक कि आधुनिक इतिहास में 1971 में सब से बड़ी मुस्लिम सेना ने एक भारतीय जनरल के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। सारे आधुनिक हथियार, तकनीक गैर-मुसलमानों ने विकसित की और वह उन्हीं के पास हैं। साफ है मुस्लिम नेताओं को पुरानी मानसिकता से बाहर आना चाहिए और यह समझना होगा कि धोखे से किसी ट्रेन, बाजार, बिल्डिंग या ऑफिस पर हमला कर निर्दोष लोगों को मार डालने में कोई वीरता नहीं है। दुनिया के सभ्य देश-समाज उसी धोखे से उत्तर नहीं देते तो इसे उनकी कमजोरी समझना बुद्धिहीनता ही है।

इस्लामी मत का इतिहास ऐसा है कि पाकिस्तान में इतिहास विषय ही वर्जित है, क्योंकि वहां के लोग तुलनात्मक सामाजिक-ऐतिहासिक सच्चाइयों का सामना करने की हालत में नहीं हैं। इसलिए सैनिक या वैचारिक, किसी क्षेत्र में मुस्लिम नेताओं के पास घमंड के लिए कुछ नहीं है। वे अपनी आक्रामक भाषा और जहां-तहां हिंसा का गुमान रखते हैं। वे लोकतांत्रिक देशों में दलीय और वोट राजनीति की कमजोरियों से मिलने वाले लाभ का भी अतिरंजित आकलन करते हैं। उन्हें मध्ययुगीन घमंड छोड़ आत्मावलोकन करना चाहिए। इस्लामी सिद्धांत के अनेक तत्व स्वयं मुस्लिम देशों में छोड़े जा चुके हैं। उनकी अंतरराष्ट्रीयता भी नाम-मात्र बची है। अपने स्थानीय हितों के लिए अनेक मुस्लिम शासक पड़ोसी मुस्लिम देश को तबाह करते रहते हैं। तुर्की-सीरिया, सऊदी अरब-यमन, पाकिस्तान-अफगानिस्तान आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हर हाल में इस्लामी श्रेष्ठता के बदले मानवीय समानता का सिद्धांत सही है। सो भारतीय संसद, जनमत और संविधान का सम्मान करके ही यहां सब उन्नति कर सकते हैं। ताकत का घमंड कहीं नहीं ले जाएगा। सब कुछ मानवीय विवेक से देखना पड़ेगा।

(लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

# खतरनाक रूप लेता काल्पनिक भय

अवधेश कुमार

सीएए के खिलाफ फैले झूठ को खत्म करने के लिए पुलिस के साथ-साथ समाज को भी आगे आना होगा

राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और आगजनी डरावनी और चिंताजनक है। सुनियोजित साजिश के बिना इतने व्यापक पैमाने पर हिंसा नहीं हो सकती। दिल्ली में स्थिति बिगाड़ने के संकेत तभी मिलने आरंभ हो गए थे जब जाफराबाद में सड़क को घेरकर धरना आरंभ किया गया। इससे साफ हो गया था कि जगह-जगह शाहीन बाग पैदा करने की तैयारी हो रही है। जब एक समूह ने इसके विरोध में मौजपुर में धरना दिया तो उस पर पथराव किया गया और वहीं से स्थिति बिगड़ने लगी। शाहीन बाग की तरह ही यहां भी पुलिस की विफलता स्पष्ट है। पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कीजिए तो यह समझते देर नहीं लगेगी कि धरना के समानांतर हिंसा, आगजनी और दंगों की भी तैयारी की गई थी। आखिर इतनी संख्या में लोग पत्थरबाजी कैसे करने लगे?

कुछ बातें तो पहले से ही सामने हैं। एक समूह देश भर में नागरिकता संशोधन कानून, एनपीआर और एनआरसी के नाम पर झूठ और गलतफहमी के द्वारा मुसलमानों के अंदर भय पैदा करने तथा उनके एक बड़े तबके को उकसाने में सफल हो चुका है। यह तथ्य बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है कि नागरिकता कानून से भारत के नागरिकों का कोई संबंध नहीं है। इसी तरह एनपीआर 2010 में हुआ, 2015 में अद्यतन किया गया और यह सामाजिक-आर्थिक जनगणना है जो अब मूल जनगणना का भाग है। एनआरसी पर अभी सरकार के अंदर औपचारिक फैसला नहीं हुआ है। अगर कल फैसला हुआ और उसमें कोई आपत्तिजनक या अस्वीकार्य पहलू होगा तो उसका विरोध किया जाएगा। जो अभी है ही नहीं उसका विरोध करने का कारण क्या हो सकता है? यह प्रश्न और ये तथ्य उनके लिए मायने रखते हैं जिनका उद्देश्य सच समझना हो। जिनका उद्देश्य सरकार के विरुद्ध पूरे समुदाय को भड़काकर स्थिति बिगाड़नी हो उनके लिए इनका कोई अर्थ नहीं है। ये समाज विरोधी, सांप्रदायिक और उपद्रवी शक्तियां हैं जिनके इरादे खतरनाक हैं। दिसंबर की जामिया हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में ही इस तरह की साजिश का विवरण है। जो लोग किसी तरह कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सरकार को बदनाम करने की फिराक में थे उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा भी बड़ा अवसर था। इसमें दोनों तरह की शक्तियां

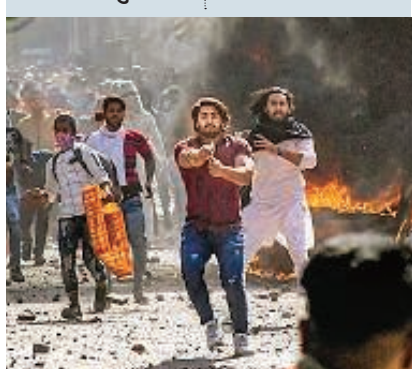

थीं। एक वे जो धरना-प्रदर्शन से ही स्थिति को बिगाड़ देना चाहते थे तथा दूसरे वे जो हिंसा द्वारा ऐसा करने की तैयारी में थे। वे चाहते थे कि किसी तरह दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक स्थिति इतनी बिगाड़ दी जाए जिससे ट्रंप की नजर तो जाए ही, उनको कवर कर रही अंतरराष्ट्रीय मीडिया के फोकस में भी विरोध आ जाए। अलीगढ़ में अशांति पैदा करने की कोशिशें पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से विफल कर दी गईं, किंतु दिल्ली में ऐसा नहीं हो सका।

समझने की आवश्यकता है कि शाहीन बाग का जो धरना सामने दिख रहा है उसके पीछे कई प्रकार के शरारती दिमाग और खतरनाक विचार हैं। पूरे देश ने वह वीडियो देखा जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा वार्ताकार नियुक्त किए जाने के साथ तीस्ता सीतलवाड़ अपने साथियों के साथ वहां महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही थीं कि आपको किस सवाल का क्या जवाब देना है और अपनी ओर से क्या सवाल करना है या शर्तें रखनी हैं। उस वीडियो ने शाहीन बाग के पीछे छिपे चेहरे को उजागर कर दिया था। यह सीधे-सीधे वार्ताकारों को विफल करने की साजिश थी।

जो लोग अभी भी सीएए के विरोध के नाम पर हो रहे विरोध को संविधान बचाने से लेकर लोकतांत्रिक बता रहे हैं उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि अब क्या होगा जिसके बाद आपका भ्रम टूटेगा? उच्चतम न्यायालय की एक पीठ नागरिकता संशोधन कानून पर 160 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अगर संविधान बचाने का विचार हो तो कायदे से इसके संवैधानिक-गैर संवैधानिक होने का फैसला न्यायालय पर छोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जब उद्देश्य खतरनाक हो तो वे क्यों ऐसा करेंगे? उनको केवल आग लगाना और उसका विस्तार करना है ताकि केंद्र सरकार के लिए विकट स्थिति पैदा हो जाए। इस आग को रोकना है तो तथाकथित मानवाधिकारवादियों तथा मीडिया के एक वर्ग की निंदा का जोखिम उठाते हुए भी कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग खाली करने के लिए किसी न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं। सड़क घेरना गैर कानूनी यानी आपराधिक कदम है और पुलिस को पूरा अधिकार इसके खिलाफ कार्रवाई करने का है। अगर दिल्ली को संभालना है तथा देश में इन खतरनाक साजिशों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है तो फिर पुलिस प्रशासन को अपनी भूमिका कठोरता से निभानी होगी, किंतु हमें यह भी समझना होगा कि यह एक वैचारिक संघर्ष में भी परिणत हो चुका है। आपने कई भाषण सुने होंगे जिनमें कहा जा रहा है तीन तलाक के खिलाफ कानून बना और हम चुप रहे। 370 हट गया हमने कुछ नहीं किया। अयोध्या का फैसला आ गया हम खामोश बैठे रहे। अब नागरिकता कानून बन गया। आगे एनआरसी होगा। इस तरह मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि वर्तमान सरकार उनकी विरोधी है और अपना वजूद बचाना है तो उठो लड़ो। इस तरह का झूठ फैला दिया जाए तो अलग-अलग तरह के तत्व अपने-अपने तरीके से विरोध करने लगते हैं। इसका सामना करने के लिए समाज को आगे आना होगा। झूठ और षड्यंत्र को खत्म करने के लिए अहिंसक प्रदर्शनों व प्रचारों द्वारा सच को प्रभावी तरीके से रखना होगा। इसमें सभी मजहब के लोगों का साथ लिया जाना चाहिए। अगर शाहीन बाग के विरोध में अहिंसक तरीके से बड़े धरने आयोजित होते तो स्थिति दूसरी होती।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

## अन्न का प्रभाव

मनुष्य के जीवन में उसके खानपान एवं रहन-सहन का सीधा असर पड़ता है। धर्मग्रंथों में उल्लिखित 'यथा अन्न तथा मन' के विचार को चिकित्सक तक मानते हैं। शरीर में कोई बीमारी आने पर खानपान में परहेज की सलाह दी जाती है। खानपान का संबंध शरीर से ही नहीं मन से भी जुड़ा हुआ है। इसका उल्लेख गीता-उपदेश में भी है। युद्ध न करने का मंतव्य प्रकट करने वाले अर्जुन के मन को बदलने के लिए श्रीकृष्ण उचित आहार संबंधित उपदेश भी देते है। श्रीकृष्ण सात्विक, राजस और तामस आहार की व्याख्या करते हैं तथा उससे पड़ने वाले सत-रज-तम गुणों का भी मतलब बताते हैं।

श्रीकृष्ण की इस व्याख्या में गहरे भाव छिपे हैं। सात्विक आहार से व्यक्ति का मन मजबूत बनता है। चिकित्सक तक अल्प भोजन की सलाह देते हैं, क्योंकि ज्यादा भोजन से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। बहुत से लोग समुचित तरीके से भोजन न करने से शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से अस्वस्थ देखे जाते हैं। व्यक्ति का आहार के रूप में जो भी खानपान है वह कितना सात्विक है, यह कोई और जाने या न जाने, वह खुद तो जानता है। छल, धोखा, ठगी, पराए व्यक्ति के हिस्से से अर्जित धन का उपयोग महाघातक होता है। प्रायः लोग कहते हैं कि वे तथा उनके घर के लोग तो बहुत सादा भोजन करते हैं फिर भी उनके घर कोई न कोई बीमार रहता है। इसका आशय भोजन में सात्विकता नहीं है। सात्विक एवं परिश्रम से अर्जित धन के उपभोग से शरीर ही नहीं आत्मबल भी मजबूत होता है। परिश्रम करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।

स्पष्ट है कि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। दूषित तरीके से अर्जित अन्न से मन भी दूषित होता है। फिर मन अनियंत्रित भी हो जाता है। केवल सकारात्मक तरीके से अर्जित धन से आहार किया जाय तो जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में सकारात्मक उपलब्धियां भी आएंगी।

सलिल पांडेय

# तलाक का बढ़ता प्रचलन

सुधीर कुमार

दहेज और तलाक दो ऐसी बुराइयां हैं, जिसने विवाह जैसे पवित्र बंधन को मैला कर दिया है

हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जब कहा कि शिक्षा और संपन्नता के कारण तलाक के मामले बढ़े हैं, तो उसके समर्थन और विरोध में कई तरह की बातें होने लगीं। हालांकि बयान पर बहस करने से ज्यादा जरूरी है, तलाक के बढ़ते प्रचलन को रोकना, जो परिवार और समाज में बिखराव उत्पन्न कर रहा है। एकाध दशक पहले प्रति हजार दंपती में केवल एक दंपती के बीच तलाक का मामला सामने आता था, जबकि अब तेरह दंपती के बीच तलाक हो रहा है। पिछली जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश तलाक के मामले में शीर्ष पांच राज्य हैं।

देश में तलाक के मामलों का निरंतर बढ़ना एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। परिवार समाज की श्रेष्ठ ईकाई है, लेकिन तलाक की वजह से यह धराशायी हो जाती है। भारतीय समाज में विवाह को पवित्र बंधन माना गया है। दंपती एक-दूसरे के साथ सुख-दुख में सहयोगी बनकर ताउम्र जीवन बीताने का संकल्प लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि विवाह दंपती को जन्म-जन्मांतर का साथ निभाने का अवसर प्रदान करता है। पति-पत्नी किसी परिवार के आधार स्तंभ होते हैं, जिनके आपसी तालमेल के बिना परिवार और समाज में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसके बावजूद हर धर्म के दंपतियों में तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्यों तलाक के जरिये आने वाली पीढ़ियों को हम असभ्य पाठ की पतित शिक्षा दे रहे हैं, जो मानव समाज को तोड़ने वाला है?

दहेज और तलाक दो ऐसी बुराइयां हैं, जिसने विवाह जैसे पवित्र बंधन को मैला कर दिया है। दहेज सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। वहीं तलाक के बढ़ते प्रचलन से समाज विघटित होता जा रहा है। एक खुशहाल दांपत्य जीवन तलाक के बाद बदहाली की गर्त में चला जाता है, लेकिन क्या पति-पत्नी अपने बीच पैदा हो रहे अविश्वास को भरोसे में नहीं बदल सकते? क्या कोई एक पक्ष समझौता कर परिवार को टूटने-बिखरने से बचाने की पहल नहीं कर सकता? तलाक की वजह से संबंधित बच्चों की ढंग से परवरिश भी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसे अपने माता-पिता दोनों का प्यार ही नसीब नहीं हो पाता है। तलाक का निर्णय मनोवैज्ञानिक रूप से उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाधा पहुंचाती है। तलाक की वजह से एक बसा-बसाया परिवार पलभर में टूटकर बिखर जाता है। किसी दंपती के मध्य तलाक की नौबत ही क्यों आती है, इस पर विमर्श की दरकार है। पति-पत्नी के बीच पैदा हो रहे अविश्वास एवं गिले-शिकवे को भरोसे में बदला जाना चाहिए। पर कैसे? दंपती के बीच संवाद-शून्यता की स्थिति ही आपसी रिश्ते में दरार पैदा करती है। एक-दूसरे से अलग होने की प्रक्रिया तब चरमोत्कर्ष पर रहती है, जब दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता। यह अकड़न एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की दरार को बढ़ाता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## गांधी के देश में हिंसा शर्मनाक

गांधी के बताए रास्ते की अनदेखी शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने महात्मा गांधी की शिक्षा का हर किसी को अनुसरण करने की सलाह दी है, खासतौर पर देश के युवा वर्ग को। कितने दुर्भाग्य की बात है कि गांधी के ही देश में लोग उनकी अहिंसा के मंत्र को भूल गए हैं। दिल्ली में सीएए के विरोध में भड़की हिंसा इसका स्पष्ट उदाहरण है। यह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। महात्मा गांधी की तीन बातें देश-दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर अग्रसर कर सकती हैं। वे हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा न सुनो। आज अगर हरेक भारतीय, चाहे वह सत्ताधारी हो, राजनेता या अभिनेता या फिर आम आदमी हो, महात्मा गांधी की बातों का अनुसरण करे तो देश में हिंसा और भेदभाव खत्म हो जाएंगे, राजनीति के स्तर में सुधार हो जाएगा और पर्यावरण संभालने के प्रति लोग गंभीर हो जाएंगे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

## हैप्पीनेस कक्षाएं

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस कक्षाओं का शुरू किया जाना सराहनीय प्रयास है। इससे बच्चों की सीखने-समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चों का मन खुश रहता है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पहले जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे वे अब इन कक्षाओं की वजह से ठीक से पढ़ने लगे हैं। उन्हें पाठ याद होने लगे हैं। इसके अलावा भी स्कूलों की दशा में सुधार किए जाने से भी पहले जहां सरकारी स्कूलों के नाम पर लोग नाक भौंह सिकोड़ते थे वे आज इन स्कूलों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है अब पैसे वाले लोग भी अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। इन स्कूलों में चल रही हैप्पीनेस कक्षाओं की चर्चा विदेशों तक में पहुंच गई है, तभी तो भारत यात्रा पर आए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया ऐसी कक्षा को देखने के लिए एक कक्षा में गईं। इन कक्षाओं को देश के सभी स्कूलों में शुरू किया जाना चाहिए।

श्रीनिवास यादव, गाजियाबाद

## देशद्रोही नारे के पीछे कौन

आजकल कोई भी देश के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है। यहां तक कि देशद्रोही नारे भी लगाए जा रहे हैं। अभी हाल की एक घटना है, जहां एक लड़की ने देश विरोधी बात अपने फेसबुक पर लिखी थी, जिसे अब गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिर ये कौन लोग हैं, जो ऐसा कृत्य करते हैं या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है, कहा नही जा सकता। देशद्रोह की बात करने वालों को कतई रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

श्रीराम, रावता मोड़, नई दिल्ली

## प्रदर्शन खत्म हो

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में महिलाओं और बच्चों की आड़ लेकर प्रदर्शन कर आम लोगों को परेशान करना कितना उचित है? दूसरे न सरकार की बात मानना और न कानून को समझना व न ही कोर्ट के आदेश से सरकार द्वारा बात करने के लिए भेजे गए प्रतिनिधियों की बात को तवज्जो देना। बढते जा रहे प्रदर्शन से आम लोगों की बढ़ती दिक्कतों के मद्देनजर सरकार पर्दे के पीछे से प्रदर्शन को शह देने वालों पर सख्ती से पेश आए और हर हाल में प्रदर्शन खत्म करवाए।

mahesh_nenava@yahoo.com

## हिंसक प्रदर्शन अनुचित

शाहीन बाग का प्रदर्शन जोकि अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी खास आपत्ति नहीं जताई है और सड़क खुलवाने के लिए वार्ताकारों को नियुक्त किया है, जोकि सराहनीय प्रयास है। किन्तु दूसरी ओर जाफराबाद जैसी हिंसक घटनाएं किसी भी तरह से उचित नहीं कहीं जा सकती हैं। गांधी और बुद्ध के इस देश में हिंसा से किसी समस्या का समाधान संभव नहीं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है किंतु हिंसक विरोध उचित नहीं है।

डा. मनोज कुमार

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

**50** करोड़ के आसपास है स्मार्टफोन धारकों की संख्या देश भर में, मार्केट रिसर्च फर्म टेक एआरसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक। वर्ष 2022 तक यह आंकड़ा 85 करोड़ को पार कर सकता है।



आजकल

लालजी जायसवाल
शोध छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

# अभिव्यक्ति की आजादी और सोशल मीडिया

**इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को निश्चित तौर पर आसान बनाने में व्यापक मदद की है। धीरे-धीरे इनका जुड़ाव हमारी अभिव्यक्ति से भी होता गया। इन दोनों की मदद से एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को अपनी बात कहने या फिर अपनी विचारधारा को प्रसारित करने का आसान जरिया मिल गया। लेकिन आज सोशल मीडिया के तौर पर विकसित हुआ एक नया मीडिया अभिव्यक्ति के मामले में बेलगाम होता जा रहा है। अब तक इसके लिए मजबूत नियामक की व्यवस्था नहीं होने और भ्रामक कंटेंट व वीडियो आदि की सत्यता की तत्काल पुष्टि से संबंधित जागरुकता के अभाव में ऐसी अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं जो समाज के लिए विघटनकारी हैं**

प्रतीकात्मक।

इंटरनेट ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज भारत के लोगों की जीवन-रेखा बन चुकी है। यह न केवल सूचनाएं प्राप्त करने और सोशल मीडिया के साथ-साथ संचार का साधन है, बल्कि उससे भी अधिक बड़ी अभिव्यक्ति के आजादी की सहायक है। आज के समय में वैचारिक और सूचना के आदान-प्रदान के लिए समुदायों और समाज के विभिन्न समूहों को आपस में जोड़ने हेतु सोशल मीडिया का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। वाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि कुछ लोकप्रिय साधन हैं जिन मंचों पर कुछ ऐसे कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं, जो सरकार, समाज और मीडिया पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से समय-समय पर उनकी आलोचना में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे कार्यकर्ता किसी घटना से जुड़कर उस पर तुरंत सुधारात्मक रवैया, न्याय या निष्पक्षता के लिए प्रतिकार, प्रतिशोध और दंड जैसे साधनों को अपनाए जाने पर जोर देने लगते हैं।

वैसे तो मीडिया सूचनाओं तथा आंकड़ों को संरक्षित व संप्रेषित करने का उपकरण है। मीडिया का कार्य सूचनाओं का एकत्रीकरण करना तथा उससे सभी को पारदर्शिता पूर्ण अवगत कराना है। सरकारी क्रियाकलापों तथा सामाजिक क्रियाकलापों को उजागर करना भी मीडिया का कार्य है। वैसे तो मीडिया सरकार को कार्यों के प्रति तथा उनके द्वारा किए गए वादों के प्रति कटिबद्धता को दिखाने के लिए मजबूर करती ही है, साथ ही उनके द्वारा किए गए सभी आधे-अधूरे कार्यों की सच्चाई को भी जनता तक पहुंचाती है। मीडिया का सबसे बड़ा योगदान लोकतंत्र में होता है, जो प्रायः विकास को प्रेरित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा बड़ा आधार स्तंभ होता है।

**हथियार की भांति इस्तेमाल हो रहा सोशल मीडिया :** मीडिया की ही एक शाखा सोशल मीडिया है जो आज टेक्नोलॉजी के युग में अलग-अलग रूपों में हमारे सामने आ रही है। आज फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि ऐसे माध्यम हैं जो लोगों को एक-दूसरे के मित्र तो बनाते ही हैं, साथ में इसकी लत लोगों में इस कदर लग जाती है कि फिर वो बच्चा हो या बूढ़ा या जवान सभी उसमें इस कदर चिपके होते हैं, जैसे गुड़ में मक्खियां। बहरहाल, हमारे लोकतंत्र ने हमें एक आजादी दी है, वो है अभिव्यक्ति की। हम अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया एक जरिया है जहां लोग अपने विचार रख सकते हैं, पर आजकल लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, लोगों का अपशब्द कहना, उन पर फिकरे कसना, उनका मजाक उड़ाना, ये सब आम हो गया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज इंसान अभिव्यक्ति की आजादी से कहीं आगे बढ़कर करता जा रहा है, जो एक खतरा बन चुका है। आज सोशल मीडिया से मित्रता की संधि करते-करते लोग उस पराकाष्ठा को भी पार कर गए हैं जो एक दूसरे के प्राण तक लेने से नहीं कतराते हैं।

**वायरल कंटेंट और फैक्ट चेक :** हालांकि आज ऐसे तमाम निजी टीवी चैनल आदि मौजूद हैं जो वायरल वीडियो को और वायरल करते रहते हैं, तो वहीं कुछ टीवी चैनल साइबर पुलिस का भी कार्य करते हैं और वायरल वीडियो या कंटेंट की सत्यता की पड़ताल कर लोगों को वास्तविकता से अवगत कराते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा चुका है कि वह लोगों को लगातार नुकसान ही पहुंचा रहा है। हमें संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, जिसमें लोगों के जानमाल का नुकसान स्तंभित होता हो।

**संवेदनशील मामलों में सोच-समझकर लें निर्णय :** झूठे मुद्दे में मॉब लिंचिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं जिस कारण कई राज्यों में इसके लिए एक कठोर कानून बनाया गया है। इसमें तमाम ऐसे लोग भीड़ का शिकार होते पाए गए हैं जो निर्दोष थे। दरअसल सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उछाला जाता है कि बच्चा चोर फलां रास्ते से जा रहा है और लोग इकट्ठा होकर उसे पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं। ऐसी घटनाएं प्रायः आपसी द्वेष के कारण भी घटी हैं। भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए जहां तक कानून बनाने की बात है, तो वह सही है। परंतु केवल कानून इस पर लगाम नहीं लगा सकता, क्योंकि जहां लोगों की प्रवृत्ति ही दूषित हो, और जहां घृणा को उकसाने वाला मौन समर्थन मौजूद हो, वहां इसे कानून से रोकना मुश्किल हो जाता है। पिछले वर्षों के दौरान ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं जिनमें मॉब लिंचिंग के रूप में कई लोगों को सार्वजनिक रूप से मारा गया और भीड़ चुपचाप खड़ी देखती रही। यहां तो जांच-पड़ताल करने वाले भी मिले हुए हैं, और उल्टे दोष पीड़ित पर ही लगा देते हैं।

**अफवाह के प्रसार पर लगाम :** इसी प्रकार फेसबुक और ट्विटर आदि पर बीते वर्ष के लोकसभा चुनाव के दौरान एक मुद्दा उठा कि अगर किसी पोलिंग बूथ पर एक निश्चित फीसद से ज्यादा टेंडर वोट रिकॉर्ड हुआ तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 की धारा 49ए के तहत दोबारा चुनाव होगा, लेकिन इस मामले में वास्तविकता यह है कि इन दोनों अधिनियमों में धारा 49ए का प्रावधान है ही नहीं। वैसे भी भारत की जनता का नागरिक शास्त्र इतना कमजोर है कि उसे पता भी नहीं चल पाता कि वास्तव में 49ए है या नहीं। शायद इसी कारण जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए के हटने के बाद वहां का नेटवर्किंग सिस्टम बंद कर दिया गया ताकि देश में फैलने वाली किसी भी संभावित अफवाह को रोका जा सके।

हमें यह समझना होगा कि एक स्वार्थी नागरिक की भांति किसी घटना को तर्क की कसौटी पर कसे बिना संवेदनशील मामलों या घटनाओं के संदर्भ में तत्काल किसी निर्णय पर पहुंचने से बचना चाहिए। पहले किसी भी घटना का तार्किक मूल्यांकन कर तभी विश्वास करना चाहिए अथवा किसी विशेषज्ञ की समुचित राय लेनी चाहिए।

**दोधारी तलवार की भांति है सोशल मीडिया :** सोशल मीडिया दोधारी तलवार की तरह है जो दोनों ओर से वार करती है। अतः इसकी म्यान को मजबूत करने यानी अपनी तार्किकता को मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना करते हुए संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समुचित उपयोग करना होगा।

चुनाव आयोग को चाहिए कि वह नेताओं के भाषणों में घृणा तत्व को चुनावी अपराध की श्रेणी में रखे। सोशल मीडिया पर तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत की गई फोटो या खबरों का स्रोत और पहचान प्रकट की जाए। सरकार को ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए, जो सोशल मीडिया जैसे मंचों का दुरुपयोग करके समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। तभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी हो पाएगी, और भीड़ द्वारा हिंसा से कई निर्दोष बच जाएंगे। भारत को मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों की तर्ज पर कड़े और त्वरित दंड का विधान करना चाहिए। मलेशिया में इसके लिए दोषी व्यक्ति को छह वर्षों की सजा देने का प्रावधान है, जबकि थाईलैंड में सात साल की सजा का प्रावधान है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में गलत खबर के जरिये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति को सजा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान है। इसके अलावा सिंगापुर, चीन, फिलीपींस आदि देशों में भी गलत खबरों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं।

## जानें अफवाह और सच का फर्क

बीते वर्षों के दौरान स्मार्टफोन और इंटरनेट के तीव्र प्रसार के बाद से सोशल मीडिया के रूप में मीडिया का एक नया अवतार सामने आया है। हालांकि अब यह सोशल मीडिया के बजाय शोषण मीडिया का रूप धारण करता जा रहा है। आज यह मीडिया लोगों का न केवल मानसिक रूप से शोषण कर रहा है, बल्कि धन आदि के लालच की वजह से लोगों का शारीरिक शोषण भी कर रहा है। आज लोगों के उत्पीड़न का अभिकरण सोशल मीडिया ही है फिर वह चाहे दुष्कर्म की घटनाएं हों या फिर अवैध धन की मांग हो।

मार्केट रिसर्च फर्म टेक एआसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। यह संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आगामी दो वर्षों में यह संख्या 85 करोड़ को पार कर सकती है। इनमें से अधिकांश लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि विभिन्न राजनीतिक दल भी आज अपना प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से ही अधिक से अधिक कर रहे हैं। राजनीति में इसका उपयोग आज सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में सामने आ रहा है। आज चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसी बाबत सभी राजनीतिक दलों की आज साइबर सेल भी अस्तित्व में है जो राजनीतिक दलों के प्रचार का कार्य करती है तथा उनके झूठे मुद्दों को भी फैलाती रहती है। इससे जनता गुमराह होती है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अनेक राजनीतिक दलों के साइबर सेल तथा सोशल मीडिया की नकारात्मक भूमिका रही है। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक दलों या अन्य संगठनों द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही है, किंतु झूठे मुद्दे उठाना तथा सामाजिक द्वेष फैलाना सही नहीं है। शायद यही कारण है कि अनेक सोशल मीडिया साइट लोगों द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्रियों पर निगाह रखते हैं और अवांछित कंटेंट और वीडियो आदि को नष्ट कर देते हैं।

दरअसल अधिकतर व्यक्ति बिना सोचे-समझे ही किसी पोस्ट को साझा कर देते हैं। जैसाकि वाट्सएप पर कई सोशल ग्रुप बने होते हैं। अक्सर ये ग्रुप किसी विचारधारा से प्रेरित होते हैं या किसी खास मकसद से बनाए जाते हैं। अगर यह कहा जाए कि अधिकतर ग्रुप राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं तो गलत नहीं होगा। यहां बिना किसी रोक-टोक के धड़ल्ले से फेक न्यूज बनाए और साझा किए जाते हैं। जाहिर है ये न्यूज किसी खास भावना या मकसद से तैयार किए जाते होंगे। फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि सामाजिक समरसता कायम रखने के लिए सोशल मीडिया एक चुनौती के रूप में उभर रहा है।

खरी-खरी

## अपना टाइम आएगा

अतुल कनक

उम्मीद तो अपुन को भी है कि अपना टाइम आएगा, लेकिन वो छप्पर फाड़कर आएगा या किसी मंदिर का घंटा पकड़कर आएगा- इस बारे में कंफ्यूजन है। दरअसल जिन लोगों को अपना टाइम आने का इंतजार रहता है, वे उन लोगों से अलग होते हैं जो इस तरह के इंतजारों को प्रोत्साहित करने के लिए ईनाम दिया करते हैं। सवाल है कि वे लोग कौन हैं, जिन्हें अपना टाइम आने का इंतजार है?

लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ होती रहे तो लोगों में यह खुशी बनी रहती है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। कई लोग तो इस गलतफहमी में ही लोकतंत्र से खिलवाड़ करते रहते हैं कि उनके ऐसा करने भर से लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। वे नारे लगाते हैं- 'अपना टाइम आएगा' और बेचारा टाइम भीड़ की धक्का-मुक्की का शिकार होकर किसी पतली गली से कट लेने को मजबूर हो जाता है। तब तक हवा में गूंजते बोल 'अपना टाइम आएगा' धकेले गए व्यक्ति को नया विश्वास देते हैं कि चिंता मत कर 'अपना भी टाइम आएगा।'

पिछले दिनों एक समारोह में एक सज्जन मिले। वे लगातार कह रहे थे कि 'अपना टाइम आएगा।' मुझे लगा कि टाइम उनके बेटे का नाम होगा, जो उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ गया है। बुजुर्ग माता-पिता को हमेशा उम्मीद रहती है कि उनका बेटा एक दिन लौटकर अवश्य आएगा। मुझे यह भी लगा कि कहीं वे अपने उधार दिए पैसे को याद करके खुद को तसल्ली तो नहीं दे रहे कि पैसा वापस आएगा? क्योंकि आखिर समय ही धन है। मैंने उन बुजुर्ग से जानना चाहा कि वे यह गाना गाकर किसके आगमन की उम्मीदें कर रहे हैं। बुजुर्ग चिढ़ गए। उनके तेवर अचानक इतने आक्रामक हो गए कि मुझे अपने पिट जाने का टाइम आता दिखा। मैं तुरंत ही वहां से खिसक लिया।

कुछ लोग अपने टाइम को बुलाने के लिए धरने पर बैठ जाते हैं तो कुछ लोग किसी की पीठ पर डंडे मारने का बयान देने का टोटका आजमाते हैं। प्लेटफॉर्म पर आयी रेल की तरह टाइम सरकता रहता है और अपने डिब्बे के इंतजार में खड़े लोग प्रतीक्षा करते हैं कि अपना टाइम आएगा। टाइम सबका आता है। कुछ लोग धक्का-मुक्की करके डिब्बे में चढ़ जाते हैं, कुछ को तो भीड़ ही नीचे धकेल देती है।

ट्वीट-ट्वीट

माफ कीजिए मी लॉर्ड। ये आपकी अवमानना हो सकती है, पर दिल्ली हिंसा में एक अंगुली आप पर भी उठती है। एक प्रदर्शन के लिए वार्ताकारों की फौज रोज-रोज मनाने जाए, तो नए-नए प्रदर्शन क्यों न पनपें?

श्वेता सिंह@SwetaSinghAT

डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को देखने का यह दृष्टिकोण क्षुद्र है कि इस पर कितने रुपये खर्च हुए। यह भारत-अमेरिका संबंधों के लिए किया गया ऐसा निवेश है जो आने वाले वर्षों में कई गुना अधिक फल देगा।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

सरकार ने साफ किया है कि एनआरसी की कोई योजना नहीं। पहले इसे लेकर भ्रम था। मैंने खुद एनआरसी की आलोचना की, लेकिन अब जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी तैयारी नहीं है, तब फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम शरणार्थियों के लिए शरण पाने का एक जरिया भर रह गया है। उसके खिलाफ हिंसक विरोध की आवश्यकता नहीं है।

चेतन भगत@chetan_bhagat

जो लोग इस ताक में थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ उल्टी टिप्पणी कर देंगे उन्हें उनकी प्रेस कांफ्रेंस से बड़ा झटका लगा होगा।

अखिलेश आनंद@akhileshanandd

छत्तीसगढ़ डायरी

कमलेश पांडेय
स्टेट डेस्क इंचार्ज, छत्तीसगढ़

# धान पर सियासत के बीच ठंडे बस्ते में सीएए

छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों दिलचस्प नजारे दिखे। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू न करने की बात कहते रहे, लेकिन अब सरकार ठिठकी नजर आ रही है। इसे रणनीतिक कदम भी बताया जा रहा है। एनपीआर के लिए राज्य शासन पहले ही अधिसूचना जारी कर चुका है। सरकार में मंत्रियों को ही नहीं पता कि एनपीआर पर उनके कदम अमल की ओर बढ़ चुके हैं। सरकार अब इसे विधानसभा पटल पर ले तो जाना चाहती है, पर बदली रणनीति के तहत।

दरअसल सरकार चाहती थी कि सोमवार से शुरू हुए बजट सत्र में राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण में इसे शामिल किया जाए। सत्र से दो दिन पहले तैयार अभिभाषण ड्राफ्ट को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी राजभवन पहुंचे तो राजभवन अफसरों ने सीएए और एनपीआर के जिक्र पर आपत्ति कर दी। राज्यपाल ने भी सरकार से इस मसले को उनके अभिभाषण में शामिल न करने का आग्रह किया। सरकार यहीं से रणनीति बदलती दिखी। सरकार भी नहीं चाहती कि अनुपूरक बजट और तीन मार्च को पेश किए जाने वाले नए वित्तीय वर्ष के बजट से पहले सदन से सड़क तक कोई बड़ा बखेड़ा न खड़ा हो। सरकार पहले ही धान की सियासत में उलझी हुई है। धान के कटोरे में सियासी उबाल चरम पर है। धान खरीद की तारीख बीत चुकी है। किसान आस्तीन चढ़ाए सड़कों पर उतर रहे हैं। भाजपा बिना समय गंवाए इस मौके को लपक चुकी है। किसानों के साथ भाजपाई भी सड़क जाम करते देखे जा रहे हैं। कांग्रेस इसलिए भी बैकफुट पर दिख रही है कि धान खरीद के अंतिम दिनों में जब बारदाना की कमी से लेकर टोकन जारी होने तक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे, तब प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल अमेरिका की यात्रा पर थे। घरेलू पिच पर मुखिया की गैर मौजूदगी ने भाजपा को

विधानसभा के बजट सत्र में अभिभाषण देने पहुंचीं राज्यपाल अनुसुईया उइके व अन्य नेता। फाइल फोटो

फ्री-हिट खेलने के मौका दिया। सीएम की अमेरिकी यात्रा भी धान की सियासत में खींच ली गई। किसानों की नाराजगी का ठीकरा सरकार की बदइंतजामी और वादाखिलाफी पर फोड़ा जा रहा। भाजपा सीएम की विदेश यात्रा पर सवाल दाग रही है। सरकार इसी कारण बजट पेश करने तक सीएए और एनपीआर के मामले पर ठिठकी दिख रही है। सरकार के सूत्र ये संकेत भी दे रहे हैं कि बजट पास हो जाने के बाद सीएए व एनपीआर को सदन में लाया जाएगा। भूपेश कैबिनेट पहले ही सीएए को वापस लेने की मांग का प्रस्ताव पास कर चुकी है। इसे विधानसभा पटल पर भी लाए जाने की घोषणा हो चुकी है।

फिलहाल अभी सियासत की धुरी धान है। धान हमेशा से छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में रहा है। डॉ. रमन सिंह के हाथ से 15 वर्षों की सत्ता छीन कर कांग्रेस को सौंपने में धान किसानों की बड़ी भूमिका रही है। वही धान किसान अब कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं। भाजपा के रणनीतिकारों को समझ में आ गया है कि राज्य में चुनाव दर चुनाव पराजय से उबरना है तो सड़क से सदन तक के संघर्ष में किसानों को साधे रखना है। यही वजह है कि धान खरीद की अंतिम तिथि 20 फरवरी को भाजपा नेता राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। खरीद तिथि 15 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। आखिरी दिनों में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सामने जरूर आए। उन्होंने दावा किया कि किसान सरकार के साथ है, सड़क पर उतरने वाले मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन प्रायोजित था। उनका यह कहना भाजपा को और हमलावर होने का मौका दे गया। सरकार दावा कर रही है कि पिछली सरकार के मुकाबले इस बार ढाई लाख अधिक किसानों ने धान बेचा है। रिकार्ड 82 लाख मीट्रिक धान की खरीद राज्य के इतिहास में पहली बार हुई। इसके बाद भी सदन में हंगामे की पटकथा तैयार है। मुद्दा धान और किसान ही हैं। हालांकि कांग्रेसी रणनीतिकारों ने भी तैयारी कर ली है। घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए मजबूर होने वाली सरकार किसानों को 25 सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस के साथ देने पर अडिग है।

सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि किसानों को भड़काने की भाजपा की साजिश सफल नहीं हो पाएगी। सरकार अपने वादे से कतई पीछे नहीं हटेगी। केंद्र सरकार की किसान सम्मान योजना की भांति ही समर्थन मूल्य के बाद शेष बची राशि को विशेष बजट प्रावधान से किसानों के खाते में डाला जाएगा। तीन मार्च को नए वित्तीय वर्ष का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे। संभावना है कि बजट में धान किसानों के बोनस राशि का प्रावधान किया जाएगा। सबकी निगाह अब बजट सत्र पर ही है। समय कम मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विदेश से लौटते ही स्वयं अब बजट पर एक्सरसाइज में जुटे हैं।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या आप शशि थरूर के इस कथन से सहमत हैं कि जनता में कांग्रेस की छवि एक भटकी हुई पार्टी की बनती जा रही है?

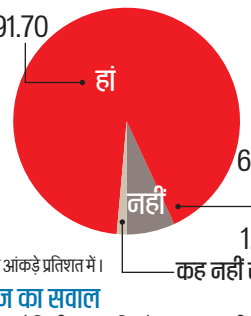

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**

क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने में कामयाब रही?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

घर में जब परदेश से आया हो मेहमान,
करें उपद्रव उस समय घर के ही शैतान।
घर के ही शैतान रार जब भीषण ठानें,
तो कैसे श्रीमान उन्हें हम अपना मानें?
आग लगे 'शाहीन' तुम्हारे ऐसे पर में,
जिसे न भाती शांति स्वयं अपने ही घर में।

– ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

वरुण आनंद
varun.anand@nda.jagran.com

# अराजकता की प्रयोगशाला

**प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी माह शाहीनबाग को एक प्रयोग की संज्ञा दी थी। तब इसे चुनाव प्रचार का हिस्सा मानकर तीखी टिप्पणियां हुईं, लेकिन आज जगह-जगह उठते अराजकता के स्वर यह साफ कर रहे हैं कि अब इस प्रयोग को पूरे देश में विस्तारित किया जा रहा है**

इतिहास स्वयं को दोहराता है। वह पहली बार आपके लिए सबक के रूप में होता है और दूसरी बार सबक से कुछ ना सीख पाने की मूर्खता के प्रतिफल के रूप में सामने आता है। पिछले करीब दो माह से शाहीनबाग में जो कुछ हो रहा था, उस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेतावनी दे रहे थे, लेकिन तथाकथित उदारवादियों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण माना और उनमें से कई तो गाहेबगाहे राष्ट्रीय मंचों और टीवी चैनलों पर हो रही बहसों में अभिभावकों की भांति इन उपद्रवियों को बचाते-दुलराते नजर आए, उस बिगड़ैल बच्चे की तरह, जिसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती रहे और बाद में अंजाम उसके स्वच्छंद अपराधी होने के रूप में सामने आए। वैसा ही अब इस प्रयोग के परिणाम सामने आने पर होता दिख रहा है। पड़ोसियों से मिल रहे ताने पुलिस की एफआइआर में बदलने लगें और तब भी अभिभावक न चेतें तो इसे आपराधिक प्रवृत्ति के साथ ही परवरिश में खोट कहा जा सकता है। शाहीनबाग का उद्दंड प्रयोग इसी राह पर चल पड़ा है।

जगह जगह से दंगे भड़कने और पत्थरबाजी व आगजनी की खबरें आ रही हैं। दिल्ली के उत्तरपूर्वी इलाके के जाफराबाद को दूसरा शाहीनबाग बनाए जाने की तैयारी है। अलीगढ़ में भी लोग इस मकसद से धरने पर बैठे। जाफराबाद में हुई व्यापक हिंसा के दौरान मंगलवार तक मरने वालों की संख्या दहाई में पहुंच चुकी थी। इन दंगों में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की भी हत्या कर दी गई। ये खबरें, और वह भी तब, जब पूरा भारत दुनिया की महाशक्ति के तौर पर पहचाने जाने वाले देश के राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त था, यह टाइमिंग संदेह करने को मजबूर करती है कि सामने से पत्थर फेक रही भीड़ के पीछे कोई और है। ये वही लोग हैं जो मंच से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाली छात्रा 'अमूल्या' के पीछे हैं। अमूल्या ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वह सिर्फ एक चेहरा है। उसे कब, कहां और क्या कहना है ये कोई और तय करता है। ये कोई और कौन हैं? इन्हें पहचानने के लिए दूरदर्शिता की जरूरत है।

**अलगाववादियों की हरकतों से बढ़ती चिंता :** हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बताया था। यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का एक उदाहरण ही था कि उन्होंने दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मंच से शाहीनबाग को एक प्रयोग कहा था। तब भी उनके इस बयान को गंभीरता से लेने के बजाय आलोचनाओं की झड़ी लग गई थी, लेकिन आज वही अलगाववादी प्रयोगशाला जब अपना दायरा बढ़ा रही है तो एक आम नागरिक जो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में निरंतर प्रयासरत रहता है, घबरा रहा है। घबराहट सिर्फ आज के संदर्भ में नहीं है, बल्कि भविष्य को लेकर भी है। आने वाली पीढ़ी के संदर्भ में इस घबराहट की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पहले सड़कों पर आवाजाही रोकना पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी और फिर हत्या...। हद तो तब हो जाती है जब इतना सब करने के बाद भी बड़ी मासूमियत से प्रधानमंत्री से बातचीत की उम्मीद भी की जाती है। कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारी बात सुनें। यानी एक तरफ पत्थरबाजी और दूसरी तरफ बातचीत। क्या ऐसे अराजक लोगों के साथ बातचीत की जानी चाहिए? लोकतंत्र का मतलब आजादी है, लेकिन जब इसे स्वच्छंदता के रूप में लिया जाने लगे तो तस्वीर बदलने लगती है। लोकतंत्र गलत रास्ते पर जाने लगता है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बवाल मचाते दंगाई। फाइल फोटो।

**सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री के लिए कहे जा रहे अपशब्द :** यह हमारा ही देश है, जहां प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर खुलेआम अपशब्द कहे जाते हैं। डंडे मारने तक की बात कही जाती है। इतनी आजादी भारत में ही मुमकिन है। जरा पड़ोसी देश चीन की ओर नजर डालें, जो इन दिनों कोरोना वायरस से लड़ रहा है। वहां एक व्यक्ति को सिर्फ इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसने वहां के राष्ट्रपति को कोरोना वायरस से मुकाबला करने में असफल बताते हुए इस्तीफा देने की बात कह दी थी।

जरा इस बारे में सोचिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग करना कितना आसान है। इस पर किसी तरह की कार्रवाई की भी कोई आशंका नहीं होती। इन सबके बावजूद शाहीनबाग के हिमायती लोग देश में अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोते दिखते हैं। आज शाहीनबाग का विस्तार देश के आम नागरिकों के धैर्य की परीक्षा है। यह संविधान की आड़ में उद्दंडता से ज्यादा कुछ नहीं है, जो देश को बंधक बनाने की कोशिश में जुटा है।

2019 से 24 फरवरी 2020 के दरम्यान किसी भी रेल हादसे में किसी यात्री की जान नहीं गई। 1853 में शुरुआत के बाद से रेलवे को पहली बार यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 26 फरवरी 2020

उत्तराखंड

# शिक्षा विभाग का चिंताजनक रवैया

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की कार्यसंस्कृति पर सवाल उठ रहे हैं। उठें भी क्यों नहीं, विभाग के अधिकारियों को न तो अपनी जिम्मेदारी एहसास और न ही कायदे-कानून की परवाह। वे जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे उनकी कार्यप्रणाली पर लगातार प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। अधिकारी शायद पर्वतीय राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर आने ही नहीं देना चाहते हैं। रोजमर्रा के काम हों या फिर शैक्षिक उन्नयन की मुहिम, सभी में विभाग का चिंताजनक रवैया है। ऐसे सुस्त रवैये को देखते हुए यह कहने से गुरेज नहीं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में विभागीय अधिकारियों की दिलचस्पी कम ही नजर आती है। केंद्र सरकार के स्तर से छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर शिक्षा विभाग का रवैया इसकी बानगी है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताब और यूनिफार्म के लिए केंद्र सरकार बजट उपलब्ध कराती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना (डीबीटी स्कीम) के तहत यह रकम सीधे बच्चों के खाते में जमा की जाती है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएं, इसके लिए शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार के स्तर से मिलने वाली सुविधाओं का विवरण अपने पोर्टल पर अपलोड करना होता है, लेकिन अधिकारियों ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। इस कार्य को बेहद हल्के में लिया गया। विडंबना यह कि जिसके लिए शिक्षा विभाग को खुद चिंतित होना था, उसकी याद भी केंद्र सरकार के अधिकारियों को दिलानी पड़ी। उन्होंने ही यहां के अधिकारियों को नींद से जगाया। आनन-फानन अब प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थियों की खोजबीन कराई जा रही है। कमोबेश यही रवैया किताबों और यूनिफार्म के लिए राज्य सरकार के स्तर पर जारी किए जाने वाले बजट की भी है। अकादमिक सत्र गुजरने को है, लेकिन राज्य के 36 हजार छात्र-छात्राओं का इंतजार खत्म नहीं हुआ। शिक्षा महकमे की धींगामुश्ती यही खत्म नहीं होती, नीतिगत मसलों पर भी अधिकारियों की कार्यशैली कठघरे में है। तीन साल पहले अनुदान श्रेणी में शामिल किए गए 200 अशासकीय स्कूलों को ही ले लीजिए। इनमें काफी संख्या में ऐसे स्कूल हैं, जो अनुदान के मानक ही पूरे नहीं करते। इनमें से 134 स्कूल टोकन अनुदान भी हासिल कर चुके हैं। ऐसे में विभागीय अधिकारियों पर अंगुली उठना स्वाभाविक है। मनमानी की शिकायतें मिलने पर सीएम 17 स्कूलों को अनुदान देने का आदेश हालिया दिनों में निरस्त कर चुके हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच भी बिठाई है। बड़ा सवाल यह कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने बेलगाम क्यों? राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार को इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए। अन्यथा यह मर्ज नासूर बनते देर नहीं लगेगी। ध्यान रहे शिक्षा व्यवस्था में यह बदहाली उस राज्य में है, जहां के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक देश के मानव संसाधन मंत्री हैं।

**उत्तराखंड में शैक्षिक उन्नयन की राह में विभाग के अफसर ही रोड़ा बन रहे हैं। उनकी उदासीनता बेचैनी बढ़ा रही है।**

बिहार

# विकेंद्रित विकास का बजट

नए वित्तीय वर्ष के लिए पेश राज्य का बजट संतुलित व विकासोन्मुखी होने के साथ ही पर्यावरण संकट को ध्यान में रखते हुए हरियाली बढ़ाने पर केंद्रित है। यह पहली बार है, जब बजट में तकरीबन सभी विभागों की योजनाओं में हरित आवरण बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान की कोशिश झलकती है। साथ ही इसमें जिस तरह कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग, ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि समेत अन्य सभी क्षेत्रों को समदर्शी तरीके से महत्व दिया गया है, इससे पता चलता है कि नीतीश सरकार की नीतियों के अनुरूप यह समावेशी और विकेंद्रित विकास की ओर ले जाने वाला बजट है।

यही कारण है कि कई अर्थशास्त्री इसकी सराहना कर रहे हैं। इससे पूर्व सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा में पेश किया गया 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण भी उत्साह बढ़ाने वाला है। निश्चय ही यह गर्व की बात है कि बिहार लगातार तीसरे वर्ष देश की विकास दर से आगे रहने वाला राज्य बन गया है। सीमित संसाधनों के बाद भी यदि एक दशक में बिहार के अंदर लगातार सामाजिक और आर्थिक विकास देखने को मिल रहा है तो यह नीतीश सरकार की प्रबल इच्छाशक्ति व कुशल प्रबंधन

प्रतीकात्मक फोटो

**नीतीश सरकार की नीतियों के अनुरूप यह समावेशी और विकेंद्रित विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह बिहार को समस्त क्षेत्रों में उन्नति के पथ पर तेजी से अग्रसर करने में समर्थ हो सकेगा।**

का परिचायक है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन जारी रहने के साथ ही लोगों की आय बढ़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण का यह परिणाम उत्साहजनक है कि पिछले एक दशक के दौरान प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के नए-नए अवसर बढ़े हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा, ज्ञान व कौशल विकास के माध्यम से बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, जो उसके दूरदर्शी होने का प्रमाण है। राज्यपाल फागू चौहान ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उचित ही कहा कि राज्य की नीतीश सरकार न्याय के साथ विकास के मूलमंत्र को अपनाते हुए सभी क्षेत्रों और वर्गों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। आर्थिक सर्वेक्षण के परिणाम साबित करते हैं कि सरकार की समावेशी और विकेंद्रित विकास की नीति अब आकार लेने लगी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आर्थिक सर्वेक्षण के बाद मंगलवार को नए वित्तीय वर्ष के लिए विधानसभा में पेश राज्य का बजट बिहार को समस्त क्षेत्रों में उन्नति के पथ पर तेजी से अग्रसर करने में समर्थ हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में बिहार की देश में छवि सुधरी है। लोगों को अपना भविष्य बेहतर दिखने लगा है।

हिमाचल प्रदेश

# जोर पकड़े स्वच्छता का संदेश

बीमारी तभी फैलती है जब साफ सफाई का अभाव होता है। स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता को आदत बनाना होगा। यह बात हैरान करने वाली है कि स्वच्छता के लिए अभियान चलाए जाने के बावजूद कई लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं। कई लोग अपने घरों को तो साफ रखते हैं मगर कूड़े को नालियों, नालों या नदियों में फेंकते हैं। ऐसा करना प्रदूषण को बढ़ावा देना है। यदि अपना घर साफ रखा जा सकता है तो अपने आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखने में क्या बुराई है। घर से निकलने वाला कूड़ा यदि प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर रखे कूड़ादान में डाला जाए तो इसमें दिक्कत कहां है। दो अक्टूबर, 2014 को देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हाथ में झाड़ू उठाने के साथ साफ-सफाई जनांदोलन बना दिया। देश के हर क्षेत्र के लोग इस काम में आगे आए। उन्होंने बढ़चढ़ कर इस अभियान में हिस्सा लिया। इतना सब होने के बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कूड़ा बिखरा दिखता है। महज सफाई अभियान चलाना या साफ सफाई के बाद फोटो खिंचवा कर उसका प्रदर्शन करना सही नहीं है। ऐसे अभियानों की सार्थकता को भी सिद्ध करना होगा। देखा जाना चाहिए कि जिस स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है, वहां निरंतर सफाई रहे। देवभूमि यानी हिमाचल प्रदेश में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो खुला शौचमुक्त तो घोषित हो गए हैं मगर वहां अब गंदगी का आलम है। ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए ऐसे स्थानों की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि स्वच्छता की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं मगर ऐसे प्रयासों में और तेजी लाए जाने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करने के अभियान तेज हों। असल में स्वच्छता एक आदत है जिसे सबको अपनाना चाहिए। हिमाचल के लिए सुखद संदेश यह है कि शिमला प्रदेश का पहला खुला शौचमुक्त (ओडीएफ) प्लस प्लस शहर बना है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण टीम ने शिमला शहर को ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा दिया है। स्वच्छता के मानकों पर नगर निगम का क्षेत्र खरा उतरा है। शत प्रतिशत घरों में शौचालय, सीवरेज कनेक्टिविटी व बेहतर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर यह दर्जा मिला है। यह उपलब्धि दूसरों के लिए भी स्वच्छता का संदेश है। इस उपलब्धि से हर किसी को सबक सीखना चाहिए। अगर शिमला उपलब्धि हासिल कर सकता है तो अन्य स्थान क्यों हासिल नहीं कर सकते हैं, इस पर मंथन करना चाहिए। जब सब लोग सामूहिक प्रयास करेंगे तभी स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा करना संभव हो सकेगा। सरकार की नहीं राज्य के लोगों पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि दुनिया में हिमाचल की प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। ध्यान रखे देश ही नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों से हर साल लाखों सैलानी हिमाचल आते हैं।

**स्वच्छता सभी को अपनानी चाहिए। इसके लिए जागरूकता अभियान तेज करना होगा। वहीं जनता को भी जिम्मेदारी का अहसास करना होगा**

झारखंड

# जहरीली शराब का कहर

बेशक झारखंड के गर्भ में अकूत संपदा है। कोयला, अभ्रक समेत अनेक खनिज पदार्थ पूरे देश को यहीं से जाते हैं। सोना और यूरेनियम की भी प्रचुरता है। कहने का आशय यह है कि इस राज्य में तमाम वैसी चीजें हैं जो इसे मुकाम दे सकती हैं। और, ऐसा हो भी रहा है मगर कुछ बातें हैं जो बढ़ते कदम पर रोक लगा देती हैं। इनमें जहरीली शराब भी है। इसके उपयोग से जान जा रही है। परिवार बिखर रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। हालिया उदाहरण लें। गिरिडीह में 15 लोगों की मौत ने पूरे सूबे को हिला दिया। इनमें 11की मौत का कारण जहरीली शराब को माना गया। इसे गिरिडीह के सिविल सर्जन ने भी माना। उपायुक्त की जांच रिपोर्ट में भी यही बात निकली।

ऐसे में साफ है कि कहीं न कहीं तंत्र की खामियों के कारण इंसानी जीवन दांव पर लग रहा है। अवैध शराब कारोबारी शराब को नशीला बनाने के लिए स्प्रिट, यूरिया व ऑक्सीटोक्सिन जैसे जहर का इस्तेमाल करते हैं। इससे बेशक बेहद कम समय में शराब तैयार होती है, लेकिन इसमें मिलाए गए रसायन

प्रतीकात्मक फोटो

**अवैध कारोबारी शराब को नशीला बनाने के लिए स्प्रिट, यूरिया और ऑक्सीटोक्सिन जैसे जहर का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस कैसे इस पर आंखें मूंदे है यह जांच का विषय है।**

इसे जहरीला बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस धंधे के बारे में तंत्र को मालूम नहीं। पुलिस और उत्पाद विभाग का अपना स्पाई नेटवर्क होता है, उनको सूचना भी मिल जाती है मगर वे आंख मूंदे रहते हैं। क्यों, ये सबको पता है। यह स्थिति ठीक नहीं। नीति नियंताओं को मंथन करना होगा कि किसी की भी जान सस्ती नहीं। और, बात सिर्फ एक जगह की नहीं है। ये राज्य के कई हिस्सों में होता रहा है। इसलिए जरूरी है कि इस घटना से सबक लेकर तंत्र के स्तर पर ऐसे उपाय किए जाएं ताकि फिर जहरीली शराब से किसी की मौत न हो। पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी शिद्दत से फर्ज अदा करें। साथ ही जागरूकता अभियान चलाएं। लोगों को बताना होगा कि शराब नहीं, परिवार उनका भविष्य है। शिक्षा का ईमानदारी से प्रचार और प्रसार करना होगा, जिससे वे सही-गलत में फर्क कर सकें। जनता के नुमाइंदों को भी आवाज उठानी होगी। वे लोगों के बीच जाएं और बताएं कि मानव जीवन अनमोल है, इसे जहरीली शराब की बलि न चढ़ाएं। मानव जीवन को बचाने के लिए समवेत प्रयास बेहद अहम हैं।

# ट्रेन की साइड बर्थ पर नहीं होगा कमर दर्द

**तैयारी** ▶ सीट के दोनों पल्ले नीचे आते ही हो जाएंगे फिक्स, सभी ट्रेनों में बदली जाएंगी बर्थ

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

ट्रेन की साइड लोअर बर्थ पर सफर करने में लोगों को कमर दर्द होने लगता है। ऐसी कई शिकायतें रेल प्रशासन को मिली हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब रेल प्रशासन इस सीट को आरामदायक बनाने की तैयारी में है। नई सीट में लेटने पर यात्रियों को कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी।

ट्रेनों की आरक्षण बोगी में साइड लोअर बर्थ होती है। पुराने स्लीपर व एसी-थ्री कोच में आठ और नए कोच में नौ लोअर बर्थ होती हैं। जबकि एसी टू में छह बर्थ होती हैं। साइड लोअर बर्थ रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (आरएसी) वाले यात्रियों को आवंटित की जाती हैं। इसमें दो यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है। बीच रास्ते में बर्थ खाली होने पर आरएसी वाले एक यात्री को खाली बर्थ व दूसरे यात्री को साइड लोअर बर्थ आवंटित की जाती है। दोनों बैठने वाली सीट को जोड़ कर एक बर्थ बनाई जाती है। जोड़ने की प्रक्रिया में बर्थ ऊंची नीची रह जाती है, जिससे उस पर सोने वाले यात्रियों की कमर में दर्द हो जाता है। इसकी कई शिकायतें रेल मंत्रालय तक पहुंची हैं। इन शिकायतों को देखते हुए रेल मंत्रालय के आदेश पर अब साइड लोअर बर्थ को आरामदायक बनाया जा रहा है।

**ब्लॉक सिस्टम से तैयार होगी बर्थ :** साइड लोअर बर्थ को ब्लॉक सिस्टम से तैयार किया जाएगा। जब दोनों सीट को जोड़ने के लिए पल्ला नीचे लाया जाएगा तो ब्लॉक आपस में जुड़ जाएगा। नीचे सपोर्ट देने की व्यवस्था होगी, जिससे बर्थ ऊपर नीचे नहीं होगी। साइड लोअर व अपर बर्थ की लंबाई 176 सेंटीमीटर होती है। प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा ने बताया कि नए कोच में आरामदायक साइड लोअर बर्थ लगाई जा रही हैं। पुराने कोचों में भी आधुनिक बर्थ लगाई जाएगी।

**साइड लोअर बर्थ की दोनों सीटें ऊपर नीचे होती हैं, इससे सोने पर कमर की हड्डी पर भार पड़ता है, जिसके चलते यात्रियों को कमर दर्द होता है। सीटों के ऊपर नीचे होने से यात्रियों को असहज महसूस होता है और नींद नहीं आती है।**

**– डॉ. शेर सिंह कक्कड़, हड्डी रोग विशेषज्ञ, (मुरादाबाद)**

## रेलवे के लिए सुरक्षित साबित हो रहा है मौजूदा वित्त वर्ष

**2019-20 के बीते 11 महीने में रेल दुर्घटना में कोई मौत नहीं**

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** भारतीय रेलवे के लिए मौजूदा वित्त वर्ष को अभी तक के सबसे सुरक्षित समय के रूप में रिकार्ड किया जा सकता है। बीते 11 महीने में किसी भी यात्री की मौत नहीं होना इस बात का सुबूत है। रेलवे ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि उसके 166 वर्षों के इतिहास में यह एक मील का पत्थर है।

एक बयान में रेलवे ने कहा है कि एक अप्रैल 2019 से 24 फरवरी 2020 तक किसी भी रेल दुर्घटना में किसी रेल यात्री की जान नहीं गई। रेलवे ने कहा है, '166 साल पहले 1853 में भारत में रेलवे सिस्टम के शुरू होने के बाद से 2019-20 में पहली बार यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। पिछले 11 महीनों के दौरान किसी यात्री की मौत नहीं हुई। यह सभी पहलुओं में रेलवे के सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार के लगातार होने वाले प्रयास का परिणाम है।' रेलवे ने यह भी कहा है कि यात्री सुरक्षा उसकी शीर्ष प्राथमिकता में है। रेलवे ट्रैक के बड़े पैमाने पर नवीकरण, ट्रैक की प्रभावी रूप से देखरेख, सुरक्षा पहलुओं की सतत निगरानी, रेलवे कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार, सिग्नलिंग प्रणाली में सुधार, सुरक्षा कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, पारंपरिक आइसीएफ कोच से चरणबद्ध तरीके से आधुनिक और सुरक्षित एलएचबी कोच में बदलना आदि उसकी प्राथमिकता में है।

# हिमाचल में नियामक आयोग के पास नहीं निजी विवि की डिग्रियों का रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, शिमला

हिमाचल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों ने कितनी डिग्रियां बांटी हैं। इसका निजी शिक्षा नियामक आयोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। न तो निजी विवि ने आयोग को डिग्रियों का रिकॉर्ड सौंपा है और न ही आयोग ने अपने स्तर पर रिकॉर्ड तैयार किया है।

प्रदेश में दो निजी विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री पाए जाने का मामला सामने आने के बाद आयोग ने जांच शुरू की। इसके बाद पता चला कि आयोग के पास ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है। पूर्व में आयोग के चेयरमैन, सदस्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इससे आयोग की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। फर्जीवाड़े के बाद आयोग ने भी अब निजी विवि पर शिकंजा कस दिया है।

आयोग ने दो निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। इन्हें कहा गया है कि स्थापना से लेकर अभी तक कितने विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी गई हैं इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करके लाएं। इसमें यह भी देखा जाएगा कि कितने छात्रों ने बीच में ही डिग्री छोड़ दी थी। इस रिकॉर्ड को दाखिले के रिकॉर्ड के साथ सत्यापित किया जाएगा। अन्य निजी विवि को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने रिकॉर्ड को जल्द आयोग के कार्यालय में दें।

**नई शर्त लगाने की तैयारी :** आयोग सभी निजी विश्वविद्यालयों पर नई शर्त लगाने जा रहा है। इसके तहत हर साल दीक्षा समारोह से पहले प्रकाशित करवाना होगा कि विवि से कितने विद्यार्थी पासआउट हुए हैं। कितनी डिग्रियां बांटी जानी है। दीक्षा समारोह से पहले डिग्रियों का ब्योरा देने के निर्देश पहले ही आयोग निजी विश्वविद्यालयों को जारी कर चुका है।

**दो निजी विवि के खिलाफ चल रही जांच :** प्रदेश के दो निजी विश्वविद्यालयों पर फर्जी डिग्रियां देने का आरोप है। इसको लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिकायत भेजी है। यूजीसी ने प्रदेश सरकार को इस मामले को लेकर पत्र लिखा है। यूजीसी से मिले पत्र के बाद नियामक आयोग ने इन विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है।

प्रतीकात्मक।

**निजी विश्वविद्यालयों के दाखिले का रिकॉर्ड आयोग के पास है। कितने विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और कितने पासआउट हुए इसका कोई रिकॉर्ड आयोग के पास नहीं है। अब डिग्रियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। निजी विवि को रिकॉर्ड जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।**

**– एसपी कत्याल, सदस्य निजी शिक्षा नियामक आयोग**

# चमोली में हिमखंड रोक रहे फूलों की घाटी की राह

संवाद सूत्र, जोशीमठ (चमोली)

विश्व धरोहर फूलों की घाटी में रेकी के लिए गया वन कर्मियों का आठ- सदस्यीय दल वापस लौट आया है। दल को घाटी में एक सप्ताह तक रुकना था, लेकिन खराब मौसम के चलते पांच दिन में ही लौट आया।

इस दौरान दल ने घाटी में हिमालयन थार का झुंड भी देखा और वन्यजीव तस्करों पर नजर रखने के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरे का बैटरी भी बदली। वन क्षेत्राधिकारी (फूलों की घाटी रेंज) बृजमोहन भारती ने बताया कि वन कर्मियों की टीम घाटी में द्वारीपुल तक गई। वहां जगह-जगह हिमखंड पैदल रास्ते को रोके हुए हैं। बताया कि घाटी में अभी सात फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है और छह से अधिक स्थानों पर 40 से 50 फीट ऊंचे हिमखंड बने हुए हैं। आगामी एक जून को विश्व धरोहर फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोला जाना है। इसके लिए अप्रैल से यहां पैदल रास्ते को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया जाएगा।

चमोली में बर्फ से लकदक फूलों की घाटी की रेकी करते नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के कर्मचारी। फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए एक जून को खोला जाना है। फोटो : साभार-नंदा देवी पार्क प्रशासन

# संगम तट से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे पीएम नरेंद्र मोदी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- पांच हजार मिट्टी के घड़े कार्यक्रम स्थल पर रखे जाएंगे पेयजल के लिए
- कार्यक्रम स्थल होगा नो पॉलीथिन जोन, कुल्हड़ में दिया जाएगा पानी

प्रयागराज के संगम तट के पास परेड मैदान में 29 फरवरी को होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कई मायनों में अहम होगा। एक तो इतनी बड़ी तादाद में पहली बार दिव्यांगों और बुजुर्गों को उपकरण प्रदान किए जाएंगे। दूसरे, कार्यक्रम में लगभग 70 हजार लोगों के लिए भोजन व जलपान की व्यवस्था होगी। इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण का भी पूरी दुनिया को संदेश देंगे।

समारोह स्थल को नो पॉलीथिन जोन बनाया जाएगा। भोजन प्लास्टिक के पैकेट में नहीं, बल्कि कागज की विशेष पैकिंग में दिया जाएगा। प्लास्टिक की पानी की बोतल के स्थान पर समारोह स्थल पर कई जगह मिट्टी के पांच हजार बड़े घड़े रखे जाएंगे। पानी भी मिट्टी के कुल्हड़ और कागज के खास कप में दिया जाएगा। दिव्यांगजन व वृद्धजन को कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में सामाजिक सरोकारों की भी झलक दिखेगी। गरीबी उन्मूलन के लिए भी समारोह स्थल से बड़ा संदेश जाएगा।

**मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को मिला रोजगार :** आयोजन से मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को व्यापक स्तर पर रोजगार मिल गया है। कोरांव, शंकरगढ़, सोरांव, प्रतापपुर, धनुपुर, सैदाबाद व मांडा के कई स्वयं सहायता समूहों को इसके लिए लगाया गया है। इसके अलावा लगभग आठ सौ लोगों को भी घड़ा व कुल्हड़ बनाने के लिए कहा गया है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जिलों प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशांबी, भदोही, मीरजापुर और बांदा से भी घड़े व कुल्हड़ मंगाए जा रहे हैं। इन जिलों के सीडीओ को इसके लिए कहा गया है। ये घड़े और कुल्हड़ 27 फरवरी की शाम तक समारोह स्थल पर मंगा लिए जाएंगे। इसके लिए सौ से ज्यादा ट्रकों व ट्रैक्टरों को लगाया गया है।

**घड़े-कुल्हड़ के लिए लगी ड्यूटी :** मिट्टी के घड़े और कुल्हड़ की व्यवस्था के लिए अफसरों व कर्मचारियों की टीम लगा दी गई है। डीपीआरओ रेनू श्रीवास्तव को इसका प्रभारी बनाया गया है। मंगलवार को उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को समारोह स्थल तक ले आने की तैयारियों की समीक्षा भी की।

नरेंद्र मोदी। फाइल

# मप्र में निजी शिक्षण संस्थाओं को निधि नहीं दे सकेंगे विधायक

अजय जैन. विदिशा

**बदलाव**

- सरकार ने विस क्षेत्र विकास निधि के प्रावधान बदले
- निर्माण के लिए दस लाख रुपये तक दे सकते थे विधायक

मध्य प्रदेश सरकार ने निजी शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को भवन निर्माण के लिए विधायकों द्वारा दी जाने वाली विधायक निधि पर रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम का विपक्षी भाजपा विधायक विरोध कर रहे हैं। प्रदेश के सिरोंज और कुरवाई के विधायकों ने इस मामले को विधानसभा के बजट सत्र में उठाने की बात भी कही है।

अभी तक मप्र में विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को निर्माण कार्यों के लिए विधायक निधि से राशि देने का अधिकार था। वे अधिकतम 10 लाख रुपये तक दे सकते थे। लेकिन राज्य के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया है। नए प्रावधानों के मुताबिक अब कोई भी विधायक अशासकीय संस्थाओं को शैक्षणिक कार्य तथा सामाजिक संगठनों द्वारा बनाई जाने वाली धर्मशाला सहित अन्य निर्माण कार्यों के लिए राशि मंजूर नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में फर्नीचर, टाट-पट्टी सहित अन्य सामग्री खरीदने के लिए भी राशि दी जाती थी। इसमें अब यह शर्त लगा दी है कि विधायक सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही विधायक निधि मंजूर कर सकेंगे।

**20 फीसद राशि देते थे विधायक :** योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के विदिशा जिला अधिकारी सेवाराम रैकवार के मुताबिक अब तक करीब 20 फीसद राशि विधायक शिक्षण संस्थाओं में निर्माण कार्य के लिए मंजूर करते थे। नए आदेश के बाद यह राशि मंजूर नहीं हो सकेगी। सभी विधायकों को योजना के नए प्रावधान बता दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि विधायकों को हर साल 1.85 करोड़ रुपये निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के तौर पर मिलते हैं।

**पाबंदी से विधायकों में असंतोष :** कमलनाथ सरकार के इस फैसले से विधायकों में भी असंतोष है। कुरवाई से भाजपा विधायक हरिसिंह सप्रे ने इसे विधायकों के अधिकारों का हनन बताया तो सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने जनता और समाज के बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास करार दिया।

**3.3** लाख घर जम्मू-कश्मीर में ऐसे हैं जिनमें पिछले डेढ़ बरस के दौरान बिजली के कनेक्शन दिए गए। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

जम्मू के बिश्नाह क्षेत्र में सरकार की ओर से प्रत्येक घर में शौचालय बनवाए गए हैं। जागरण

# जम्मू-कश्मीर में अब जमीन पर दिखने लगीं योजनाएं

## विकास ▶ पहली बार बिजली, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाएं फाइलों से निकल लोगों के घरों तक पहुंचीं

**जागरण विशेष**

**नवीन नवाज, जम्मू**

जम्मू-कश्मीर में सरकारी योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। बिजली, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाएं आज घरों तक पहुंच रही हैं। दूरदराज क्षेत्र के लोग भी मान रहे हैं कि पहली बार योजनाएं फाइलों से बाहर निकली हैं। शायद यह अनुच्छेद 370 हटने का चमत्कार है।

राज्य में तेजी से हो रहे विकास कार्यों से आमजन खुश हैं। आलम यह है कि कश्मीर के कुपवाड़ा के टंगडार में 70 साल में जो घर बिजली की रोशनी से वंचित थे, अब रात में जगमगाते हैं। अख्तर बीबी और उन जैसी महिलाओं को शौच के लिए अंधेरे में घर से नहीं निकलना पड़ता। मंजीत सिंह को अपने पिता के इलाज को सरकारी मदद के लिए न किसी विधायक के पास चक्कर काटने पड़े और न नौकरशाहों के दफ्तर में अर्जी लेकर घूमना पड़ा। पिछले डेढ़ साल में जम्मू-कश्मीर में मौलिक सुविधाओं के विकास ने जो गति पकड़ी है, उससे आमजन खुश हैं।

जम्मू-कश्मीर अब दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में बंट चुका है। जून 2018 में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार भंग हुई थी। इसके बाद राज्यपाल शासन लागू हो गया। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल के पास प्रशासनिक कमान है। विकास योजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कामकाज की समीक्षा की जा रही है। इसका असर विभिन्न इलाकों में आम लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव से समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू-कश्मीर में जनयोजनाओं की प्रगति को सराहा है। उन्होंने खुद और ट्वीट कर भी जम्मू-कश्मीर में डेढ़ साल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.5 लाख शौचालयों के निर्माण और 3.3 लाख घरों में बिजली के कनेक्शन देने की पुष्टि की है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में 3.5 लाख लोगों ने गोल्डन कार्ड प्राप्त किया है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि बदलाव है जो साफ देखा जा सकता है।

अस्पतालों में सुविधाओं में विस्तार देखने को मिल रहा है, जम्मू में आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराती महिला। जागरण

हमारा ध्यान आम लोगों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है। स्वच्छ भारत मिशन हो या हर घर में बिजली की योजना, सभी की लगातार निगरानी की जा रही है। हमने पंचों, सरपंचों को भी इनमें शामिल किया है। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में देश के अन्य भागों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री भी जम्मू-कश्मीर का जिक्र करते हैं।

**- रोहित कंसल, प्रवक्ता, योजना एवं निगरानी विभाग**

जम्मू से सटे चट्ठा गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाली सुलोचना कहती हैं कि हमें बिजली भी मिली और शौचालय भी। सुबह अंधेरे में घर से शौच के लिए निकलना पड़ता था। पिछले साल जनवरी में हमारे घर ब्लॉक के अधिकारी आए थे, उन्होंने शौचालय बनवाया। हमारे मुहल्ले में 15 परिवारों के घरों में शौचालय पिछले साल ही बना है...। कश्मीर में त्रेहगाम के ऊपरी हिस्से में रहने वाली अख्तर बीबी कहती हैं कि खुले में शौच जाना अपमानजनक था। आप महिलाओं से पूछो कि सरकार ने जो शौचालय बनवाए हैं, इनकी अहमियत क्या है...।

जम्मू कश्मीर में आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 31 लाख से अधिक है। अब तक 11 लाख 37 हजार लोगों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। योजना को आम लोगों तक पहुंचाने में जुटे डॉ. वसीम ने कहा कि हमारा दावा शायद आपको सही न लगे, लेकिन आप अस्पताल आकर देखें कि लोग कैसे लाभ ले रहे हैं। शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सौरा में पिता के डायलिसिस के लिए त्राल, पुलवामा से आए मंजीत सिंह ने कहा कि गोल्डन कार्ड का फायदा बहुत है। इससे हमें सस्ता और बढ़िया इलाज मिल रहा है, अन्यथा मैं अपने पिता को इलाज के अभाव में तड़पता देखता रह जाता। बड़गाम से आए रशीद ने कहा कि हमने तीन माह पहले ही गोल्डन कार्ड बनवाया है। इससे मेरी बीबी कुलसूम के दिल का ऑपरेशन का खर्च व अन्य टेस्ट सस्ते हो गए हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव आयुक्त अटल डुल्लु ने कहा कि करीब 62 हजार लोगों ने विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए गोल्डन कार्ड का लाभ प्राप्त किया है।

**बिजली आने में लग गए 70 साल...** : डेढ़ साल में जिंदगी में आए बदलाव का जिक्र करते हुए नजीर खटाना ने कहा कि हमारा थीड गांव लालचौक से बीस किलोमीटर दूरी पर है। यहां बिजली पहुंचने में 70 साल लग गए। हम लोग कई बार प्रतिनिधिमंडल लेकर मंत्रियों के पास गए, सचिवालय में चक्कर काटे। धरने दिए। थकहार कर बैठ गए थे। पिछले साल जुलाई में बिजली विभाग वाले आए और यहां खंभे व तार बिछने शुरू हो गए।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

# भोपाल के नवाब की बेटी साजिदा के फर्जी दस्तखत से खेल मैदान की रजिस्ट्री

**दीपक विश्वकर्मा, भोपाल**

- मामला अहमदाबाद पैलेस की संपति हड़पने का
- रिकॉर्ड में 1976 दिखाई गई रजिस्ट्री का पन्ना भी है फटा
- शर्मिला टैगोर और सैफअली खान भी हैं इसी खानदान के

भोपाल के नवाब रहे स्व. हमीदुल्ला खान की संपत्तियों को फर्जी ढंग से हड़पने के मामलों का अंत ही नहीं हो रहा है। अब नया तथ्य सामने आया है कि जिस अहमदाबाद पैलेस में हमीदुल्ला परिवार के साथ रहते थे, उसके पास स्थित खेल मैदान की भी उनकी बेटी साजिदा सुल्तान के फर्जी हस्ताक्षर से रजिस्ट्री हो चुकी है। ज्ञात हो, बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और अभिनेता सैफअली खान इसी खानदान के हैं।

खेल मैदान पर अभी सेफिया एजुकेशन सोसायटी शिक्षण संस्थान एक कॉलेज का संचालन कर रहा है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार खेल मैदान की रजिस्ट्री नूर महल क्षेत्र निवासी छोटे खान नामक व्यक्ति ने 1976 में ही करा ली थी। इस फर्जीवाड़े का पता तब चला जब हाल ही में इसका नामांतरण कराने के लिए बैरागढ़ तहसीलदार के पास आवेदन दिया गया। तहसीलदार ने आवेदन आने पर इस जमीन के पक्षकारों को नोटिस जारी किया तो फर्जी हस्ताक्षर से रजिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ।

**नामांतरण नोटिस से हुई शंका** : सेफिया एजुकेशन सोसायटी के सीईओ जैनुद्दीन शाह को जब नामांतरण के लिए दिए गए आवेदन के कारण नोटिस मिला तो वे चौंक गए। दैनिक जागरण के सहयोग प्रकाशन 'नईदुनिया' से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 1985 से यहां सेफिया एजुकेशन सोसायटी के नाम से शिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा है। सालों बाद अचानक जब नामांतरण के लिए नोटिस आया तो शंका पैदा हुई। इसकी जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय व रजिस्ट्रार कार्यालय से रिकॉर्ड निकलवाया तो कागजात फटे हुए मिले, जबकि रजिस्ट्रार कार्यालय के रसीद कट्टे में 1976 में किसी छोटे खान के नाम पर रजिस्ट्री होना नहीं पाया गया है।

**हस्ताक्षर मिलाए तो फर्जी निकले** : उन्होंने बताया कि जब रजिस्ट्री पर विक्रय करने वाले के हस्ताक्षर का मिलान किया गया तो सामने आया कि साजिदा सुल्तान के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर रजिस्ट्री कराई गई है। इसके बाद फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों से रजिस्ट्री कराने की डीआइजी व कलेक्टर भोपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई।

नवाब का अहदाबाद पैलेस। इसे पुराना सेफिया कॉलेज भी कहा जाता है। निर्मल व्यास

पुलिस और प्रशासन से पूरे मामले की शिकायत दो महीने पहले ही की थी। इसके बाद भी अब तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। रजिस्ट्री विभाग के पास जो रिकॉर्ड है वह फर्जीवाड़ा कर बनाया गया है।

**- जैनुद्दीन शाह, सीईओ, सेफिया एजुकेशन सोसायटी भोपाल**

फर्जी हस्ताक्षर से रजिस्ट्री का मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जाएगी।

**- तरुण पिथोड़े, कलेक्टर, भोपाल**

**1975 से है हाई कोर्ट का स्टे** : यह जमीन साजिदा सुल्तान के पास 4 फरवरी 1960 से 28 दिसंबर 1971 तक रही थी। इसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट के समक्ष पारिवारिक विभाजन को लेकर एक अपील दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने मामले में 30 जुलाई 1975 को स्टे आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि नवाब की संपत्ति न तो खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है। यह स्टे अब भी प्रभावी है।

**कल भोपाल आएगा परिवार** : नवाब हमीदुल्ला खान के परिवार की संपत्तियों के विवाद और इसके बंटवारे के बाद अब शाही खानदान के सदस्य 27 फरवरी को एक निजी कार्यक्रम के लिए भोपाल आएंगे। परिवार की सदस्य फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और करीना कपूर खान भी भोपाल आएंगी। बताया जाता है कि परिवार अपनी संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों में प्रशासन से शिकायत कर अपना पक्ष रखेगा।

# रंग बन परिधानों पर शोभित हो रहे बुद्ध को अर्पित फूल

## श्रद्धा, हर्बल और खादी... ▶ महाबोधि मंदिर के फूलों से बन रहा रंग, बौद्ध श्रद्धालुओं को लुभा रहे इनसे रंगे परिधान

मंदिर से निकले फूलों से बनाए जा रहे हर्बल रंग, रंगी जा रही खादी, बौद्ध धर्मावलंबियों में इनसे बने वस्त्रों की अच्छी मांग

**नीरज कुमार, गया**

भगवान बुद्ध के श्रीचरणों में अर्पित श्रद्धा के फूल रंग बनकर अनुयायियों के परिधानों में रच-बस गए। इससे जहां बौद्ध धर्मावलंबियों को प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, वहीं स्थानीय महिलाओं को रोजगार मुहैया हो गया है। युवा उद्यमी प्रवीण चौहान को रोजगारपरक उद्यमिता के लिए उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू सम्मानित कर चुके हैं।

जनसंख्या नियोजन

बोधगया भगवान बुद्ध की तपोभूमि है। यहां महाबोधि मंदिर से प्रतिदिन कई किलो फूल निकलते हैं। उनमें अधिकतर गेंदा के फूल होते हैं। पर्यटन के मौसम यानी सर्दियों में इनकी मात्रा रोजाना 250 से 300 किग्रा होती है। अब ऐसे फूल प्रवीण की टीम के लिए रोजी-रोटी का जरिया बन गए हैं और बुद्ध के अनुयायियों के लिए श्रद्धा (रंगीन खादी) के रूप में जीवनपर्यंत सुरक्षित रखने की सामग्री।

प्रवीण ने पिछले साल मंदिर से निकले फूलों से डाई (हर्बल रंग) बनाने की कवायद शुरू की। उस रंग से गया के निकट मानपुर में बुनी जाने वाली खादी के कपड़े रंगे जा रहे हैं। इस कपड़े की मांग विदेश में भी खूब है। जहानाबाद जिला में टनकुप्पा गांव के निवासी प्रवीण ने बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) से स्नातक की डिग्री ली। उसके बाद कुछ अलग करने का संकल्प लिया और बोधगया पहुंच गए। अपने प्रयास की बदौलत अब वे 'खादी मैन ऑफ बिहार' कहे जा रहे हैं। नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति उन्हें दि विजन ऑफ अंत्योदय सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। उनकी कोशिश और कामयाबी की कहानी दि विजन ऑफ अंत्योदय नामक पुस्तक में दर्ज है।

प्रवीण ने बताया, गेंदा के फूल से पराग और पंखुड़ी अलग करके उसे सुखाते हैं। उससे प्रयोगशाला में पाउडर बनाया जाता है। यह छोटी-सी प्रयोगशाला बोधगया औद्योगिक परिक्षेत्र में है। 30 किग्रा फूल से एक किग्रा पाउडर तैयार होता है। वह पाउडर डाई कहा जाता है, जिससे खादी की रंगाई होती है। बकौल प्रवीण, यह डाई गेंदा के फूलों से बनती है। मंदिर में चढ़ने वाले विदेशी फूलों में रसायन की मात्रा होती है। इस कारण उनसे डाई के बजाय हर्बल अबीर तैयार किया जाता है।

हर्बल रंग से रंगे हुए खादी के कपड़ों के साथ प्रवीण चौहान। जागरण

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

### सात समंदर पार अधिक मांग

प्रवीण बताते हैं कि इन फूलों से रंगीन हुई खादी की मांग ऑस्ट्रेलिया, जापान व लंदन तक है। मांग इतनी है कि उसे पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा। इसका एक कारण फैशन से धर्म की जुगलबंदी भी है। प्रवीण के मुताबिक बुद्ध से मिलकर शुद्ध हुई खादी फैशन की दुनिया में कदमताल करने लगी। यह ताज्जुब नहीं, हकीकत है। रंग से परिधान तक की योजना गया जिला प्रशासन के साथ ऑस्ट्रेलिया के द् हैप्पी हैंड्स' प्रोजेक्ट की कैथी विलियम्सन ने करार किया है। उसके बाद बोधगया के ग्रामीण क्षेत्र की 30 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। उन्हें खुद कैथी ने प्रशिक्षित किया है। अब वे महिलाएं प्रवीण की संस्था इंडियन सोशल रिस्पांसबिलिटी नेटवर्क से जुड़कर स्वावलंबी बन गई हैं। रूमा तोमर, शंशाक चौधरी, निवेदिता अचूतम, व सौम्या आदि के सहयोग से काम सुर्खियों में आ गया है। प्रयोगशाला में अब चरखा और सूत की भी व्यवस्था करने की कोशिश हो रही, ताकि वहीं पर परिधान भी तैयार किया जा सके।

# उत्तराखंड के टिहरी जिले की पंचायतों में भी लिविंग विद लेपर्ड का फार्मूला

**अनुराग उनियाल, नई टिहरी**

- टिहरी वन प्रभाग में वर्ष 2019 के दौरान नहीं हुई गुलदार के हमले की कोई भी घटना
- अब वन विभाग पंचायतों के जरिये लोगों को जागरूक करने के लिए चल रहा अभियान

उत्तराखंड के टिहरी जिले में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए लिविंग विद लेपर्ड फार्मूला कामयाब होता दिख रहा है। वर्ष 2019 में टिहरी वन प्रभाग में गुलदार के हमले की एक घटना नहीं हुई। इससे उत्साहित होकर वन विभाग अब क्षेत्र पंचायत समिति (बीडीसी) और ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी जिले में जागरुकता अभियान शुरू करने जा रहा है। हाल ही में अहमदाबाद (गुजरात) में हुए सेमिनार में भी टिहरी वन प्रभाग ने लिविंग विद लेपर्ड फार्मूले के तहत प्रजेंटेशन दिया था, जिसे काफी सराहा गया।

लिविंग विद लेपर्ड फार्मूले को क्षेत्र पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बैठकों में लागू करके लिए वन विभाग की मुख्य विकास अधिकारी स्तर पर वार्ता भी हो चुकी है। वन विभाग ने वर्ष 2018 में टिहरी के पौखाल और जाखणीधार क्षेत्र में इसके तहत जागरुकता अभियान शुरू किया था। तितली ट्रस्ट देहरादून ने महाराष्ट्र के संजय गांधी नेशनल पार्क और जुनर गांव में यही फार्मूला अपनाया था। इसके बाद टिहरी में भी इसे अपनाया गया।

टिहरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी कोको रोसे ने बताया कि पिछले हफ्ते अहमदाबाद में आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने इस फार्मूले के तहत प्रजेंटेशन दिया था, जिसे काफी पसंद किया गया। बताया कि इसी क्रम में अब वन विभाग के अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी देंगे। उधर, टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रुहेला का कहना है कि व्यापक स्तर पर जागरुकता से ही मानव-वन्यजीव संघर्ष रोका जा सकता है। क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों की बैठक में फार्मूले की जानकारी दिए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता का माहौल बनेगा। क्योंकि, पंचायत प्रतिनिधि जनमानस के सबसे अधिक करीब होते हैं।

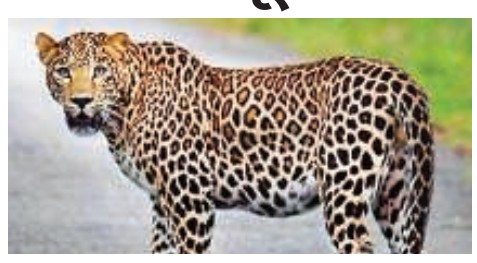

प्रतीकात्मक फोटो

### लिविंग विद लेपर्ड फार्मूला

- गुलदार के व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी
- उनके वास स्थलों की पहचान
- हिंसक होने के लक्षणों की पहचान
- जागरुकता संबंधी जानकारी
- गुलदार के घायल होने की पहचान

# पंजाब में घटा उर्वरकों का इस्तेमाल, पैदावार बढ़ी

**आशा मेहता, लुधियाना**

- रंग लाई मिट्टी की जांच, खेतों में आई नई जान
- वर्ष 2015-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की प्रति हेक्टेयर थी 247 किलोग्राम खपत

एक दशक पहले तक देश में हो रहे रासायनिक उर्वरकों के बेतहाशा प्रयोग में पंजाब के किसान भी आगे रहे। इन उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से भले ही सूबे में फसलों की पैदावार बढ़ी, लेकिन मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक तत्वों पर काफी बुरा असर पड़ा। ऐसे में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मृदा परीक्षण को लेकर अभियान चलाया गया। इसके सकारात्मक परिणाम पंजाब में भी देखने को मिले। अब न केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम हुआ है, बल्कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने से फसलों की पैदावार भी बढ़ी है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) भी वर्षों से किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाने के लिए लगातार प्रेरित करता रहा है। पीएयू के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पंजाब के अधिकारियों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में सूबे में रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी आई है। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की औसत खपत 247 किलोग्राम थी जो अब कम होकर 228 किलोग्राम रह गई है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग काफी कम हो गया।

वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि भारत में जितनी भी नाइट्रोजन खाद बनाई जाएगी, वह नीम युक्त ही होगी। तब से अब तक पंजाब में नाइट्रोजन की खपत 1447 हजार टन से घटकर 1434 हजार टन रह गई है। यानी इसकी खपत में 13 हजार टन की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह फास्फोरस व पोटाश के प्रयोग में भी कमी आई है। पीएयू से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में इस समय मृदा परीक्षण के लिए कुल 66 प्रयोगशालाएं हैं।

**मृदा परीक्षण से सामने आए बेहतर परिणाम: डॉ. चौधरी**

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के भूमि विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. ओपी चौधरी के अनुसार, मृदा परीक्षण के परिणाम बेहतर हैं। किसान जागरूक हो गए हैं। ज्यादातर किसान खेतों की मिट्टी की जांच करवाने लगे हैं। इसी का परिणाम है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई है।

प्रतीकात्मक फोटो

### ऐसे घटी रासायनिक उर्वरकों की खपत (आंकड़े हजार टन में)

| वर्ष | नाइट्रोजन | फास्फोरस | पोटाश |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 1447 | 418 | 78 |
| 2016-17 | 1458 | 411 | 48 |
| 2017-18 | 1401 | 402 | 75 |
| 2018-19 | 1434 | 333 | 54 |

(स्रोत: पीएयू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर)

### ऐसे बढ़ी पैदावार (हजार टन में)

| वर्ष | गेहूं | धान |
|---|---|---|
| 2015-16 | 16068 | 17621 |
| 2016-17 | 17636 | 18864 |
| 2017-18 | 17830 | 19972 |
| 2018-19 | 18209 | 19136 |

(स्रोत: पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना)

**एक साल में 23.40 लाख सैंपलों की हुई जांच** : राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डॉ. स्वतंत्र कुमार ऐरी के मुताबिक, किसान जरूरत के अनुसार ही खाद का इस्तेमाल करें, उसे लेकर विभाग ने काफी प्रयास किए गए हैं। किसानों को खेतों की मिट्टी की जांच करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही एक एजेंसी की मदद से मिट्टी के सैंपलों की जांच भी करवाई जा रही है। पंजाब में एक साल में करीब 23 लाख चालीस हजार सैंपलों की जांच की गई है। उस जांच के मुताबिक गांवों में फर्टिलिटी मैप लगाए गए हैं जिससे हरेक गांव की मिट्टी की पोजीशन की जानकारी मिलती है।

**बड़ी दिक्कत**

अनियोजित ढंग से हो रहे सड़कों के चौड़ीकरण के कारण उभर रहे नए-नए भूस्खलन जोन, आगामी बरसात में ये भूस्खलन जोन फिर बढ़ा सकते हैं यात्रियों के साथ आमजनों की मुश्किलें

# गंगोत्री हाईवे पर नासूर बने भूस्खलन जोन, उपचार की दरकार

**शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी**

चारधाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के तहत गढ़वाल क्षेत्र में 739 किलोमीटर सड़क तैयार होनी है। सीमा सड़क संगठन(बीआरओ) व नेशनल हाइवे (एनएच) का कहना है कि इसमें 644 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। लेकिन, इसके साथ ही पहाड़ों में नए-नए भूस्खलन जोन भी उभर रहे हैं। परियोजना शुरू होने के बाद से पहाड़ों पर पहले के मुकाबले तीन गुना से अधिक भूस्खलन जोन सक्रिय हो चुके हैं, जबकि पुराने भूस्खलन जोन ट्रीटमेंट के बाद भी नासूर बने हुए हैं। ऐसे में आगामी बरसात में ये फिर यात्रियों के साथ आमजन की भी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

ऋषिकेश-गंगोत्री हाइवे पर अभी जिला मुख्यालय उत्तरकाशी तक 169 किलोमीटर क्षेत्र में चारधाम परियोजना का काम चल रहा है। इस हाइवे पर पहले नालूपानी और चुंगी बड़ेथी डेंजर जोन में थे, लेकिन, अब यहां 25 से अधिक भूस्खलन जोन बन चुके हैं। हालांकि, उत्तरकाशी के पास चुंगी बड़ेथी में बीते तीन वर्षों से भूस्खलन जोन का उपचार चल रहा है, लेकिन यह सही होने के बजाय नासूर बन चुका है। वर्ष 2019 की बरसात तो चुंगी बड़ेथी का ट्रीटमेंट कार्य भूस्खलन के साथ ही धराशायी हो गया था। इससे अधिकांश समय यहां पर हाइवे बाधित रहा।

उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर चुंगी बड़ेथी के पास भूस्खलन जोन तीन साल से सक्रिय है, इस भूस्खलन जोन का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। जागरण

गंगोत्री हाइवे पर अभी तक करीब 12 भूस्खलन जोन चिह्नित किए गए हैं। इनके ट्रीटमेंट के लिए मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जा रही है। ताकि समय पर नई तकनीक से इन भूस्खलन जोन का उपचार किया जा सके।

**- विनोद कुमार श्रीवास्तव, कमांडर, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी**

यही हाल नालूपानी का है। यहां ट्रीटमेंट तो हो रहा है, पर भूस्खलन का खतरा बरकरार है। इस हाइवे पर नए भूस्खलन जोन में नरेंद्रनगर, नगुण, कुमारखेड़ा, बेमर, फकोट, कमांद व खाड़ी के पास बने हैं। यमुनोत्री हाइवे पर डाबरकोट भूस्खलन जोन पर अभी उपचार कार्य शुरू नहीं हुआ। यहां भूस्खलन जोन से पार पाने के लिए सुरंग स्वीकृत है। इस हाइवे पर भी आठ से अधिक भूस्खलन जोन नए बने हैं। ऋषिकेश-बदरीनाथ हाइवे पर साकनीधार, तीनधारा, जियालगढ़, सिरोबगड़ कालेश्वर, लंगासू, दिउलीबगड़, नंदप्रयाग, बांजबगड़, क्षेत्रपाल, बिरही, गडोरा, पीपलकोटी, पातालगंगा सहित 20 से अधिक भूस्खलन जोन हैं। रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाइवे पर बांसवाड़ा, बड़ासू, फाटा सहित कई स्थानों पर भूस्खलन जोन उभर हैं। हैरत देखिए कि चारधाम परियोजना के निर्माण से बने भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली और नदी बचाओ आंदोलन के संयोजक सुरेश भाई ने अनियोजित निर्माण से बढ़े भूस्खलन जोन पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि विकास के कार्य जरूरी हैं, लेकिन अनियोजित तरीके से नहीं। जिस तरह से पहाड़ों को काटा जा रहा है, उससे भूस्खलन लगातार बढ़ रहा है। जंगल और नदियों के साथ पूरा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है।

## खुली मिठाई पर भी लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

**नई दिल्ली, एजेंसियां :** मिठाई की दुकानों में कंटेनर या ट्रे में रखी खुली मिठाइयों के लिए भी अब दुकानदार को मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एफएसएसएआइ) ने इस वर्ष जून से स्थानीय मिठाई दुकानदारों के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखने की बाध्यता केवल पैकेटबंद मिठाइयों के लिए ही है।

भारत और अमेरिका बेहद पारदर्शी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों देश एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं। हमें जल्द व्यापक कारोबारी समझौते की उम्मीद है।

— पीयूष गोयल
वाणिज्य व उद्योग मंत्री

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेंसेक्स | 40,281.20 ▼ 82.03 | निफ्टी | 11,797.90 ▼ 31.50 | सोना प्रति दस ग्राम | ₹ 43,549 ▼ ₹954 | चांदी प्रति किलोग्राम | ₹49,990 ▼ ₹80 | $ डॉलर | ₹71.85 ▼ ₹00.13 | क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल | $ 56.14 |

# 500 अरब डॉलर के इंडो-यूएस कारोबार की उम्मीद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत-अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर (मौजूदा दर पर 35 लाख करोड़ रुपये) के स्तर पर पहुंच सकता है। औद्योगिक संगठन सीआइआइ की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से 2018 के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार में 11.8 फीसद सालाना विकास दर दर्ज किया गया है। यह दर जारी रहने पर वर्ष 2030 तक दोनों देश का आपसी व्यापार 500 अरब डॉलर के स्तर को छू लेगा। वर्ष 2000 में भारत और अमेरिका के बीच महज 19 अरब डॉलर का व्यापार होता था जो वर्ष 2018 में 142 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से लेकर अब तक सिर्फ दो साल वर्ष 2001 और 2009 में दोनों देशों के व्यापार में वैश्विक सुस्ती के कारण नकारात्मक बढ़ोतरी रही।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक नीति की वजह से पिछले चार साल में अमेरिका से होने वाले आयात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमेरिका से भारी मात्रा में सुरक्षा उपकरणों की खरीद के कारण वर्ष 2014 से 2018 के बीच अमेरिका के कारोबारी घाटे में 22 फीसद की गिरावट हुई है। वर्ष 2014 में अमेरिका का व्यापारिक घाटा 31 अरब डॉलर का था जो वर्ष 2018 में 24.2 अरब डॉलर का रह गया। सीआइआइ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर के स्तर पर ले जाने के लिए कई कदम उठाने होंगे। इनमें भारत को अमेरिका से आने वाले मेडिकल उपकरणों पर शुल्क में ढील के साथ हार्ले डेविडसन जैसी बाइक पर लगने वाले आयात शुल्क को समाप्त करने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही, ई-कॉमर्स में एफडीआई नियमों में भी सुधार की जरूरत बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को पांच लाख रुपये से अधिक कीमत वाली बाइक के आयात को शुल्क मुक्त कर देना चाहिए। इससे अमेरिका को सांकेतिक जीत का अहसास होगा जिससे भारत को फायदा होगा। हार्ले डेविडसन के आयात पर अभी 50 फीसद ड्यूटी है। पहले यह 75 फीसद था। ट्रंप अब भी ट्रेड का जिक्र होने पर हार्ले डेविडसन पर लगने वाले आयात शुल्क की चर्चा जरूर करते हैं। मंगलवार को भी उन्होंने मीडिया से बातचीत में इसका जिक्र किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तरफ से अमेरिकी मेडिकल डिवाइस के आयात की कीमत तय करना भारत के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। अमेरिका द्वारा भारत को अपने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) से बाहर करने की एक प्रमुख वजह भारत का यह फैसला रहा। भारत और अमेरिका इन मुद्दों पर एक व्यापक बातचीत का माहौल तैयार कर सकते हैं।

## आम, अंगूर और अनार के लिए खुलेगा अमेरिकी दरवाजा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अमेरिका से आएंगे चेरी, अल्फा-अल्फा हे, पोर्क और चिकन उत्पाद
- बहुत जल्द दोनों देशों के बीच इन उत्पादों के व्यापार को लेकर होगा अंतिम करार

व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भारत-अमेरिका जल्द ही कुछ सीमित वस्तुओं के व्यापार को लेकर अंतिम करार करने जा रहे हैं। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इन सीमित व्यापार के मामले में दोनों देशों के बीच पहले ही विचार-विमर्श हो चुका है और इस पर अंतिम सहमति लगभग बन चुकी है। सीमित व्यापार पर बनने वाली सहमति पर दोनों देश जल्द ही अपनी-अपनी वैधानिक जांच पड़ताल के बाद अंतिम मुहर लगा देंगे।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के अल्फा-अल्फा हे , चेरी, पोर्क और चिकन उत्पादों के आयात के लिए भारत अपने दरवाजे खोलने पर राजी हो गया है। वहीं, भारत के आम, अंगूर और अनार के लिए अमेरिका अपना बाजार खोलेगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच इन वस्तुओं के व्यापार पर बनी सहमति को अंतिम रूप देने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। हालांकि डेयरी उत्पाद को लेकर भारत ने अपने बाजार खोलने पर सहमति नहीं दी है। अमेरिका अपने डेयरी उत्पादों के बेचने की इजाजत देने के लिए भारत पर लगातार दबाव बनाता रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के चिकन उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोलना अमेरिका के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। आम और अनार के निर्यात के लिए भारतीय उत्पादकों को पहले अमेरिकी अधिकारियों को भारत में बुलाकर उत्पादन प्रक्रिया की जांच करानी पड़ती है। अमेरिकी अधिकारियों को बुलाने का खर्च भारतीय उत्पादकों को उठाना पड़ता है। इससे निर्यात की लागत बढ़ जाती है और अमेरिकी बाजार में भारतीय आम और अनार लैटिन अमेरिकी देश के इन उत्पादों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं।

लेकिन दोनों देशों के बीच बनी सहमति के बाद आम और अनार के निर्यातकों को इस प्रकार की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इस प्रकार की जांच प्रक्रिया की शर्त लागू होने से पहले भारत सालाना 30 लाख डॉलर मूल्य के आम का निर्यात अमेरिका को करता था।

भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अमेरिका भारतीय अंगूर के लिए भी अपने दरवाजे खोलने पर सहमत हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका हार्ले डेविडसन पर लगने वाले आयात शुल्क को बिल्कुल ही समाप्त कराना चाहता है, लेकिन भारत ने अभी अंतिम मंजूरी नहीं दी है।

### भारत-अमेरिका आपसी एफटीए की ओर

सीमित वस्तुओं के व्यापार को अंतिम रूप देने के साथ भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) वार्ता शुरू करने पर भी सहमति बन गई है। मंगलवार को हैदराबाद हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश बड़ी ट्रेड डील करने पर भी सहमत हुए हैं। मोदी ने कहा कि हमें आशा है कि आपसी हित में इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच एफटीए पर वार्ता शुरू करने से पहले अमेरिकी सरकार अपने कांग्रेस में नोटिस देगी और उसके 90 दिनों के बाद ही एफटीए पर बातचीत शुरू हो सकती है। इससे पहले एफटीए पर बातचीत के लिए एक ज्वाइंट स्टडी ग्रुप का गठन होगा जो व्यापारिक बातचीत के लिए मार्ग को प्रशस्त करेगा।

# भारत-अमेरिका संबंध को ऊर्जा साझेदारी से मिलेगी मजबूती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अमेरिका से तेल, गैस का आयात बढ़ाने के साथ कोयला भी खरीदेगा भारत

ऊर्जा क्षेत्र भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई वार्ता में दोनो देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में पारस्परिक निवेश को कई गुना बढ़ाने पर सहमति जताई। अमेरिका से तेल व गैस का आयात बढ़ाने के अलावा भारत कोयले की खरीद शुरू करेगा। अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबील भारत के गैस पाइपलाइन से अछूते क्षेत्रों में गैस पहुंचाने में इंडियन ऑयल की मदद करेगी। जबकि भारतीय कंपनियां अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को और बढ़ाएंगी।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा कि उनकी अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्रूलेट के साथ अच्छी बैठक हुई। प्रधान ने कहा, 'हमने दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में चल रही रणनीतिक भागीदारी की समीक्षा की तथा इसे अगले स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए।' पिछले वर्ष अपने एक भाषण में प्रधान ने कहा था कि अमेरिका से होने वाला ऊर्जा आयात इस वर्ष बढ़कर 10 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर ब्रूलेट ने भी ट्वीट कर बताया कि 'बैठक बहुत उत्पादक रही। मुझे उम्मीद है कि अब तक हमने जो प्रगति की है उसे और आगे बढ़ाने में सफल होंगे।' ऊर्जा क्षेत्र में मंगलवार को दोनो देशों के बीच कई समझौते हुए। इनमें सबसे प्रमुख समझौता एक्सॉन मोबील और इंडियन ऑयल के बीच हुआ है। इसके तहत गैस ग्रिड से अछूते रह गए क्षेत्रों में गैस पहुंचाने के लिए भारत में वर्चुअल गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा। वर्चुअल पाइपलाइन का मतलब है कि जहां वास्तविक पाइपलाइन नहीं है वहां सड़क, रेल तथा जलमार्गों के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाएगी। पाइपलाइन से अब तक वंचित रहे क्षेत्रों में दोनों कंपनियां मिलकर प्राकृतिक गैस का इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं बाजार विकसित करेंगी तथा स्वच्छ ईंधन एवं गैस आधारित विकास एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगी।

अमेरिका से ऊर्जा आयात करने वाला भारत चौथा सबसे बड़ा देश है। चार वर्ष पहले जहां भारत अमेरिका से सात अरब डॉलर का ऊर्जा आयात करता था, जो अब बढ़कर नौ अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अभी तक भारत अमेरिका से मुख्यतया कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करता था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। अमेरिका द्वारा परिवहन लागत में सब्सिडी दिए जाने के कारण मात्र चार वर्षों में भारत ने अमेरिकी कच्चे तेल की दैनिक खरीद को 10 गुना बढ़ाकर ढाई लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। नवीनतम समझौते के बाद अब कोयले की खरीद भी शीघ्र शुरू हो जाएगी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र के विविधीकरण में मदद की है। ऊर्जा दोनो देशों में सहयोग का सबसे आकर्षक क्षेत्र बनेगा।

# भारतीय कंपनियों को निवेश का न्योता

**ऑफर** ▶ अमेरिका के राष्ट्रपति ने नियामकीय प्रावधानों को आसान बनाने का किया वादा

## इकोनॉमी को गति देने के लिए अमेरिका में भारतीय निवेश आकर्षित करने की तैयारी

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय कंपनियों को अपने देश में निवेश का न्योता दिया है। इसके लिए उन्होंने नियामक प्रावधानों को आसान बनाने की बात भी कही है। ट्रंप ने कहा कि वह अपनी इकोनॉमी को गति देने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी दो दिवसीय भारतीय यात्रा के दौरान देश के अग्रणी कारोबारियों से बातचीत कर रहे थे।

इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और आदित्य बिडला ग्रुप के मुखिया मंगलम बिडला शामिल हुए। इन दौरान भारतीय कारोबारियों ने ट्रंप को अमेरिका में अपने निवेश और कारोबार से अवगत कराया। बैठक में ट्रंप ने भारतीय कारोबारियों से अमेरिका में निवेश के जरिये रोजगार सृजित करने में मदद का आग्रह किया।

नियामकीय चुनौतियों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि कुछ नियमन कारोबारी प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा हम नियामकीय चुनौतियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बहुत सी कारोबारी कठिनाइयों को दूर कर दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपसी सहयोग पर बातचीत कर रहे हैं। भारतीय कारोबारी अमेरिका में नौकरियां सृजित करें और अमेरिका यहां नौकरियों में इजाफा करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान यह भी कहा कि कोरोना वायरस महामारी को जल्दी ही नियंत्रित कर लिया जाएगा, क्योंकि चीन इस मामले में पूरी तत्परता से काम कर रहा है। भारतीय उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि खतरनाक कोरोना वायरस से निपटने को लेकर अमेरिका करीब 2.5 अरब डॉलर (लगभग 18,000 करोड़ रुपये) खर्च करने की योजना बना रहा है।

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में उद्योगपतियों के साथ बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मुखातिब हुए। प्रेट्र

# पेंशन कम्यूटेशन सुविधा बहाल

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा (कम्यूटेशन) बहाल कर दी है। इस फैसले से 6.3 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। पेंशन कम्यूटेशन के तहत अंशधारकों को एडवांस के तौर पर पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। इसका लाभ लेने पर 15 साल तक घटी हुई दर से और उसके बाद पूरी पेंशन मिलेगी।

श्रम मंत्रालय ने उन पेंशनभोगियों के लिए इसे बहाल करने का फैसला किया, जिन्होंने 25 सितंबर, 2008 को या उसके पहले इस सुविधा का लाभ उठाया था। ईपीएफओ ने इसे बहाल करने के निर्णय को 20 फरवरी को अधिसूचित किया। इसके लिए ईपीएफओ की पेंशन योजना को संशोधित किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक जिन सदस्यों ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले आंशिक निकासी सुविधा का लाभ उठाया था, उनकी पेंशन इस सुविधा का लाभ लेने के 15 साल पूरा होने के बाद बहाल कर दी गई है। इस निर्णय से 6.3 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं।

### इंतजार खत्म

- 6.3 लाख पेंशनभोगियों को होगा फायदा, ईपीएफओ की पेंशन योजना संशोधित

प्रतीकात्मक

### सुविधा किनके लिए

ईपीएफओ ने पेंशन फंड से आंशिक निकासी का प्रावधान वापस ले लिया था। अब इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर दिया गया है, जिन्होंने 25 सितंबर, 2008 को या उसके पहले इसका विकल्प चुना था। पेंशन कम्यूटेशन के तहत पेंशन में अगले 15 साल तक एक-तिहाई की कटौती होती है और घटी हुई राशि एकमुश्त दे दी जाती है। 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी राशि लेने का हकदार होता है।

### अगस्त में मिली थी मंजूरी

अगस्त, 2019 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ का निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों के लिए कम्यूटेशन की सुविधा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

# निवेश का सुरक्षित ठिकाना बना सोना

**नई दिल्ली, जेएनएन :** कोरोना वायरस चीन के बाहर भी अपने पैर पसारता जा रहा है। इसके चलते ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरे असर की आशंका से डरे निवेशक सोने की तरफ रुख कर रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों के दौरान दुनियाभर के सराफा बाजारों में रौनक देखने को मिली। इस दौरान घरेलू बाजारों में भी सोना इस सप्ताह सोमवार को पहली बार 44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया। यह लगातार निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। इस वर्ष जनवरी के दौरान गोल्ड ईटीएफ में 200 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जो पिछले सात वर्षों में सर्वाधिक है। यह भी तब, जबकि भौतिक आधार पर सोने की मांग में कमी रही है।

सोमवार को लंदन के सराफा बाजार में सोने का भाव 1,689.31 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के साथ सात वर्षों के उच्च स्तर पर रहा। इससे पहले सोना जनवरी, 2013 में इस स्तर पर पहुंचा था। भारतीय बाजारों में सोमवार को सोना 953 रुपये के उछाल के साथ 44,472 रुपये प्रति 10 ग्राम के शिखर पर जा पहुंचा था। चांदी में भी 586 रुपये का उछाल आया और यह कारोबार के आखिर में 49,990 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी थी। हालांकि मंगलवार को इन बहुमूल्य धातुओं की कीमत में कुछ नरमी देखने को मिली। इस दौरान पीली धातु 954 रुपये लुढ़ककर 43,549 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिकी।

इस वर्ष अब तक सोने की ग्लोबल कीमत में सात परसेंट तक का इजाफा हो चुका है। पहले भी यह देखा जाता रहा है कि जब ग्लोबल इकोनॉमी पर किसी तरह का संकट नजर आता है, सोने में निवेश बढ़ जाता है। आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के समय सोने में किया गया निवेश सुरक्षित माना जाता है। आइएमएफ जैसी ग्लोबल संस्थाएं पहले ही कोरोना वायरस को लेकर चेता चुकी हैं। इस दौरान सोने में बढ़ते निवेश को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। कुछ जानकार मानते हैं कि सोने में बढ़ते तेज निवेश से इक्विटी मार्केट को चौकन्ना रहने की जरूरत है। कई विश्लेषक इस वर्ष की शुरुआत से ही कह रहे हैं कि इस वर्ष सोना 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक का स्तर पार कर लेगा।

### रौनक

- घरेलू बाजारों में सोना पहली बार 44 हजार रुपये के पार जाने में सफल
- जनवरी के दौरान गोल्ड ईटीएफ में हुआ रिकॉर्ड निवेश

# एयर इंडिया को खरीदने में अडानी ग्रुप की रुचि

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी की अगुआई वाला अडानी ग्रुप सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को खरीदने की तैयारी कर रहा है। बोली के लिए कोई अंतिम फैसला करने से पहले ग्रुप प्रस्ताव की जांच-परख कर रहा है। सरकार ने वित्तीय संकट का सामना कर रही एयर इंडिया में 100 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की हुई है। इसके साथ ही सरकार एयर इंडिया की कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग इकाई में 50 परसेंट हिस्सेदारी बेच रही है।

मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि अडानी ग्रुप की विलय और अधिग्रहण टीम एयर इंडिया के बोली दस्तावेज में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। अगर अडानी ग्रुप एयर इंडिया के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआइ) जमा करता है, तो वह टाटा ग्रुप, हिंदुजा, इंडिगो जैसी कंपनियों की कतार में शामिल हो जाएगा। अडानी ग्रुप पहले ही छह एयरपोर्ट के संचालन अधिकार हासिल कर चुका है। इसलिए ग्रुप एयर इंडिया के एयरपोर्ट ऑपरेशन में रुचि दिखा रहा है। हालांकि ग्रुप अंतिम फैसला एयर इंडिया के कर्ज और नुकसान को ध्यान में रखते हुए लेगा। एयर इंडिया के खरीदार को करीब 23,286.5 करोड़ कर्ज के रूप में चुकाने होंगे। इसके अलावा कंपनी की कुछ और देनदारियां भी हैं, जो खरीदार के हिस्से में आएंगी। एयर इंडिया के निजीकरण प्रस्ताव में ऐसी कोई शर्त नहीं है, जिससे अडानी ग्रुप के रास्ते में बाधा हो। ज्ञात हो कि सरकार ने विमानन कंपनियों को एयरपोर्ट के कारोबार में 27 परसेंट से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने पर रोक लगा रखी है।

- ग्रुप कर रहा है बोली प्रस्ताव की पड़ताल, छह एयरपोर्ट के संचालन अधिकार हासिल कर चुका है ग्रुप

प्रतीकात्मक

### बढ़ सकती है बोली जमा करने की समय-सीमा

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने पर विचार हो रहा है। गृह मंत्री की अगुआई वाला अंतर-मंत्रालयी समूह इस सप्ताह के अंत में बैठक करेगा, जहां नई तिथि की घोषणा की जा सकती है। फिलहाल बोली जमा करने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। इस समय इच्छुक खरीदार कंपनी के वर्चुअल डाटा रूम जाकर आंकड़ों की पड़ताल कर रहे हैं। कंपनी से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया से आगे और कंपनियों के जुड़ने की संभावना है। इसलिए अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इससे पहले सरकार ने 27 जनवरी को एयर इंडिया में 100 परसेंट हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीएमआइ) जारी किया था। इसके बाद 21 जनवरी को कंपनी के बारे में जानकारियों का पहला सेट जारी किया गया था।

### वजह

मॉरीशस को ग्रे लिस्ट में डालने से भी निवेशकों के उत्साह में कमी, सेंसेक्स 82 अंक और निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ बंद

# शेयर बाजारों पर कोरोना का भय हावी

**मुंबई, प्रेट्र :** ग्लोबल इकोनॉमी पर कोरोना वायरस के असर से डरे निवेशकों की शेयर बाजारों से बेरुखी बनी हुई है। मंगलवार को लगातार तीसरे सत्र में देश के प्रमुख शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 82.03 अंक नीचे खिसककर 40,281.20 के स्तर पर बंद हुआ। इस दौरान एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 31.50 अंकों की गिरावट देखने को मिली। कारोबार की समाप्ति की घंटी बजने के समय यह 11,797.90 के स्तर पर था।

सेंसेक्स पैक में सन फार्मा के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.37 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। एचसीएल टेक, आरआइएल, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी और एलएंडटी के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए। हालांकि इस दौरान टीसीएस, टाटा स्टील, भारती एयरटेल और एसबीआइ के शेयरों में तेजी देखने को मिली। बीएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में ऑयल एंड गैस, एनर्जी, हेल्थकेयर, इंडस्ट्रियल्स, ऑटो और कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स गिरकर बंद हुए। इससे पहले सोमवार को भी घरेलू बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली थी।

जानकारों के मुताबिक ग्लोबल स्तर पर बढ़ते कोरोना वायरस के प्रभाव से दुनियाभर के शेयर बाजारों पर दबाव बना है। घरेलू शेयर बाजार भी इससे अछूते नहीं हैं। मनी लांड्रिंग पर काबू पाने के लिए कई देशों की सरकारों द्वारा सम्मिलित रूप से करीब तीन दशक पहले गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पिछले दिनों मॉरीशस को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इससे भी निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि मॉरीशस के निवेशकों का एफपीआइ के रूप में पंजीकरण जारी रहेगा। हालांकि अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक उन पर निगरानी बढ़ा दी जाएगी।

मंगलवार को एशिया के अन्य बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। इस दौरान शंघाई के शेयर बाजार टूटकर बंद हुए। वहीं सियोल और हांगकांग के शेयर बाजार हरे निशान पर रहे।

प्रतीकात्मक

### इन शेयरों में रही गहमागहमी

**एचयूएल :** नई मैन्यूफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने की सूचना के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। इस दौरान बीएसई में कंपनी के शेयर 0.74 परसेंट बढ़त के साथ 2,232.40 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए।

वहीं एनएसई में यह 0.72 परसेंट उछाल के साथ 2,231.20 रुपये के भाव पर बिके। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि वह नई मैन्यूफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने की तैयारी कर रही है।

**टीवीएस :** मंगलवार को कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बीएसई में इसके शेयर 0.26 परसेंट गिरावट के साथ 436.35 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। वहीं एनएसई में यह 0.50 परसेंट टूटकर 436.40 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। इससे पहले कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया था कि कोरोना वायरस के चलते उसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे फरवरी में कंपनी के उत्पादन में 10 परसेंट गिरावट आने की आशंका है।

# बीते दिसंबर में 12.67 लाख लोगों को मिलीं नौकरियां

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** पिछले वर्ष दिसंबर में देश में करीब 12.67 लाख नई नौकरियां पैदा हुईं, जबकि इससे पिछले महीने यानी नवंबर में 14.59 लाख नौकरियां पैदा हुई थीं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के ताजा आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ईएसआइसी के साथ कुल 1.49 करोड़ नए कर्मचारियों और श्रमिकों के नामांकन कराए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सितंबर, 2017 से दिसंबर 2019 के दौरान लगभग 3.50 करोड़ नए लोग ईएसआइसी योजना में शामिल हुए।

एनएसओ की रिपोर्ट ईएसआइसी, ईपीएफओ और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बनाए गए नए सदस्यों के पेरोल डेटा पर आधारित है। अप्रैल, 2018 से इन तीनों निकायों के नए सदस्यों के आंकड़ों के आधार पर नौकरियों के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं।

**औपचारिक क्षेत्र की स्थिति :** नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक सितंबर, 2017 से दिसंबर 2019 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि योजना में करीब 3.12 करोड़ नए सदस्य शामिल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि सदस्यों की संख्या विभिन्न स्रोतों से मिली है, लिहाजा आंकड़ों में दोहराव हो सकता है। एनएसओ ने कहा कि रिपोर्ट फॉर्मल सेक्टर में रोजगार के स्तर को लेकर एक अलग दृष्टिकोण देती है। इससे समग्र स्तर पर रोजगार का पता नहीं चलता।

- सितंबर, 2017 से दिसंबर 2019 के दौरान ईएसआइसी योजना में शामिल हुए लगभग 3.50 करोड़ नए लोग

## न्यूज गैलरी

### चीन में स्वीडिश प्रकाशक को दस साल जेल की सजा

**बीजिंग :** चीन में अवैध रूप से विदेशी सूचना मुहैया कराने के मामले में स्वीडन के प्रकाशक गुई मिन्हाई को दस सजा जेल की सजा सुनाई गई है। चीन में जन्मे गुई मिन्हाई को 2018 में पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह स्वीडिश राजनयिकों के साथ थे। उनकी गिरफ्तारी को लेकर चीन और स्वीडन में तनाव भी देखने को मिला था। गुई पहले हांगकांग में रहते थे, लेकिन बाद में चीन आ गए थे और ऐसी किताबों की बिक्री की थी, जिनमें चीनी नेतृत्व की आलोचना होती थी। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने उनकी रिहाई की मांग की थी। इस पर चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि चीन के आतंरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्वी चीन के निंग्बो शहर की अदालत ने सोमवार को गुई को सजा सुनाई। वर्ष 2018 में उनकी चीनी नागरिकता बहाल कर दी गई थी, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो सका है कि उन्होंने अपनी स्वीडिश नागरिकता छोड़ी है या नहीं। अक्टूबर से दिसंबर 2015 के दौरान 55 वर्षीय गुई हांगकांग से गायब हो गए थे। वह बाद में चीन में दिखाई दिए। उस अवधि के दौरान चीन के सियासी नेतृत्व पर ऐसी कई किताबें प्रकाशित हुई थीं, जो हांगकांग में खूब चर्चित हुई थीं। (रायटर)

### ब्रिटेन के शीर्ष जज ने देखी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही

**नई दिल्ली :** ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष लॉर्ड रॉबर्ट जॉन रीड ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही देखी। न्यायमूर्ति रीड, जो 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' पर न्यायाधीशों के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए हैं, मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के साथ भरी अदालत में लगभग 15 मिनट तक बैठे रहे। सोमवार की कार्यवाही शुरू होने से पहले अदालत के एक अधिकारी ने एलान किया कि ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष लॉर्ड रीड मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों के साथ डायस साझा करेंगे। तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख अदालती कार्यवाही के अंत में किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट रूम में जस्टिस रीड का स्वागत किया। पीठ ने तब मध्यस्थता का एक मामला उठाया, जिस पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बहस की। कुछ मामलों को लेने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्कॉटलैंड के जस्टिस रीड को 11 जनवरी को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। (प्रेट्र)

लॉर्ड रॉबर्ट जॉन रीड। फाइल

# दो लाख लोगों की जांच करेगा दक्षिण कोरिया

**कोरोना का कहर** ▶ चीन के बाद वायरस से यहां प्रभावित हैं सबसे ज्यादा 977 लोग

### राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा-हालात गंभीर, दस की हो चुकी है मौत

**सियोल, एजेंसियां :** दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के केंद्र में आए एक चर्च से जुड़े दो लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जाएगी। चीन के बाद दक्षिण कोरिया वायरस के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यूरोप और पश्चिम एशिया में भी मामले बढ़ रहे हैं। ईरान और इटली में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से यह वायरस अब पूरे चीन समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। थाइलैंड में भी 37 लोग संक्रमित पाए गए हैं।

दक्षिण कोरिया में 144 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या बढ़कर 977 हो गई है। अब तक दस लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा कि हालात गंभीर होते जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के चौथे सबसे बड़े शहर डेगू में जितने मामले सामने आए हैं, उनमें से 68 फीसद का संबंध शहर के शिनचोंजी चर्च से बताया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि इसी चर्च से जुड़ी एक 61 वर्षीय महिला से वायरस फैला है। चर्च ने एक बयान में बताया कि अधिकारियों को सदस्यों की सूची मुहैया कराई जाएगी।

ईरान में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमण रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों को विसंक्रमित करने का अभियान चलाया जा रहा है। दवाओं के छिड़काव की यह तस्वीर कोम शहर में स्थित फातिमा मसुमेह की दरगाह की है। यह शिया मुस्लिमों का दूसरा सबसे पवित्र स्थल है। लेकिन इसे मध्य-पूर्व में कोरोना वायरस के फैलने का संभावित केंद्र माना जा रहा है। एएफपी

चर्च से करीब दो लाख 15 हजार लोग जुड़े हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि जल्द ही सभी की जांच की जाएगी। जबकि एक अधिकारी ने कहा कि जांच शुरू हो गई है। रोजाना करीब 13 हजार लोगों की जांच की जा रही है।

**इटली में भी 220 संक्रमित, सात की मौत :** यूरोपीय देश इटली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 220 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सात मौत भी हो चुकी है। रोम में भी पहले मामले की पुष्टि हुई है। इटली के वायरस प्रभावित लोम्बाडी क्षेत्र के कई इलाकों में आवाजाही बंद कर दी गई है। हालात का जायजा लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम भी पहुंची है।

**ईरान में 16 की गई जान, उप स्वास्थ्य मंत्री भी पीड़ित :** ईरान में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। पूरे देश में 195 लोग संक्रमित पाए गए हैं। करीब 900 संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हैरची भी वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। इराक ने भी चीन और ईरान से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।

**जापान में क्रूज सवार चौथे यात्री की मौत :** जापान में क्रूज सवार चौथे यात्री की मौत हो गई। जापान के तट पर तीन फरवरी से खड़े डायमंड प्रिंसेज क्रूज पर करीब 700 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए थे। क्रूज पर कुल 3,711 लोग सवार थे। इनमें 132 भारतीयों समेत 1,100 चालक दल के सदस्य थे। क्रूज से ज्यादातर लोगों को उतार लिया गया है। 14 भारतीय भी संक्रमित पाए गए हैं।

**चीन में नए मामलों में गिरावट :** चीन में गत दिसंबर में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। तब से 80 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,663 की जान भी जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि चीन में 23 जनवरी से लेकर दो फरवरी तक वायरस का प्रकोप शिखर पर रहा, लेकिन अब गिरावट देखी जा रही है।

### वायरस से मुकाबले पर अमेरिका खर्च करेगा 18 हजार करोड़ रुपये

**वाशिंगटन, एएफपी :** अमेरिका का राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए कुल 2.5 अरब डॉलर (करीब 18 हजार करोड़ रुपये) खर्च करने की योजना बना रहा है। वाशिंगटन पोस्ट अखबार के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने संसद से 1.8 अरब डॉलर की आपात खर्च को स्वीकृति देने की मांग की है।

### संभावित महामारी के लिए तैयार रहे विश्व : डब्ल्यूएचओ

**जिनेवा, एएफपी :** विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख ने कहा कि विश्व को कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने की दिशा में कठिन मेहनत करने और संभावित महामारी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि इससे निपटने के लिए हम जो कदम उठा सकते हैं उसके लिए सभी देशों को तैयार रहना चाहिए।

### धार्मिक स्वतंत्रता पर अगले सप्ताह अमेरिकी आयोग करेगा सुनवाई

**वाशिंगटन, प्रेट्र :** अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआइआरएफ) अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। इस दौरान इस पर विचार किया जाएगा कि भारत और म्यांमार जैसे देश किस तरह नागरिकता कानून की आड़ में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं और शोषण, अत्याचार और सामूहिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें कि आयोग ने यह घोषणा उस समय की जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं।

आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस दौरान इस बात पर चर्चा की जाएगी कि भारत और म्यांमार जैसे देशों में नागरिकता कानून की आड़ में किस तरह धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बैठक चार मार्च को प्रस्तावित है। बता दें कि भारत सरकार के अनुसार सीएए के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो सदस्य 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, वे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे।

# नए नियमों के तहत अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाना होगा कठिन

- सोमवार से प्रभावी हो गए हैं नए 'पब्लिक चार्ज रूल'
- अमेरिका प्रति वर्ष करीब 1,40,000 लोगों को देता है ग्रीन कार्ड

**वाशिंगटन, आइएएनएस :** सोमवार से प्रभावी हुए 'पब्लिक चार्ज रूल' के बाद सरकारी सहायता पर निर्भर कानूनी अप्रवासियों के लिए अमेरिका में ग्रीन कार्ड प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। नया नियम उन गैर अप्रवासी आवेदकों पर भी लागू होगा, जो अमेरिका में कुछ और समय तक रहना चाहते हैं या फिर अपने गैर अप्रवासी स्टेटस को बदलना चाहते हैं।

बता दें कि ग्रीन कार्ड (स्थायी निवासी कार्ड) एक ऐसा कार्ड है, जिससे पता चलता है कि आप अमेरिका के एक वैध स्थायी निवासी हैं। फिलहाल अमेरिका प्रति वर्ष करीब 1,40,000 लोगों को ग्रीन कार्ड देता है। इस हिसाब से भारत के खाते में 9800 ग्रीन कार्ड आते हैं। नई आव्रजन प्रणाली में प्रवासियों की आय, आयु और शैक्षणिक योग्यता पर जोर दिया गया है। नए नियम के खिलाफ अमेरिका की विभिन्न अदालतों में अपील अभी भी लंबित हैं, लेकिन इलिनोइस जिला अदालत द्वारा लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद कानून को लागू कर दिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और मेरीलैंड राज्यों की विभिन्न अदालतों द्वारा लगाई गई रोक हटाई थी। नए नियम उन अप्रवासियों पर लागू नहीं होंगे, जो पहले से ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या फिर जिन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन दे रखा है।

अमेरिका में नागरिकता की चाह रखने वाले लोगों को अब आसानी से ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाएगा। शरणार्थी और राजनीतिक शरण मांगने वालों को भी नए नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है।वर्ष 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने शरणार्थियों को आने से रोकने के लिए मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने और अवैध अप्रवासियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही थी। हालांकि पूर्व में उनके समर्थक रहे कुछ आलोचकों को कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे पर पर्याप्त काम नहीं किया है।

# इंडोनेशिया में बाढ़ से बिगड़े हालात, राष्ट्रपति भवन में भी घुसा पानी

**जकार्ता, एपी :** इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। शहर कई इलाकों में पांच फीट तक पानी भरने से घरों और इमारतों में हजारों लोग फंस गए हैं। राष्ट्रपति भवन में भी पानी घुस गया है। शहर की परिवहन व्यवस्था भी पटरी से उतर गई है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अगस विबोवो ने कहा, 'भारी बारिश के चलते ग्रेटर जकार्ता की कई नदियों में बाढ़ आ गई है। इसके चलते कई रिहायशी और कारोबारी इलाकों में पांच फीट तक पानी भर गया है।' एक अधिकारी के अनुसार, 'मंगलवार सुबह बाढ़ का पानी राष्ट्रपति भवन परिसर में भी घुस गया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। पंप के जरिये पानी को निकाला जा रहा है।' जकार्ता में रविवार रात भारी बारिश हुई थी। शहर में स्थित देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिप्टो मंगुनकुसुमो में भी पानी भर गया है।

अस्पताल की कई मशीनें और उपकरण खराब हो गए हैं। विबोवो ने बताया कि कई जिलों में पानी भरने से 300 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। कई इलाकों में बिजली काट दी गई है। टेलीविजन फुटेज में सैनिक और बचावकर्मी रबर की नौका के जरिये बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित इलाकों से निकालते देखे गए। इंडोनेशिया की मौसम एजेंसी ने आगामी दो हफ्ते तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। गत जनवरी में भी जकार्ता पर बाढ़ की मार पड़ी थी। उस समय करीब 60 लोगों की मौत हुई थी। हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। बाढ़ के चलते एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा था।

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सड़कें बाढ़ से जलमग्न होने से लोगों को आवाजाही के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एपी

# मिस्र की शांति के संरक्षक और पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का निधन

- इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ थे अमेरिका के विश्वस्त सहयोगी
- विरोध प्रदर्शनों के बाद 2011 में देना पड़ा था राष्ट्रपति पद से इस्तीफा

**काइरो, एपी :** सत्ता से बेदखल किए जाने से पहले पश्चिम एशिया में स्थायित्व का निरंकुश चेहरा और करीब 30 साल तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे होस्नी मुबारक का मंगलवार को निधन हो गया। वह 91 साल के थे।

मई, 1928 में जन्मे होस्नी मुबारक इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के विश्वस्त सहयोगी थे और इजरायल के साथ मिस्र की शांति के संरक्षक थे। जनवरी, 2011 में काइरो के तहरीर चौक (स्क्वायर) और अन्य स्थानों पर मिस्र के लाखों लोगों ने 18 दिनों तक सड़कों पर उतरकर उनके निरंकुश कुशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके बाद 11 फरवरी, 2011 को उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उनके सत्ता से हटने के बाद मिस्र को कई साल तक अराजकता और अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ा। सेना का मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ संघर्ष छिड़ गया जिसे मुबारक ने लंबे समय तक निष्प्रभावी बना रखा था। उनके सत्ता से हटने के करीब ढाई साल बाद अब्देल फतह अल सिसी ने मिस्र के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल कर दिया और 2011 के विरोध प्रदर्शनों के बाद नागरिकों को हासिल आजादी वापस ले ली।

होस्नी मुबारक। फाइल/रायटर

मिस्र के सरकारी टीवी ने बताया कि मुबारक की मृत्यु काइरो के अस्पताल में हुई जहां उनकी एक सर्जरी की गई थी। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं थीं, लेकिन उनका विवरण नहीं दिया गया। राष्ट्रपति अल सिसी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 1973 में इजरायल के साथ हुए युद्ध में उनकी सेवाओं की प्रशंसा की। लेकिन उन्होंने मुबारक के करीब तीन दशक के शासनकाल का कोई उल्लेख नहीं किया। मुबारक ने 1973 के युद्ध में मिस्र की वायुसेना का नेतृत्व किया था। राष्ट्रपति ने बुधवार से तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुबारक के निधन पर गहरा दुख जताते हुए मुबारक को अपना निजी मित्र बताया। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि मुबारक ने अपना जीवन अपनी मातृभूमि की सेवा और दुनिया में सच्चाई व न्याय के लिए लगा दिया। फलस्तीनी लोगों का मुद्दा उनके लिए शीर्ष पर था।

### युद्ध अपराध में अपने जवानों की जांच कर रहा है ऑस्ट्रेलिया

**सिडनी, एएफपी :** अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान अपने जवानों द्वारा किए गए 50 से अधिक युद्ध अपराधों की ऑस्ट्रेलिया जांच कर रहा है। जिन मामलों की जांच की जा रही, उनमें नागरिकों और कैदियों की हत्या भी शामिल है। रक्षा मंत्री लिंडा रेनाल्ड्स ने उम्मीद जताई कि कुछ महीनों के अंदर देश के रक्षा प्रमुख को जांच संबंधी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के विशेष बलों द्वारा अफगानिस्तान में कथित दुर्व्यवहार की चार जांचें चल रही हैं।

ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा बलों के इंस्पेक्टर जनरल की एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 55 अलग-अलग घटनाओं की जांच की जा रही है। जिन मामलों की जांच की जा रही है, उनमें निर्दोषों की हत्या शामिल है। हालांकि जांच के दायरे में युद्ध के समय लिए गए फैसलों को शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि युद्ध अपराध का आरोप लगने के बाद 2016 में इस संबंध में जांच शुरू की गई थी। जज पॉल ब्रेरेटन की अगुआई में चल रही जांच के तहत 338 गवाहों को बुलाया गया है।

# विदेश में इलाज करा रहे नवाज शरीफ की नहीं बढ़ेगी जमानत अवधि

- पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने चिकित्सकीय आधार पर लिया फैसला
- 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए लंदन गए थे पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ

**लाहौर, प्रेट्र :** विदेश में इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत अवधि नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की सरकार ने चिकित्सकीय आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य के कानून मंत्री राजा बशारत ने कहा कि शरीफ की जमानत बढ़ाने के लिए कोई नैतिक, कानूनी और ठोस आधार मौजूद नहीं है। फिलहाल शरीफ का लंदन में इलाज चल रहा है।

सत्तारूढ़ तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में चल रहे विवाद के बीच तीन बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 19 नवंबर को इलाज के लिए लंदन गए थे। 23 दिसंबर को उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट द्वारा दी गई चार सप्ताह की अवधि की समाप्ति पर अपनी जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस पर शरीफ की जमानत चार सप्ताह और बढ़ा दी गई। बाद में शरीफ की जमानत अवधि बढ़ाने पर निर्णय लेने के लिए पंजाब सरकार ने चार सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। समिति ने शरीफ से नए सिरे से चिकित्सा रिपोर्ट मांगी।

नवाज शरीफ। फाइल

प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. यास्मीन राशिद की मौजूदगी में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए बशारत ने कहा कि समिति ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ की जमानत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ को आठ सप्ताह की जमानत दी थी। इसके बाद आठ सप्ताह और बीत गए और तब से उनकी जमानत पर चर्चा चल रही है।

पंजाब सरकार के कानून मंत्री बशारत के अनुसार, आज तक नवाज को लंदन के किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि पीएमएल-एन सुप्रीमो के स्वास्थ्य के बारे में सरकार के साथ किसी भी प्रकार की रिपोर्ट साझा नहीं की गई। बशारत ने कहा कि पंजाब सरकार अब अपना फैसला केंद्र सरकार के साथ साझा करेगी, जो इस मामले पर अंतिम फैसला करेगी। बता दें कि जनवरी में लंदन के एक रेस्तरां में शरीफ की परिवार के साथ बैठे एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसी के बाद से उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर सवाल उठाए जाने लगे थे।

### कतर ने पाकिस्तान को शांति समझौते के लिए किया आमंत्रित

**इस्लामाबाद, प्रेट्र :** कतर ने अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में शनिवार को महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान मौजूद रहने के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया है।

'रेडियो पाकिस्तान' के अनुसार पाकिस्तान में कतर के राजदूत सक्र बिन मुबारक ने कतर के विदेश मंत्री की ओर से पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को मंगलवार को आमंत्रित किया। कुरैशी ने अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि पाकिस्तान का हमेशा से ही यह विचार रहा है कि अफगान संघर्ष का कोई सैन्य हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर ने अफगान सुलह प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि शांति समझौते से वार्ता में सहायता मिलेगी।

### कुवैत ने मनाया 59वां स्वतंत्रता दिवस

अरब प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर भाग में स्थित कुवैत ने मंगलवार को अपना 59वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ-साथ खाड़ी युद्ध के खत्म होने का जश्न मनाया। लेकिन वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने के कारण कुवैत ने देश में हर साल होने वाले दो दिनों के अवकाश को रद कर दिया। बता दें कि कुवैत में भी कोरोना के तीन संदिग्ध मामले प्रकाश में आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग बेहद सतर्कता बरत रहा है। एएफपी

### हॉलीवुड के फिल्म निर्माता हार्वे विंस्टीन अस्पताल में भर्ती

**वाशिंगटन, एएनआइ :** यौन अपराध और दुष्कर्म का दोषी ठहराए जाने के बाद हॉलीवुड के फिल्म निर्माता हार्वे विंस्टीन ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क के बेलव्यू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म निर्माता ने सीने में दर्द, घबराहट और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत की थी। विंस्टीन के वकील ने बताया कि अब उनकी तबीयत ठीक है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें सुधार केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

कई आरोपों के बाद न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने सोमवार को विंस्टीन को दोषी ठहराया था। उन्हें मिरियम हेली की गवाही के आधार पर पहली डिग्री के यौन अपराध और अभिनेत्री जेसिका मन की गवाही पर तीसरी डिग्री के दुष्कर्म का दोषी पाया था। हालांकि उन्हें पहली डिग्री के दुष्कर्म जैसे ज्यादा गंभीर आरोपों का दोषी नहीं पाया गया।

# ईयू ब्रेक्जिट सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करेगा : बर्नियर

- समझौते के प्रारूप को यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने दी मंजूरी
- 31 जनवरी को यूरोपीय संघ से अलग हो गया था ब्रिटेन

**ब्रसेल्स, एएफपी :** यूरोपीय संघ ने मंगलवार को कहा कि वह ब्रिटेन के साथ किसी भी कीमत पर ब्रेक्जिट सौदा नहीं करेगा। संघ निष्पक्ष और संतुलित व्यापार समझौता चाहता है।

यूरोपीय संघ (ईयू) से ब्रिटेन के अलग होने के बाद किए जाने वाले व्यापार समझौते के प्रारूप पर सहमति के लिए संघ के मंत्रियों की बैठक के बाद ईयू के वार्ताकार माइकल बर्नियर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'हम किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे।' ईयू बराबरी के स्तर पर तैयार नियमों को मानेगा और ब्रिटिश जल क्षेत्र में यूरोपीय संघ के मछुआरों के प्रवेश की व्यवस्था चाहेगा। सोमवार को शुरू हो रही वार्ता के लिए मंत्रियों ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समझौता वार्ता मुश्किल, शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगी।

बर्नियर की तरफ से तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर ब्रिटेन चाहता है कि यूरोपीय बाजार में उसके सामान को शुल्क मुक्त प्रवेश मिले तो उसे उनके मानकों का पालन करना होगा। लंदन ने इस अवधारण को तत्काल खारिज कर दिया है।

बता दें कि इस साल 31 जनवरी को ब्रिटेन 28 देशों के यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। लेकिन एक साल की ट्रांजिशन अवधि के दौरान वह पहले की तरह ही ईयू के साथ व्यापार करता रहेगा। इस ट्रांजिशन अवधि के खत्म होने के बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के व्यापारिक रिश्तों को लेकर एक तंत्र विकसित करने की कोशिश की जा रही है।

मुझे उम्मीद है कि मेरा चयन ऑस्ट्रेलिया की टी-20 विश्व कप टीम में हो जाएगा।
— केन रिचर्डसन, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज

## देखना चाहता हूं, कौन सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ेगा : हक

**लाहौर, आइएएनएस** : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा है कि उन्हें इंतजार है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को कौन बल्लेबाज तोड़ता है। सचिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 664 मैचों में कुल 34,357 रन बनाए हैं। सचिन ने अपने करियर में 200 टेस्ट और 463 वनडे के अलावा एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय भी खेला था।

# एशिया एकादश में विराट सहित छह भारतीय खेलेंगे

### विश्व एकादश और एशिया एकादश टीमों की हुई घोषणा 21 और 22 मार्च को होने हैं दो टी-20 मुकाबले

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली:** भारतीय कप्तान विराट कोहली को मंगलवार को एशिया एकादश टीम में शामिल किया गया है। अगले महीने ढाका में 'बंगबंधु-100 इयर सेलिब्रेशन' के तहत फाफ डुप्लेसिस की अगुआई वाली विश्व एकादश के खिलाफ दो मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोहली को एक मैच के लिए टीम में शामिल किया है, लेकिन यह उनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा। बीसीसीआइ ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। यह मुकाबला 21 और 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इन मैचों का आयोजन बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशताब्दी के जश्न के तौर पर किया जा रहा है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने कहा हमें भारत की ओर से चार नाम मिले हैं। हमने इसको लेकर करार नहीं किया है लेकिन रिषभ पंत, कुलदीप यादव, शिखर धवन और मुहम्मद शमी का आना माना जा रहा है। भारत की ओर से कहा गया है कि केएल राहुल और विराट कोहली दोनों एक-एक मैच खेलेंगे लेकिन यह अभी तय नहीं हुआ है। बीसीबी चाहता है कि कोहली दोनों टी-20 मुकाबलों का हिस्सा रहें लेकिन भारतीय टीम के कठिन कार्यक्रम को देखते हुए यह कोहली पर निर्भर करेगा कि वह दोनों मैच खेलेंगे या नहीं। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने कहा कि कोहली का नाम भेज दिया गया है लेकिन यह फैसला कोहली को ही लेना है और वह इस पर फैसला बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली से बात करने के बाद लेंगे। भारतीय टीम फिलहाल न्यूजीलैंड दौरे पर है। एक सप्ताह बाद न्यूजीलैंड दौरे का अंत हो जाएगा। इसके बाद भारत 12 मार्च से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। जिसका पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 15 मार्च को लखनऊ और तीसरा मुकाबला 18 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा। इसके बाद 29 मार्च से आइपीएल शुरू होगा। जहां तक खिलाड़ियों की उपलब्धता की बात है तो बीसीसीआइ अध्यक्ष गांगुली ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि हम चार से पांच खिलाड़ियों को भेज सकते हैं। विश्व एकादश में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड जैसे नाम शामिल हैं। एशिया एकादश में चार बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान, तमीम इकबाल, मुश्फिकुर रहीम और लिटन दास शामिल हैं। एशियाई एकादश में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है।

**एशिया एकादश टीम:** लोकेश राहुल, धवन, विराट कोहली, पंत, कुलदीप, शमी, तिसारा, मलिंगा, राशिद खान, मुजीब, मुस्तफिजुर, तमीम इकबाल, मुश्फिकुर, लिटन दास और संदीप लामिछाने।

**विश्व एकादश टीम:** एलेक्स हेल्स, गेल, डुप्लेसिस (कप्तान), पूरन, ब्रेंडन टेलर, जॉनी बेयरस्टो, कीरोन पोलार्ड, आदिल राशिद, शेल्डन कॉटरेल, लुंगी नगिदी, एंड्रयू टाइ और मिशेल मैक्लेनघन।


मुहम्मद शमी ● फाइल फोटो, प्रेट्र


कुलदीप यादव ● फाइल फोटो, एपी


रिषभ पंत ● फाइल फोटो, एएफपी


लोकेश राहुल ● फाइल फोटो, प्रेट्र


शिखर धवन ● फाइल फोटो, एपी


विराट कोहली ● फाइल फोटो, प्रेट्र

## एक नजर में

### बुरी यादों के साथ फिर केपटाउन लौटेंगे स्मिथ, वार्नर

**केपटाउन:** ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर बुधवार को न्यूलैंड्स के उसी मैदान पर उतरेंगे जहां उन्हें गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया था। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला इसी मैदान पर खेला जाना है। मैच के लिए हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को किसी दुर्व्यवहार से बचाया जा सके। स्मिथ और वार्नर उस समय क्रमशः टीम के कप्तान और उप कप्तान थे जब 24 मार्च 2018 को तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के दौरान कैमरून बैनक्राफ्ट को टेलीविजन पर रेगमाल (सैंडपेपर) को गेंद पर रगड़ते देखा गया था। स्मिथ और बैनक्राफ्ट ने उसी शाम संवाददाता सम्मेलन में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने जानबूझ कर गेंद से छेड़छाड़ की थी। बाद में पता चला कि इस योजना में वार्नर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तीनों खिलाड़ियों को इसके बाद निलंबित कर दिया गया था। (प्रेट्र)

### घोषाल करेंगे टीम की अगुआई

**नई दिल्ली:** सौरव घोषाल और जोशना चिनप्पा 25 से 29 मार्च तक मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले जाने वाली 20वीं एशियाई टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप में पुरुष और महिला टीमों की अगुआई करेंगे। घोषाल 13 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और उनकी मौजूदा विश्व रैंकिंग 13वीं है जबकि 18 बार राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली जोशना की रैंकिंग 12वीं है। भारतीय स्क्वॉश रैकेट महासंघ (एसआरएफआइ) द्वारा घोषित पुरुषों की टीम में घोषाल के अलावा अभिषेक प्रधान, हरिंदर पाल संधू और अभय सिंह को चुना गया है जबकि महिलाओं में जोशना के साथ तन्वी खन्ना, सुनयना कुरुविला और सान्या वत्स को टीम में जगह दी गई है। खिलाड़ियों का चयन हाल ही में संपन्न हुई 77वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर हुआ। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए एसएफआरआइ ने डेविड पालमेर को भारतीय राष्ट्रीय टीम का टूर्नामेंट आधारित कोच नियुक्त किया। (प्रेट्र)

### भारत में ड्रिबल-ए-थॉन

**मुंबई:** नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) ने मंगलवार को भारत में लीग के पहले ड्रिबल-ए-थॉन का अनावरण किया। यह एक बास्केटबॉल चैलेंज टूर्नामेंट है जिसमें छह साल से अधिक आयु के प्रतिभागी एक किलोमीटर के कोर्स पर बास्केटबॉल को ड्रिबल करने की चुनौती का सामना करेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 29 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी। इसके बाद यह अगले कुछ महीनों तक जयपुर और गाजियाबाद सहित देश के कई अन्य शहरों में आयोजित होगा। (आइएएनएस)

### बेंगलुरु का सामना माजिया से

**बेंगलुरु:** पहले चरण में शिकस्त के बाद बेंगलुरु एफसी की टीम बुधवार को यहां मालदीव के माजिया एस एंड आर क्लब के खिलाफ एएफसी कप के प्ले ऑफ के दूसरे चरण में हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। माले में 19 फरवरी को हुए पहले चरण के मुकाबले में बेंगलुरु एफसी के मुख्य मैनेजर कार्ल्स कुआड्रेट ने अकादमी के कुछ खिलाड़ियों को खिलाने का फैसला किया था और टीम को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। बुधवार को अपने गढ़ कांतीर्वा स्टेडियम में हालांकि बेंगलुरु एफसी की टीम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। चोट के बाद बेंगलुरु एफसी के कप्तान सुनील छेत्री भी इस मैच में वापसी करेंगे जबकि एटीके के खिलाफ इंडियन सुपर लीग के पिछले मैच में कोच ने अधिकतर नियमित खिलाड़ियों को आराम दिया था। (प्रेट्र)

### न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय कप्तान ने अपने बल्लेबाजों से बेहद रक्षात्मक रवैया छोड़ने की अपील की

# पुजारा एंड कंपनी को आक्रामक देखना चाहते हैं कोहली

**वेलिंगटन, प्रेट्र:** भारतीय कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले, अपने बल्लेबाजों से बेहद रक्षात्मक रवैया छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि विदेशी दौरों में इस तरह के खेल से कभी फायदा नहीं मिलता। भारत को बेसिन रिजर्व में पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वह तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर दोनों पारियों में 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाया था।

कोहली ने हार के बाद कहा कि मुझे लगता है कि बल्लेबाजी इकाई के तौर पर हम जिस तरीके का उपयोग करते हैं, उसे सही करना होगा। मुझे नहीं लगता कि सतर्क होने या बेहद सावधानी बरतने से मदद मिलेगी क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आप अपने शॉट नहीं खेल पाओ। दूसरी पारी में तकनीकी तौर पर मंझे हुए बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने बेहद रक्षात्मक रवैया अपनाया और 81 गेंदों पर 11 रन बनाए। हनुमा विहारी ने 79 गेंदें खेलीं और 15 रन बनाए। बल्लेबाजी यूनिट किसी भी समय लय हासिल करने में नाकाम रही। पुजारा ने बीच में 28 गेंद तक एक भी रन नहीं बनाया और ऐसे में दूसरे छोर पर खड़े मयंक अग्रवाल को ढीले शॉट खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय कप्तान को यह कतई पसंद नहीं है कि आप दौड़कर एक रन न लो और किसी अच्छी गेंद का इंतजार करो जो आपका विकेट ही ले लेगी। कोहली ने कहा कि आपको संदेह पैदा होगा, अगर इन परिस्थितियों में एक रन भी नहीं बन रहा है, आप क्या करोगे? आप केवल यह इंतजार कर रहे हो कि कब वह अच्छी गेंद आएगी जो आपका विकेट ले लेगी। भारतीय कप्तान को विरोधी टीम पर हावी होने के लिए जाना जाता है और वह चाहते हैं कि उनके कुछ बल्लेबाज भी इसका अनुसरण करें। उन्होंने कहा कि मैं परिस्थितियों का आकलन करता हूं, अगर मैं देखता हूं विकेट पर घास है तो मैं हमलावर तेवर दिखाता हूं ताकि मैं अपनी टीम को आगे ले जा सकूं। कोहली ने कहा कि अगर आप सफल नहीं होते, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी सोच सही थी आपने कोशिश की लेकिन अगर इससे फायदा नहीं मिला तो उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सतर्क रवैये से कभी फायदा मिलता है विशेषकर विदेशी पिचों पर।

**मैकमिलन बोले, भारतीय बल्लेबाज ऐसे खेले, जैसे भारत में खेल रहे हों:** न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रेग मैकमिलन ने मंगलवार को कहा कि भारतीय बल्लेबाज इस तरह से खेल रहे थे मानो वे भारत में खेल रहे हों और उनकी इस तरह की बल्लेबाजी काम नहीं आई। भारतीय बल्लेबाज विपरीत परिस्थितियों में नहीं चल पाए। मैकमिलन ने कहा कि वे जिस तरह से खेले उसमें किसी तरह का सामंजस्य नहीं बिठाया।

### जेमिसन के प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड टीम प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ीं

**वेलिंगटन:** पहले टेस्ट में भारत को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले न्यूजीलैंड के क्रिकेटर काइली जेमिसन ने टीम प्रबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे छह फुट आठ इंच के इस गेंदबाज ने अपनी गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। छोटी गेंद फेंकने में माहिर नील वैगनर के स्थान पर टीम में शामिल किए गए जेमिसन ने 39 रन देकर चार विकेट लिए। उन्हें अपने कद की वजह से काफी उछाल मिला और इसने भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखा। इसके बाद उन्होंने बल्ले से भी जौहर दिखाया। उन्होंने 44 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली। इस पारी में चार छक्के भी शामिल थे। निचले क्रम के बल्लेबाजों काफी सधे अंदाज में बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड के आखिरी तीन खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा रन जोड़े और टीम का स्कोर 348 तक पहुंच पाया। 204 टेस्ट विकेट लेने वाले वैगनर पितृत्व अवकाश पर हैं। वह शनिवार से क्राइस्टचर्च में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही मैट हेनरी भी चयन के लिए उपलब्ध होंगे। इसने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए चयन की एक मुश्किल पैदा कर दी है। कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि काइली अपने पदार्पण मैच में शानदार थे। उन्होंने कहा कि हमने सीमित ओवरों के प्रारूप में उन्हें खेलते देखा था। हमने महसूस किया था कि कैसे वह अलग-अलग एरिया में योगदान दे सकते हैं।

### भारतीय बल्लेबाजी से थोड़ा हैरान हुआ : स्टीड

**वेलिंगटन :** न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने कहा कि पहले टेस्ट मैच में भारत के आसानी से आत्मसमर्पण कर देने से उन्हें थोड़ा हैरानी हुई लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वे क्राइस्टचर्च में दमदार वापसी करेंगे। भारत पहले टेस्ट मैच में 165 और 191 रन पर आउट हो गया जिसके कारण उसे 10 विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्टीड ने कहा कि यह थोड़ा हैरान करने वाला था लेकिन ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि हमने उसके खिलाड़ियों पर लंबे समय तक दबाव बनाए रखा। ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी हमारी परिस्थितियों में बेजोड़ हैं। ट्रेंट आठ सप्ताह तक बाहर रहे और उनके आने से टीम को मजबूती मिली। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच ने भारतीय टीम को आगाह किया कि न्यूजीलैंड का दौरा करना कुछ अन्य देशों में खेलने की तरह मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि टीमें यह स्वीकार करें कि दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से की तरह न्यूजीलैंड में खेलना भी मुश्किल है। यह गर्व की बात है। स्टीड ने कहा कि चौथे दिन सुबह अजिंक्य रहाणे को सस्ते में आउट करना महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके बाद उन्हें लग गया था कि न्यूजीलैंड जल्द ही उनकी पारी समाप्त कर देगा। उन्होंने कहा कि हमने मैच में महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लिए। हमने रहाणे को आउट किया और इससे हमारा विश्वास बढ़ा। भारतीय कप्तान विराट कोहली चाहते हैं कि उनके बल्लेबाज सकारात्मक रवैया अपनाए और स्टीड ने कहा कि भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम हावी होकर खेलना पसंद करती है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय बल्लेबाज अधिक दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे और यह हमारे गेंदबाजों के लिए चुनौती होगी क्योंकि भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम दमदार वापसी करेगी। नील वैगनर अपने बच्चे के जन्म के कारण पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। उनकी दूसरे मैच में वापसी हुई है। ऐसे में न्यूजीलैंड के चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने की संभावना है। स्टीड ने कहा कि चयन को लेकर इस तरह की दुविधा अच्छी होती है क्योंकि नील वैगनर की वापसी हुई है।

### तैराक साध्वी ने जीते दो स्वर्ण पदक

**भुवनेश्वर, प्रेट्र:** तैराक साध्वी धूरी ने दो स्वर्ण जबकि मिहिर आंब्रे ने मंगलवार को यहां अपना दूसरा खिताब जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पांचवें दिन पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया।

सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के नाम अब सात स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य के कुल 14 पदक है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के सिद्धांत सेजवाल ने भी तैराकी में स्वर्ण जीता जिससे टीम छह स्वर्ण, सात रजत और पांच कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है। बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी (छह स्वर्ण, पांच रजत, एक कांस्य) तीसरे स्थान पर है जबकि सोमवार को तालिका में शीर्ष पर काबिज रहे अमृतसर स्थित गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी (छह स्वर्ण, एक रजत, पांच कांस्य) चौथे स्थान पर फिसल गया। वहीं, वॉलीबॉल छोड़कर तीरंदाजी से जुड़ने के सिर्फ दो साल के अंदर कृत्तिका शर्मा ने व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग का खिताब जीत लिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रही 19 साल की कृतिका ने बारिश के बीच अपने करियर की सबसे बड़ी सफलता हासिल की। कृतिका की नजरें अब इस महीने होने वाले सीनियर विश्व कप ट्रायल पर टिकी है।

# केएल राहुल के टेस्ट सीरीज से बाहर होने पर कपिल ने उठाए सवाल

क्रिकेट डायरी

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली :** पूर्व कप्तान कपिल देव ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद भारतीय टीम की आलोचना की है। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच में भारत को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेट से हराया था। कपिल ने कहा कि हमें न्यूजीलैंड की तारीफ करनी होगी, वह शानदार क्रिकेट खेल रही है। तीन वनडे और टेस्ट मैच में उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली। अगर हम मैच को विश्लेषण करेंगे तो, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई इतने बदलाव कैसे कर सकता है। हर मैच में लगभग नई टीम होती है। उन्होंने कहा कि टीम में कोई भी स्थाई नहीं है। अगर स्थान को लेकर सुरक्षा की भावना नहीं है तो इसका असर खिलाड़ियों की फॉर्म पर पड़ेगा।

कपिल ने कहा कि बल्लेबाजी में कई बड़े नाम हैं लेकिन फिर भी आप दोनों पारियों में 200 का स्कोर नहीं कर सके, इसका मतलब है कि आपने स्थितियों से तालमेल नहीं बैठाया है। आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रणनीति पर देना होगा। कपिल साथ ही लोकेश राहुल के टेस्ट टीम में न होने से नाराज हैं। राहुल को टी-20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था और इस सीरीज में भारत ने कीवी टीम को 5-0 से मात दी थी।

विश्व कप विजेता कप्तान ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, जब हम खेले थे और अब जो हो रहा है उसमें काफी अंतर है। आप जब टीम को बनाते हो तो आपको अपने खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देना होता है। जब आप कई सारे बदलाव करते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं होता। प्रबंधन हर प्रारूप के लिए विशेष खिलाड़ी में विश्वास रखता है।


कपिल देव ● फाइल फोटो, ट्विटर

**आइपीएल के लिए दो मार्च से ट्रेनिंग शुरू करेंगे धौनी:** चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी आइपीएल के 13वें सत्र से पूर्व अन्य खिलाड़ियों के साथ यहां दो मार्च से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। पिछले साल जून-जुलाई में आइसीसी के 50 ओवर के विश्व कप के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 38 साल के धौनी के खेलने को लेकर अटकलों का दौर जारी है। धौनी एमए चिदंबरम स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। आइपीएल 2020 की शुरुआत चेन्नई सुपरकिंग्स और गत चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच 29 मार्च को मुंबई में होने वाले मुकाबले के साथ होगी। सीएसके के सीईओ केएस विश्वनाथन ने बताया कि धौनी उपलब्ध खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करेंगे जबकि टीम का पूर्ण तैयारी शिविर 19 मार्च से शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार पूर्व भारतीय कप्तान धौनी के सुरेश रैना और अंबाती रायुडू जैसे खिलाड़ियों के साथ दो हफ्ते अभ्यास करने की उम्मीद है। इसके बाद वह ब्रेक लेंगे और फिर वापस लौटेंगे। रैना और रायुडू यहां पिछले लगभग तीन हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहे हैं।

**ओझा विदेशी लीगों में खेलने के इच्छुक:** भारतीय टीम के बायें हाथ के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा विदेशी टी-20 लीगों में खेलने के इच्छुक हैं जिसके विकल्पों की तलाश के लिए वह बीसीसीआइ की अनुमति लेंगे। ओझा ने पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने यहां डीवाई पाटिल टी-20 कप के इतर कहा कि मेरे दिमाग में कई चीजें हैं। मैं अभी कमेंट्री कर रहा हूं। मैं बीसीसीआइ से सलाह लूंगा कि क्या मैं भारत से बाहर कुछ लीगों में खेल सकता हूं। मैं ऐसा तभी करूंगा जब मुझे इसके लिए अनुमति मिलेगी।

# ट्रंप के बयान पर अब वॉन और पीटरसन ने ली चुटकी

**नई दिल्ली, जेएनएन:** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को सोशल मीडिया पर छाए रहे। उन्होंने अहमदाबाद के मोटरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप में क्रिकेट दिग्गजों सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का जिक्र किया। हालांकि ट्रंप ने सचिन के नाम का गलत उच्चारण सूचिन किया। अब इंग्लैंड के दो दिग्गज खिलाड़ियों माइकल वॉन और केविन पीटरसन ने इस उच्चारण पर चुटकी ली है।

माइकल वॉन ने ट्विटर पर लिखा कि मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि ट्रंप जब कभी पाकिस्तान पहुंचेंगे तो पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमां के नाम का उच्चारण किस तरह करेंगे। पीटरसन ने भी ट्रंप को ट्रोल किया। उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन होस्ट पीयर्स मोर्गन से कहा कि कृपया अपने दोस्त से कहो कि महान लोगों का नाम लेने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया करें? यहां तक कि आइसीसी ने भी इसका मजाक बनाया था। उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि क्या किसी को तेदुलकर के नाम का कोई और उच्चारण पता है?

**बटलर टेस्ट क्रिकेट में भी खुद को साबित करने के लिए प्रतिबद्ध:** वनडे क्रिकेट की अपनी सफलता को टेस्ट क्रिकेट में दोहराने में नाकाम रहे इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने कहा कि वह खेल के सबसे लंबे प्रारूप में भी खुद को साबित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

**कदम** कई बीमारियों से जूझ रहे हैं भारत के दिग्गज तीरंदाज लिंबाराम, खेल मंत्री ने लिया संज्ञान, निजी अस्पताल ने कहा मुफ्त में करेंगे इलाज

# पद्मश्री लिंबा राम की मदद के लिए आगे बढ़े हाथ

**अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली**

जिंदगी जितनी भी जटिल हो, कोई ना कोई हाथ थामकर मुश्किल रास्तों से मंजिल तक ले जाने वाला सारथी मिल ही जाता है। ऐसे ही सारथी ओलंपियन, पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी तीरंदाज लिंबा राम को मिले, जो इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं।

रीढ़ और गर्दन की हड्डी में परेशानी के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में लाइन लगाने से मजबूर लिंबा राम की दर्द भरी कहानी दैनिक जागरण ने मंगलवार के अंक में प्रकाशित की थी। बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजू ने इसका संज्ञान लिया। इसके साथ ही गाजियाबाद के कौशांबी में स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्यकारी निदेशक शुभांग अरोड़ा ने भी उनके मुफ्त इलाज की घोषणा की है। शुभांग ने कहा कि मैंने सुबह-सुबह दैनिक जागरण में इस खबर को पढ़ा और उसके तुरंत बाद अपने अस्पताल के क्लीनिकल डायरेक्टर डॉ. राहुल शुक्ला को फोन कर लिंबा के इलाज की निशुल्क व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। जब मुझे पता चला कि लिंबा राम इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं तो उनकी पत्नी जैनी से संपर्क किया। लिंबाराम को इलाज के लिए अस्पताल बुलाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं जैनी ने कहा कि यशोदा अस्पताल की तरफ से मुझे फोन आया था। अभी मैंने लिंबा से बात नहीं की है क्योंकि उनको मानसिक समस्या है। मैं उनसे बात करके यशोदा अस्पताल को अवगत कराऊंगी। जैनी ने कहा कि दैनिक जागरण ने जो भी हमारे लिए किया है मैं उसे लिए उन्हें दिल से धन्यवाद देती हूं।

गंभीर दिमाग की बीमारी के कारण दिल्ली के तीन अस्पतालों में चल रहा है इलाज, लिंबा की पत्नी ने कहा, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार का नहीं हुआ कोई फायदा
सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए धक्के खा रहे पद्मश्री लिंबा राम
कौन हैं लिंबा राम
खत्म हो गए 10 लाख
हम चुपचाप लाइन में लगे रहते हैं

25 फरवरी को लिंबा राम की परेशानियों को लेकर छपी रिपोर्ट ● जागरण

यशोदा हॉस्पिटल के कार्यकारी निदेशक शुभांग अरोड़ा ● ट्विटर

# स्वर्ण जीत सकते हैं भारतीय निशानेबाज : बिंद्रा

टोक्यो ओलंपिक डायरी

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली:** ओलंपिक चैंपियन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कहा कि भारतीय निशानेबाजों के पास टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में कई पदक सहित स्वर्ण जीतने की क्षमता है।

37 वर्षीय बिंद्रा ओलंपिक की निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आगामी ओलंपिक के बाद इस क्लब में उनके साथ नए खिलाड़ी जुड़ेंगे। बिंद्रा ने कहा, 'हम ओलंपिक खेलों के लिए जा रहे हैं जहां हमारे पास कई पदक जीतने का मौका होगा। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का वास्तविक मौका होगा।' भारतीय निशानेबाजों के लिए साल 2019 बेहद ही सफल रहा है। भारत ने ओलंपिक के लिए रिकॉर्ड 15 कोटा हासिल किए हैं। रियो ओलंपिक (2016) में निशानेबाजी टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा था जिसके बाद बिंद्रा की अगुआई में समिति के निर्देश पर कुछ बदलाव किए गए थे।

### ओलंपिक से पहले निरंतर प्रदर्शन करना होगा : हरमनप्रीत

**नई दिल्ली:** भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मंगलवार को कहा कि टोक्यो ओलंपिक को देखते हुए टीम को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हरमनप्रीत ने कहा, 'हमने पिछले मैचों में क्वार्टर के बीच में धीमे खेल और लय बरकरार नहीं रखने का खामियाजा भुगता है। ओलंपिक में जाने से पहले यह हमारे लिए चिंता का विषय है। कोच (ग्राहम रीड) का मानना है कि हमें सर्कल भेदने, सर्कल के बाहर विरोधी खिलाड़ी से निपटने और ज्यादा पेनाल्टी कॉर्नर नहीं देने पर काम करना होगा। एक लंबे शिविर से इन सभी चीजों में सुधार करने का मौका मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया की शीर्ष तीन टीमों के खिलाफ अच्छे परिणाम से हमारा मनोबल बढ़ा है लेकिन बहुत सारे विभाग हैं जो अभी भी चिंता का सबब बने हुए है।'

हरमनप्रीत सिंह ● ट्विटर

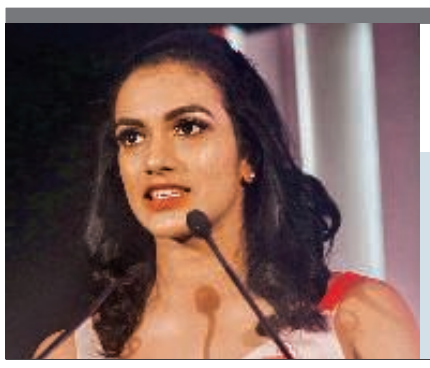

## भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनी सिंधु

**अमरावती, आइएएनएस :** विश्व चैंपियन भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी-करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सिंधू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में मंगलवार को यहां एंटी-करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इस अवसर पर भ्रष्टाचार रोको शीर्षक से एक वीडियो भी जारी किया गया।

भारत की जेमिमाह रोड्रिगेज बेहद ही शानदार क्रिकेटर हैं। उन्होंने काफी प्रभावित किया है।
– शकीरा सेलमैन, वेस्टइंडीज की पूर्व क्रिकेटर



# पेस डेविस कप टीम में बरकरार

**टेनिस डायरी** ▶ एआइटीए ने क्रोएशिया के खिलाफ घोषित की पांच सदस्यीय टीम

### भारतीय टीम में दिविज शरण होंगे रिजर्व खिलाड़ी

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली**

अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) की चयन समिति ने क्रोएशिया के खिलाफ आगामी डेविस कप मुकाबले के लिए मंगलवार को घोषित पांच सदस्यीय टीम में अनुभवी लिएंडर पेस को बरकरार रखा है। इसके अलावा दिविज शरण टीम के रिजर्व खिलाड़ी होंगे।

एआइटीए ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) को भारतीय टीम की अंतिम सूची भेज दी। क्वालीफायर्स ग्रुप के ये मुकाबले छह और सात मार्च को खेले जाएंगे। भारतीय टीम अभी 24 देशों के क्वालीफायर्स ग्रुप में है जहां क्रोएशिया शीर्ष वरीयता प्राप्त टीम है। क्वालीफायर्स ग्रुप की 12 विजेता टीमें इस साल के आखिर में होने वाले डेविस कप फाइनल्स के लिए क्वालीफाई करेंगी जबकि हारने वाली टीमों को विश्व ग्रुप एक में रखा जाएगा। सुमित नागल, प्रजनेश गुणेश्वरन और रामकुमार रामनाथन टीम में सिंगल्स खिलाड़ी हैं जबकि पेस और रोहन बोपन्ना डबल्स खिलाड़ी की भूमिका निभाएंगे। बोपन्ना चोट का हवाला देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले से हट गए थे जबकि शरण उस समय अपने शादी के रिसेप्शन में व्यस्त थे। कजाखिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित इस मुकाबले में पेस और जीवन नेदुनचेझियान ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यह सिर्फ दूसरी बार होगा जब भारतीय टीम डेविस कप में क्रोएशिया का सामना करेगी। पिछली बार दोनों टीमों का सामना 1995 में दिल्ली में हुआ था जब भारतीय टीम ने 3-2 से जीत दर्ज की थी। पेस ने उस मुकाबले में सिंगल्स और महेश भूपति के साथ डबल्स में जीत दर्ज की थी। क्रोएशिया की टीम में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष-50 में शामिल दो खिलाड़ी हैं। बोर्ना कोरिक 26वें जबकि अनुभवी मारिन सिलिक 36वें पायदान पर हैं। यह देखना दिलचस्प होगा की सिलिक को भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए टीम में जगह मिलती है या नहीं। वह नवंबर 2019 में हुए फाइनल्स में नहीं खेले थे जहां टीम को स्पेन और रूस के खिलाफ ग्रुप मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पेस के रहने से टीम की उम्मीदें बढ़ेंगी।

### एनिसिमोवा ने स्वितोलिना को हराकर उलटफेर किया

**दोहा :** अमेरिका की एमांडा एनिसिमोवा ने दोहा डब्ल्यूटीए ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पांचवीं रैंकिंग की एलिना स्वितोलिना को 6-3, 6-3 से हराकर उलटफेर किया। अमेरिकी युवा खिलाड़ी ने यूक्रेन की अपनी प्रतिद्वंद्वी को एक घंटे में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्वितोलिना पिछले सत्र में विंबलडन और फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थी। कजाखिस्तान की इलेना रीबाकिना ने पहला सेट गंवाने के बाद रोमानिया की सोरेना क्रिस्टिया को 3-6, 6-3, 6-1 से हराया। क्रोएशिया की पेट्रा मार्टिक को चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्रीकोवा ने 4-6, 6-1, 6-2 से पराजित किया।

भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस। फाइल फोटो, प्रेट्र

### महिला वर्ग में किसी खिलाड़ी का दबदबा नहीं होना अच्छा : पियर्स

**नई दिल्ली :** चार बार की ग्रैंडस्लैम विजेता फ्रांस की मेरी पियर्स ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सर्किट में महिला वर्ग में किसी भी खिलाड़ी का दबदबा नहीं होना खेल के लिए अच्छा है क्योंकि अनिश्चितता से रोमांच बना रहता है।

पिछले 13 महिला ग्रैंडस्लैम सिंगल्स टूर्नामेंट में 11 अलग-अलग विजेता देखने को मिले हैं जो दर्शाता है कि पिछले तीन साल में कोई भी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर दबदबा नहीं बना पाई। फ्रेंच ओपन की जूनियर वाइल्ड कार्ड सीरीज के यहां चल रह मुकाबलों के लिए पहुंची इस ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट की ब्रांड दूत पियर्स ने कहा, 'यह अच्छा है कि किसी भी खिलाड़ी का दबदबा नहीं है। जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो किसी को नहीं पता होता कि कौन खिताब जीतेगा। युवा खिलाड़ी लगातार अच्छी प्रदर्शन कर रहीं हैं और स्तर में सुधार कर रही हैं। टेनिस बॉल, टेनिस कोर्ट, जूते, रैकेट, स्ट्रिंग सभी चीजों के लिए काफी खर्चा करना होता है। इसके अलावा कोचिंग और ट्रेनिंग पर भी काफी खर्चा होता है। जब मैं 13 साल की थी तो मुझे प्रायोजक मिल गया था जिससे 16 साल तक मुझे पैसों की तंगी नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि अगर मुझे प्रायोजक नहीं मिलता तो मेरे माता-पिता के लिए यह कितना आसान या मुश्किल होता।' उन्होंने कहा, 'भारत ने पिछले कुछ समय में कुछ अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा। भूपति के साथ मिलकर मैंने 2005 में विंबलडन का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीता। इन खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय टेनिस में भारत को पहचान दिलाई।' पियर्स रोला गैरां पर खिताब जीतने वाली मेजबान देश की आखिरी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2000 में महिला सिंगल्स और डबल्स ोनों वर्ग का खिताब जीता था। इस खिताब जीत के 20 साल पूरे होने के संदर्भ में उन्होंने कहा, '2000 मेरे लिए काफी विशेष वर्ष रहा। उस साल मेरा सपना साकार हुआ। मेरे लिए पहले दौर का मुकाबला काफी महत्वपूर्ण था। उसे खेलने के बाद मैंने सोचा कि इस बार इस टूर्नामेंट को मैं अपना बना सकती हूं। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई लेकिन मैच दर मैच मेरे खेल में निखार आता गया और मैं चैंपियन बनीं।' रिकॉर्ड 24वें सिंगल्स ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने की कोशिशों में जुटी अमेरिकी की अनुभवी सेरेना विलियम्स की पियर्स ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'सेरेना ने अब तक जो हासिल किया है वह काबिले तारीफ है। उसने महिला टेनिस में लंबे समय तक दबदबा बनाया। मां बनने के बाद उसने जिस तरह वापसी की वह उसके आत्मविश्वास और क्षमता को दिखाता है। उम्मीद करती हूं कि वह रिकॉर्ड खिताब जीतने में सफल रहेगी क्योंकि यही उसकी प्रेरणा है।'

### रणजी सेमीफाइनल और फाइनल में होगा डीआरएस का उपयोग

**राजकोट, प्रेट्र :** सौराष्ट्र और गुजरात के बीच रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच के दौरान पहली बार देश की शीर्ष घरेलू प्रतियोगिता में निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) का उपयोग किया जाएगा। टीमों को प्रत्येक पारी में चार रेफरल दिए जाएंगे लेकिन टेक्नोलॉजी में हॉकआई और अल्ट्रा ऐज शामिल नहीं होंगे जो कि अंतरराष्ट्रीय मैचों में उपयोग होने वाले डीआरएस के प्रमुख अंग हैं।

सौराष्ट्र क्रिकेट संघ की ओर से कहा गया कि रणजी ट्रॉफी में पहली बार अंपायर निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) को लागू किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2019-20 के सेमीफाइनल और फाइनल मैचों में डीआरएस प्रणाली अपनाई जाएगी। पिछले सप्ताह बीसीसीआइ के क्रिकेट महाप्रबंधक सबा करीम ने कहा था कि रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट से नहीं बल्कि सेमीफाइनल के लिए डीआरएस के सीमित उपयोग की योजना हमेशा से थी। डीआरएस का फैसला पिछले सत्र में कई नॉकआउट मुकाबलों में गलत फैसलों की वजह से लिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जयदेव शाह ने इस फैसले का स्वागत किया है। डीआरएस लागू होने के बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में अंपायरों से गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी।

## एक पैर में जूता पहन जय भगवान का अभ्यास

**पवन शर्मा, करनाल**

▶ यह भारतीय मुक्केबाज अब 900 खिलाड़ियों को दे रहा है ट्रेनिंग

ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता मुक्केबाज जयभगवान ने अपने करियर के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ओलंपिक में खेलने का सपना सच कर दिखाया। जयभगवान ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में बताया कि मैं महज 22 रुपये का जूता खरीदकर टूटी साइकिल से स्टेडियम जाता था।

सस्ते जूते चंद रोज भी नहीं चल पाते थे तो एक पैर में ही जूता पहनकर अभ्यास करता। कभी खाने के लिए सोचता तो कभी आगे की पढ़ाई के बारे में। फिर एक दिन राज्य खेलों में अच्छे प्रदर्शन पर 3100 रुपये का पुरस्कार मिला तो नई राह दिखाई दी। बस, फिर आगे बढ़ता गया और ओलंपिक खेलने का सपना सच कर दिखाया। अब युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए पूरे हरियाणा में पांच जगह अकादमी चला रहा हूं। यहां लड़कियों को निशुल्क प्रशिक्षण देता हूं और चाहता हूं कि ओलंपिक में ये खिलाड़ी भारत के लिए पदकों का अंबार लगा दें। जयभगवान ने बताया कि बचपन से उन्हें इस खेल से गहरा लगाव था। फिल्मों में अभिनेता धर्मेंद्र को देखकर मेरा मुक्केबाजी के प्रति लगाव हो गया। पिता राजपाल सिंह पीडब्ल्यूडी में थे और अभाव भरे जीवन में भी आगे बढ़ने का हौसला देते रहे। इससे कभी नकारात्मकता नहीं आई।

हिसार में जिस छोटे से घर में जयभगवान रहते थे, उसी के पड़ोस में मुक्केबाज सूबे सिंह बेनीवाल का घर था। उन्हें रोज अभ्यास करते देख जयभगवान ने भी प्रशिक्षण शुरू कर दिया। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जयभगवान ने 2012 लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया। हालांकि ओलंपिक पदक का उनका सपना अधूरा ही रह गया। जयभगवान मानते हैं कि भारतीय मुक्केबाज हर मोर्चे पर खूब दमखम रखते हैं लेकिन चोट और रोगों के उपचार में उन्हें अभी भी समस्याओं से जूझना पड़ता है।

करनाल : ओलंपियन एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता मुक्केबाज जय भगवान। जागरण

## ओलंपिक मशाल के लिए ग्रीस का प्लान-बी

**कोरोना का डर**

**एथेंस, एएफपी :** कोरोना वायरस का खतरा अब 2020 टोक्यो ओलंपिक आयोजन पर भी पड़ सकता है। ग्रीस ओलंपिक समिति ने सोमवार को कहा कि अगर उनके देश में कोरोना वायरस का खतरा नजर आता है तो वह ओलंपिक मशाल प्रज्ज्वलित करने के कार्यक्रम पर प्लान-बी पर भी सरकार से बात कर रही है।

टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए मशाल जलाने की तारीख 12 मार्च है और इसी दिन ओलंपिया में मशाल प्रज्ज्वलित की जाएगी। इसके बाद टॉर्च को ग्रीस की धरती पर घुमाया जाएगा। इसके बाद 19 मार्च को इसे एथेंस के पेनाथेनिक स्टेडियम में जापानी आयोजकों को थमाया जाएगा।

### कोरोना के डर से टेबल टेनिस चैंपियनशिप स्थगित

**सियोल :** टेबल टेनिस विश्व टीम चैंपियनशिप कोरोना वायरस मामलों के कारण स्थगित कर दी गई। यह चैंपियनशिप अगले महीने दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में आयोजित की जानी थी। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने कहा कि 22 से 29 मार्च को होने वाली यह प्रतियोगिता अब 21 से 28 जून के बीच हो सकती है। दक्षिण कोरिया की के-लीग फुटबॉल भी स्थगित कर दी गई। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हैंडबॉल ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं क्योंकि कोरिया में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या बढ़कर 893 पर पहुंच गई है।

### भारतीय मुक्केबाज इटली में प्रशिक्षण जारी रखेंगे

**नई दिल्ली :** टोक्यो ओलंपिक 2020 के क्वालीफायर टूर्नामेंट की तैयारी के सिलसिले में इटली में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय मुक्केबाजों को कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समय से पहले घर वापस आने का विकल्प दिया गया था, लेकिन टीम ने वहां रुके रहने का फैसला किया। भारतीय खिलाड़ी असिसी स्थित प्रशिक्षण शिविर में अभ्यास कर रहे है जो इटली में इस जानलेवा बीमारी के केंद्र से काफी दूर है। भारतीय टीम में 13 मुक्केबाज और इतने ही सहयोगी सदस्य हैं। इटली में कोरोना वायरस का प्रकोप में है।

### मैचों में नहीं होंगे दर्शक

**रोम :** कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इटली की सीरी-ए और यूरोपा लीग के आगामी मैच बंद स्टेडियमों में खेले जाएंगे और इनमें कोई दर्शक मौजूद नहीं होगा। इटली के खेल मंत्री विनसेंजो स्पैडाफोरा ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कहा, 'खेल जगत की मांग और यह जानते हुए कि उत्तरी इटली के छह क्षेत्रों में जनता के लिए खेल आयोजनों पर प्रतिबंध जारी है इसलिए हमने बंद दरवाजों के अंदर मैचों का आयोजन करने पर सहमति जताई है।' इंटर मिलान ने भी घोषणा की कि लुडोगोरेट्स के खिलाफ होने वाले यूरोपा लीग के उसके मैच के दौरान कोई भी दर्शक स्टेडियम में मौजूद नहीं रहेगा।



## प्राची संग परिणय सूत्र में बंधे नड्डा के पुत्र गिरीश

**जेएनएन, बिलासपुर**

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बड़े बेटे गिरीश नड्डा मंगलवार देर रात राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले कारोबारी अजय ज्याणी की पुत्री प्राची के साथ परिणय सूत्र में बंध गए।

इससे पहले गिरीश की बरात राजस्थान के पुष्कर से मंगलवार शाम पास ही स्थित गुलाब बाग पैलेस धूम-धड़ाके के साथ पहुंची। बरात हाथी, घोड़े व ऊंटों पर सवार होकर निकली। गिरीश हाथी पर सवार थे। गुलाब बाग पैलेस में मध्यरात्रि विवाह की रस्में पूरी की गईं। इससे पहले, दो दिन तक हल्दी समेत शादी की रस्में और परंपराएं निभाई गईं। नड्डा और उनकी पत्नी मल्लिका के अलावा देशभर से आए परिवारिक मित्रों ने हिमाचली रीति-रिवाज के तहत गिरीश की सेहराबंदी की। ननिहाल वालों ने भी पूरी रस्में निभाईं।

शादी समारोह में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पत्नी डॉ. साधना ठाकुर पहले ही दिन से कार्यक्रम में योगदान दे रही हैं। भाजपा के हिमाचल प्रदेश के पूर्व महामंत्री महेंद्र पांडेय, संदीपनी भारद्वाज व अन्य नेता भी समारोह में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी भी अजमेर पहुंचे। देर रात प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेताओं ने भी शादी समारोह में शिरकत की।

**बिलासपुर में वधु प्रवेश 28 को :** पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बुधवार को विवाह की रस्में पुष्कर में पूरी होने के बाद वर-वधु के साथ जेपी नड्डा और परिवार के लोग हिमाचल में बिलासपुर जिले के विजयपुर स्थित पैतृक आवास में लौट आएंगे। यहां 28 फरवरी को सुबह वधू प्रवेश का कार्यक्रम रखा है। वहीं, 29 फरवरी को भी एक आयोजन विजयपुर में ही किया जाएगा। उस दिन पूरे देश से मेहमानों को भोजन पर बुलाया गया है। वहीं, बिलासपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने जेपी नड्डा के 28 फरवरी के विजयपुर में आगमन को देख सुरक्षा प्रबंध पुख्ता किए हैं। इलाके में यातायात प्रबंधन सुचारू बनाने के लिए पुलिस जुटी हुई है। इसके लिए पुलिस अधिकारी भी लगातार विजयपुर के दौरे कर रहे हैं।

राजस्थान के पुष्कर में मंगलवार को अपने बड़े बेटे गिरीश नड्डा के विवाह समारोह के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (बाएं)। जागरण

### सीएस प्रोफेशनल में मुंबई की श्रुति और इंदौर के हर्षित टॉपर

**जागरण संवाददाता, कानपुर :** भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की दिसंबर 2019 में हुई सीएस की मुख्य परीक्षाओं सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिए गए। प्रोफेशनल में मुंबई की श्रुति ने न्यू सिलेबस और इंदौर के हर्षित जैन ने ओल्ड सिलेबस पाठ्यक्रम में टॉप किया है।

घोषित परिणाम के अनुसार, प्रोफेशनल की परीक्षा पास करके कंपनी सचिव बनने वालों में न्यू सिलेबस में मुंबई की श्रुति कल्पेश शाह प्रथम, गाजियाबाद की उर्वशी गुप्ता द्वितीय, मुंबई की मैत्री योगेश मेघानी तीसरे स्थान पर रहीं। पुराने सिलेबस में इंदौर के हर्षित जैन प्रथम, मुंबई के सुशील प्रताप कुमावत दूसरे व मुंबई के ही अब्दुल कादिर खोजेम तीसरे स्थान पर रहे। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के न्यू सिलेबस में पुणे की कल्याणी अश्विन प्रथम, मुंबई के अमनदीप सिंह दूसरे और भीलवाड़ा के पुलक बंसल तीसरे स्थान पर रहे। ओल्ड सिलेबस में चेन्नई की प्रिया जी पहले, मुंबई के जोश रंजन दूसरे स्थान पर रहे।

## गुजरात के खंभात में पुरानी रंजिश को लेकर हिंसा व आगजनी

**राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद**

**चिंताजनक**

▶ बंद के दौरान दो केबिन और मोटरसाइकिलों में आग लगाई

▶ पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया

नमस्ते ट्रंप के एक दिन पहले रविवार को आणंद जिले के खंभात में पुरानी रंजिश को लेकर असामाजिक तत्वों ने खंभात के कुछ इलाकों में हिंसा व आगजनी की। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की। डीजीपी ने घटना की रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार सुबह से ही इलाके के अधिकांश स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे। सड़क किनारे दो केबिन और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई। घटना के बाद पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में ले लिया।

अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के एक दिन पहले ही पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में टकराव हो गया था। बाद में एक गुट ने खंभात के हिंदू बहुल इलाकों में आकर हिंसा व आगजनी की जिसमें एक की मौत हो गई तथा 13 घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने घरों में घुसकर महिलाओं और पुरुषों से मारपीट तथा लूटपाट की। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बरात का वीडियो बनाने की बात को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया था। बाद में वे गुट बनाकर आए और लोगों के साथ पिटाई शुरू कर दी। इस हमले में दर्जनों घर व दर्जनों वाहन जला दिए गए।

घटना के विरोध में मंगलवार को कई हिंदू संगठनों ने खंभात बंद का आहवान किया है। पुलिस ने हालात पर नियंत्रण के लिए इलाके में गश्त शुरू की है। इस दौरान पुलिस जब अकबरपुर इलाके में गश्त करने पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने घटना की रिपोर्ट मांगी, साथ ही लापरवाही के मामले में पुलिस अधीक्षक व उपाधीक्षक का तबादला कर दिया है। डीजीपी ने यहां तीन पुलिस उपाधीक्षक व सात पुलिस निरीक्षक तथा एसआरपी की तीन व आरएएफ की दो कंपनियां तैनात की हैं।

विजय रूपाणी। फाइल

प्रदेश में ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पुलिस और गृह मंत्रालय इसको लेकर सख्त कदम उठाएंगे। डीजीपी मौके पर पहुंचे हैं, घटना की जांच की जा रही है।
**विजय रूपाणी, सीएम गुजरात सरकार**

## दलित को कंधे पर बैठा मंदिर में ले गए पुजारी

तेलंगाना के खम्मम में सामाजिक समरसता की एक मिसाल देखने को मिली। दलित समुदाय से आने वाले रवि को कंधे पर उठाकर भद्राचलम नरसिंह स्वामी मंदिर के पुजारी कृष्ण चैतन्य यहां के ऐतिहासिक श्री लक्ष्मी रंगनाथ स्वामी मंदिर के भीतर ले गए। यह मंदिर संरक्षण आंदोलन के दौरान हुआ। इसका आयोजन सामाजिक समरसता वेदिका, नरसिंह वाहिनी जैसे सामाजिक संगठनों ने किया था। एएनआइ

## बिना तलाक दिए पति या पत्नी का लिव इन रिलेशन में रहना अवैध : हाई कोर्ट

**जागरण संवाददाता, प्रयागराज**

**अहम फैसला**

▶ तीन बच्चों की मां को सुरक्षा व संरक्षण देने से हाई कोर्ट का इन्कार

बिना तलाक दिए पति या पत्नी के लिव इन रिलेशन में रहने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया है। कोर्ट ने अहम फैसले में लिव इन रिलेशन में रह रही तीन बच्चों की मां को सुरक्षा व संरक्षण देने से भी इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना तलाक दिए अलग होकर लिव इन रिलेशन में रहने वालों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति भारती सप्रू व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने यह आदेश अखिलेश व जितेंद्र की याचिका पर दिया है। याची महिला अखिलेश की शादी रामपुर के धूलिका धरमपुर के जगतपाल के साथ हुई थी। दंपती के तीन बच्चे हैं। पति के शराब पीकर मारपीट करने और कमाकर लाने को कहने से आजिज आकर अखिलेश मुरादाबाद के शादीशुदा जितेंद्र के साथ रहने लगी। अखिलेश ने कोर्ट को बताया कि वह जितेंद्र के साथ लिव इन रिलेशन में है, उसे धमकाया जा रहा है। जितेंद्र ने कोर्ट को बताया कि उसकी मर्जी के खिलाफ परिवार वालों ने उसकी शादी की है। वह याची के साथ रह रहा है। कोर्ट ने कहा कि बिना तलाक दिए पति या पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहना अवैध है। ऐसे मामले में कोर्ट संरक्षण नहीं दे सकती है।

**हाई कोर्ट ने 2016 में भी दिया था आदेश :** इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में आदेश दिया था कि शादीशुदा महिला गैर पुरुष के साथ लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकती। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। मीरजापुर की महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने यह आदेश दिया था। याची की शादी 30 मई 2016 को हुई थी। उसका कहना था कि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, जबकि वह पांच साल से अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। दोनों पति-पत्नी की तरह रहते हैं लेकिन, परिवार वाले परेशान कर रहे हैं। उनको ऐसा करने से रोका जाए। कोर्ट का कहना था कि पति-पत्नी को ही सह संबंध बनाने की कानूनन मान्यता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में फैसला दे चुका है कि अविवाहित या तलाकशुदा स्त्री-पुरुष ही रिलेशनशिप में रह सकते हैं।




### मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में आसमान आंशिक बादल छाये रहेंगे। इन राज्यों के एक-दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा व बर्फबारी के आसार हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा। छिटपुट बादलों के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा।

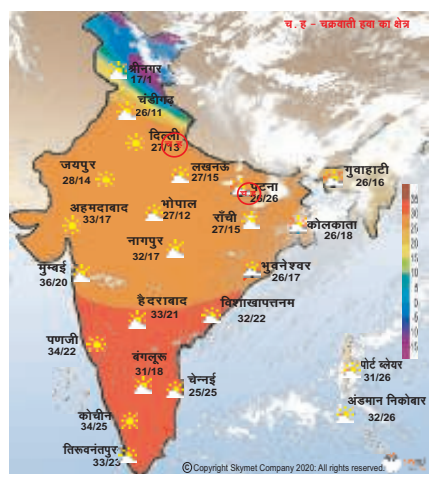

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

| शहर | | शहर | |
|---|---|---|---|
| मुम्बई | 35/21/सा | अहमदाबाद | 33/14/आंबा |
| कोलकाता | 27/17/आंबा | बड़ौदा | 34/15/सा |
| चेन्नई | 33/23/आंबा | नागपुर | 33/16/सा |
| हैदराबाद | 33/20/आंबा | इन्दौर | 29/13/आंबा |
| बंगलूरू | 32/19/आंबा | राँची | 28/16/आंबा |
| त्रिवेन्द्रम | 33/24/आंबा | पटना | 27/27/आंबा |
| गुवाहाटी | 30/18/आंबा | जमशेदपुर | 29/17/आंबा |
| गंगटोक | 15/08/सा | पुणे | 34/19/आंबा |

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 26 फरवरी 2020
# आजकल
16
www.jagran.com

## हवाई ऑब्जेक्ट को पकड़ने की तकनीक (रडार) सामने आई

1935 में आज ही रॉबर्ट वाट्सन वॉट ने रेडियो प्रणाली के जरिए एयरक्राफ्ट के डिटेक्शन और लोकेशन जानने का आसान तरीका दुनिया के सामने रखा था। इस तकनीक को आगे चलकर रडार के नाम से जाना जाने लगा और अब इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है।

## कलर्ड मोशन पिक्चर बनाने का तरीका सामने रखा गया

1909 में आज ही पहली बार लंदन में लोगों के सामने 21 शॉर्ट फिल्मों के एक प्रोग्राम के जरिए 1906 में ईजाद इस तकनीक के बारे में बताया गया था। इस तकनीक को किनमाकलर कहा जाता था। इसमें काले और सफेद के अलावा लाल और हरे रंग का प्रयोग होता था।

## मसाला फिल्मों के माहिर थे मनमोहन देसाई

हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा को नई दिशा देने वाले निर्माता-निर्देशक मनमोहन देसाई का जन्म 1936 में आज ही गुजरात में हुआ था। पर्दे पर सपनों की दुनिया बुनने वाले मनमोहन देसाई की फिल्मों से दो भाइयों या परिवार के अन्य सदस्यों के बिछुड़ने और आखिरकार उनके नाटकीय ढंग से मिलने का फॉर्मूला खूब चर्चित हुआ। उनकी पहली बनाई फिल्म छलिया थी। पिछली सदी के आठवें और नवें दशक की शुरुआत में अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथोनी, कुली, मर्द, सुहाग जैसी कई हिट फिल्में बनाई। 1 मार्च, 1994 को उनका देहांत हो गया।

## इधर-उधर की

### बच्ची से हार गया कोरोना

**वुहान, एजेंसी :** अगर जीने की इच्छा हो तो जिंदगी मिल ही जाती है। यह कहावत तो सुनी ही होगी, आज आपको ऐसा ही एक किस्सा बताते हैं। कोरोना वायरस से तो दुनिया हलकान है, बड़े से बड़े डॉक्टर परेशान हैं। ऐसे में एक नवजात ने महज 17 दिनों के भीतर कोरोना को हरा दिया। वुआन के बाल अस्पताल में ऐसी ही एक बच्ची को तब लाया गया जब उसे श्वास और हृदय संबंधी बीमारी परेशान कर रही थी। डॉक्टरों ने लक्षण देखकर उसका दवाओं के बिना इलाज करने की ठानी और जब 17 दिनों बाद टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट निगेटिव आई। डॉक्टरों ने बताया, उसे श्वास रोग की कोई बड़ी समस्या, कफ या बुखार नहीं था इसीलिए बिना दवा के इलाज संभव हो सका। बता दें कि वैश्विक महामारी के रूप ले चुका कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में ही सबसे पहले प्रकाश में आया था। इसके चलते चीन में अब तक 26 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और यहां लगभग 80 हजार लोग इससे संक्रमित हैं।

# मंगल ग्रह पर भी आते रहते हैं भूकंप

**खोज** ▶ नासा के लैंडर ने लगाया पता, आने वाले भूकंपों की तीव्रता होती है कम

### नवंबर 2018 में लाल ग्रह पर भेजा गया था 'इनसाइट'

**वाशिंगटन, आइएएनएस:** मंगल ग्रह पर भी अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता बहुत कम होती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोबोटिक लैंडर 'इनसाइट' की जांच में लाल ग्रह पर 450 से अधिक भूकंपीय संकेतों का पता चला है। बता दें कि मंगल ग्रह की सतह के निचले हिस्से का गहराई से अध्ययन करने के उद्देश्य से 'इनसाइट' को नवंबर 2018 में लाल ग्रह पर भेजा गया था।

'इनसाइट' के प्रमुख खोजकर्ता ब्रूस बैनर्ड्ट ने कहा कि सबसे बड़े भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर चार थी। यह तीव्रता ग्रह के निचले हिस्से तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 'नेचर जियोसाइंस एंड नेचर कम्युनिकेशन' में प्रकाशित इस शोध में कहा गया है कि मंगल ग्रह पर ना केवल भूकंप आते हैं बल्कि धूलभरी आंधी और अजीब तरह के चुंबकीय कंपन भी होते रहते हैं। खोज के दौरान भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोमीटर, हवा के दबाव को मापने के लिए सेंसर के साथ ही ग्रह के तापमान को जानने के लिए ऊष्मा के प्रवाह का प्रयोग किया गया था। बता दें कि भूकंपीय तरंगें उन सभी चीजों से प्रभावित होती हैं, जिनसे वे गुजरती हैं। माना जा रहा है कि इस नई खोज से वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। नासा ने कहा कि इस नई खोज से यह समझने में मदद मिलेगी कि पृथ्वी सहित सभी चट्टानी ग्रह सबसे पहले कैसे बने? बता दें कि 2019 अंत तक इनसाइट मंगल ग्रह पर एक दिन में दो भूकंपीय संकेत भेज रहा था। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी भी उम्मीद है कि उन्हें बड़े भूकंप के संकेत मिल सकते हैं। खास बात यह है कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्र जरूर हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि मंगल ग्रह पर भेजे गए अब तक के मिशनों के मुकाबले 'इनसाइड' लाल ग्रह में हवा की गति और दवाब को लगातार मापने में सक्षम है।

नासा द्वारा जारी की गई इस तस्वीर में इनसाइट लैंडर के गुंबद से सिस्मोमीटर को ढका गया है। एपी

**अक्टूबर 2018 में पहली बार दर्ज किया गया था मार्सक्वेक :** अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मई 2018 में मंगल ग्रह पर सीस्मिक गतिविधियों के अध्ययन के लिए 'इनसाइट' को भेजा था। मंगल ग्रह पर उतरने के पांच महीने बाद पहली बार इस लैंडर ने इसकी सतह पर भूकंप के संकेत दिए थे। नासा की कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) के वैज्ञानिकों ने इस कंपन की गतिविधि को रिकॉर्ड किया था। उन्होंने इसे 'मार्सक्वेक' नाम दिया था। मंगल ग्रह पर भूकंप आने की खबर यह भी बताती है कि भविष्य में यदि मनुष्य लाल ग्रह पर जाकर बस जाए तो वहां भी उसका प्राकृतिक आपदाओं से पीछा नहीं छूटने वाला है। हालांकि वह दौर आने में अभी काफी समय है।

### तेजी से गर्म और ठंडा हो सकता है लाल ग्रह

'इनसाइट' लैंडर ने मंगल ग्रह के मौसम के पैटर्न के बारे में कई बातें बताई हैं। प्रकाशित शोध में कहा गया है कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में तापमान में उतार-चढ़ाव का तेज अनुभव होता है। अमेरिका स्थित कार्नेल यूनिवर्सिटी के डॉन बैनफील्ड ने कहा, मंगल ग्रह का वायुमंडल इतना पतला है कि यह पृथ्वी के मुकाबले तेजी से गर्म और ठंडा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि लैंडिंग के लगभग एक महीने बाद इनसाइट को एक बड़े धूल के तूफान का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि पृथ्वी और चंद्रमा की तरह ही लाल ग्रह का वातावरण बदलता रहता है।

# जबलपुर में छह साल से पिंजरे में बंद मादा तोते ने दिए तीन अंडे

मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक पिंजरे में छह साल से बंद मादा तोते ने तीन अंडे दिए हैं। नई दुनिया

**देवशंकर अवस्थी, जबलपुर**

मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिछले छह साल से पिंजरे में बंद एक मादा तोते ने तीन अंडे दिए हैं। करन प्रजाति की मादा तोते के अंडे देने से लोग अचरज में हैं। हालांकि, वन्य जीव विशेषज्ञ का कहना है कि यह कोई अजूबा नहीं है, ऐसा हजारों में एक मामला सामने आता है।

जबलपुर के ब्राह्मण मोहल्ला पुरवा निवासी सतीश तिवारी उस समय आश्चर्य में पड़ गए जब उनके घर के पिंजरे में छह साल से बंद तोते (एलेक्जेंड्री पैराकीट) ने एक के बाद एक तीन अंडे दिए। पहला अंडा 30 जनवरी को, जबकि दो अंडे दो दिन पहले दिए। पहले अंडे को तोते ने फोड़ दिया, जबकि दो अंडे सुरक्षित हैं।

**स्वाभाविक प्रक्रिया : विशेषज्ञ:** वन्य जीव विशेषज्ञ का मानना है कि मादा पक्षियों का अंडे देना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसा कि पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों में होता है। वे बिना निषेचन के अंडे देती हैं, लेकिन उन अंडों से बच्चे पैदा नहीं होते। बच्चे देने के लिए पक्षियों में निषेचन प्रक्रिया जरूरी है। उन्होंने बताया कि मादा तोते ने जो अंडे दिए, वह भी ठीक ऐसा ही मामला है। भले ही मादा तोता इतने वर्षों से पिंजरे में है, लेकिन उसमें ऐसे लक्षण स्वाभाविक रूप से बने। उसके अंडों से भी बच्चे तैयार नहीं होंगे।

**स्पेक्ट्रम**

हजारों पक्षियों में किसी एक के साथ ऐसा होता है। मादा का काम ही अंडे देना है, इसके लिए निषेचन प्रक्रिया से गुजरना जरूरी नहीं है।

**डॉ. एबी श्रीवास्तव, वन्य जीव विशेषज्ञ, जबलपुर, मप्र।**

# मानसिक रूप से परेशान रहती हैं कम उम्र की माताएं

- कनाडा की एमसी मास्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा
- कहा- अन्य के मुकाबले कम उम्र की महिलाएं चार गुना ज्यादा रहती हैं परेशान

यह अध्ययन एडोलेसंट हेल्थ नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

**टोरंटो, आइएएनएस :** एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि तीन में से दो माताओं को एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या हमेशा घेरे रहती है। विज्ञान पत्रिका एडोलेसंट हेल्थ नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि अन्य के मुकाबले किशोरावस्था में ही मां बनने वाले महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां सबसे ज्यादा झेलती हैं। लगभग 40 फीसद माताओं को डिप्रेशन (अवसाद), चिंता और हाइपरएक्टिविटी (अतिसक्रियता) जैसा कोई एक मानसिक विकार जरूर होता है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि ये विकार 21 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के मुकाबले कम उम्र की महिलाओं को चार गुना ज्यादा होते हैं। कनाडा की एमसी मास्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रेयान वान लिशआउट ने कहा, 'अब हम समझते हैं कि माताएं केवल प्रसव के बाद अवसाद जैसी समस्याओं से जूझती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता।' उन्होंने कहा कि इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग बेहतर स्क्रीनिंग प्रक्रिया विकसित करने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर चरणबद्ध तरीके से इलाज के लिए भी किया जा सकता है।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने वर्ष 2012 से 2015 के बीच 450 ऐसी माताओं के स्वास्थ की निगरानी की जो अपनी पहली डिलीवरी के समय 21 साल की थी और इससे प्राप्त डाटा की तुलना उन्होंने ऐसी महिलाओं से की जो 20 साल से पहले मां बन चुकी थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि शायद विश्व में यह पहला अध्ययन होगा जिसमें प्रसव के बाद महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच की गई है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक वान लिशाउट ने कहा, 'इस तरह के शोध के लिए 'नैदानिक साक्षात्कार' सबसे अच्छा मानक है। हमें खुशी है कि सैकड़ों माताओं से बात करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया गया है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि इस अध्ययन के लिए 2014 की ओंटेरियो चाइल्ड हेल्थ स्टडी से 15 से 17 साल की महिलाओं के मानसिक विकारों की तुलना में उनकी ऐसी हमउम्र माताओं से की गई थी जिनके बच्चे नहीं थे। अध्ययन में कहा गया है कि युवा माताओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना और उनका उपचार करना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका स्वास्थ्य उनके बच्चों को भी प्रभावित करता है। कई बार यह समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि बच्चों को आजीवन इसका नुकसान झेलना पड़ता है।

## तनाव होने पर मिलता है भावनात्मक सहारा

**न्यूयॉर्क, आइएएनएस :** यह तो सभी जानते हैं कि ज्यादा तनाव हमारे शरीर के लिए बेहद घातक सिद्ध हो सकता है। अब एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि दुष्प्रभावों के अलावा तनाव होने के कई सामाजिक फायदे भी मिल सकते हैं। स्ट्रेस एंड एएमपी हेल्थ नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग ज्यादा तनाव से ग्रसित रहते हैं उन्हें अन्य लोगों के मुकाबले अधिक भावनात्मक सहारा मिलता है और दिन-ब-दिन यह सपोर्ट बढ़ता चला जाता है।

अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता डेविड अलमेडा ने कहा, ' हमारा निष्कर्ष बताता है कि तनाव के चलते दिन खराब होने का यह मतलब कतई नहीं है कि हमारा पूरा दिन ही खराब रहेगा। अगर तनाव वास्तव में हमें अन्य लोगों के साथ जोड़ सकता है, तो यह बेहद महत्वपूर्ण है।'

## विकासक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गट बैक्टीरिया

**वाशिंगटन, प्रेट्र :** हमारी आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया मनुष्यों के विकास में पुराने अनुमानों के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इन सूक्ष्मजीवों की खुद को परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेने की कला प्राचीन मनुष्यों को नए भौगोलिक क्षेत्रों में जीवत रहने में मदद करती होगी।

फ्रंटियर्स इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन नाम के जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मनुष्यों, वानरों के गट बैक्टीरिया यानी आंतों के माइक्रोबायोम का विश्लेषण किया। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रॉब डून के मुताबिक, मनुष्य के गट बैक्टीरिया जल्दी से नई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं, इसीलिए मनुष्य नई भौगोलिक परिस्थितियों में खुद को ढाल लेता है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि गट बैक्टीरिया मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## फोटो न्यूज

### कॉर्निवाल में जलवायु परिवर्तन रोकने का संदेश

ब्राजील के रियो डि जेनेरियो में चल रहे कॉर्निवाल की दूसरी रात यूनिडॉस तिजुका सांबा स्कूल के सदस्यों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। इस बार कॉर्निवाल की थीम वैश्विक जलवायु परिवर्तन है। इसके जरिए धरती के बढ़ते तापमान के खतरों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। तस्वीर में आर्कटिक की पिघलती बर्फ और उस पर संकट में फंसे ध्रुवीय भालू को दिखाया गया है। एएफपी

## शोध अनुसंधान

### हृदय रोग का पता लगाने में रक्त जांच मददगार

शोधकर्ताओं का कहना है कि सामान्य रक्त जांच से हृदय रोग के खतरे की पहचान करने मदद मिल सकती है। इससे समय रहते इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी पत्रिका में छपे अध्ययन के अनुसार, रक्त में उच्च स्तर पर एमिलॉइड बीटा का पाया जाना हृदय रोग का संकेत हो सकता है। एमिलॉइड बीटा का संबंध भूलने की बीमारी अल्जाइमर से भी होता है। अब यह पाया गया है कि धमनियों के मोटा होने, हार्ट फेल होने और हृदय रोग में इसकी भूमिका हो सकती है। उन्होंने यह निष्कर्ष 6,600 से ज्यादा रोगियों के रक्त नमूनों के विश्लेषण के आधार पर निकाला है। ब्रिटेन की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि इस शोध से एक ऐसी आसान रक्त जांच के विकास की राह खुल सकती है, जिसके इस्तेमाल से हृदय रोग से ज्यादा खतरे वाले लोगों की पहचान की जा सकती है। -आइएएनएस

### हाई बीपी से जुड़े खास गट बैक्टीरिया की पहचान

एक भारतवंशी समेत शोधकर्ताओं के दल ने हाई ब्लड प्रेशर (बीपी) से जुड़े एक खास गट (आंत) बैक्टीरिया की पहचान की है। इस बैक्टीरिया से पल्मोनेरी आर्टिरीअल हाइपरटेंशन (पीएएच) के खतरे का अनुमान लगाया जा सकता है। इस बीमारी में फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियां संकरी हो जाती हैं। नतीजन सांस में तकलीफ और सीने में दबाव जैसे लक्षण सामने आते हैं। हाइपरटेंशन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, हर व्यक्ति की आंत में कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये पाचन में मदद करते हैं। शोधकर्ताओं ने एक ऐसे खास बैक्टीरिया की पहचान की है, जिसकी मौजूदगी से पीएएच का 83 फीसद तक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के भारतीय मूल के शोधकर्ता मोहन रायजादा ने कहा, 'हमने पहली बार यह साबित किया है कि आंत में खास बैक्टीरिया की मौजूदगी से पीएएच का पता लगाया जा सकता है।' -आइएएनएस

## स्क्रीन शॉट

# सौरव गांगुली की कहानी को पर्दे पर लाएंगे करण जौहर?

महेंद्र सिंह धौनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक बन चुकी हैं। तापसी पन्नू पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज की बायोपिक 'शाबाश मिट्ठू' की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म '83' में रणवीर सिंह कपिल देव बने हैं। 'जर्सी' में भी शाहिद कपूर क्रिकेटर की भूमिका में होंगे। अब पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और वर्तमान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की बायोपिक की चर्चा हो रही है। खबर है कि करण जौहर सौरव गांगुली की बायोपिक बना सकते हैं, जिसके लिए करण और सौरभ मुलाकात कर चुके हैं। सौरव ने एक साक्षात्कार में अपनी बायोपिक में रितिक रोशन द्वारा अपना किरदार निभाए जाने की इच्छा जताई थी। हालांकि इस बायोपिक की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले एकता कपूर भी सौरव गांगुली की बायोपिक बनाना चाहती थीं। एक इंटरव्यू के दौरान सौरव ने बताया था कि इस मामले में एकता से बात नहीं बनी और फिल्म बनना रद्द हो गया था। इस साल '83', 'रश्मि रॉकेट', 'मैदान', 'सायना', और 'जर्सी' जैसी फिल्में रिलीज होंगी, जो खेल की पृष्ठभूमि पर होंगी।

# इरफान को गुरु दक्षिणा देंगे पंकज त्रिपाठी

पंकज त्रिपाठी ने अभिनेता इरफान को हमेशा अपना गुरु माना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इरफान पंकज के सीनियर थे। यह पहली बार होगा, जब पंकज अपने गुरु के साथ स्क्रीन साझा करेंगे। फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' में पंकज कैमियो कर रहे हैं। इस कैमियो को करने का कारण पंकज ने इरफान को बताया। पकंज का कहना है कि इरफान उनके गुरु रहे हैं और वह हमेशा से ही इरफान के साथ एक ही फ्रेम में नजर आना चाहते थे। पंकज के मुताबिक, उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वह इरफान को देखकर सीखा है। ऐसे में उन्होंने फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' में जो छोटा-सा रोल किया है, वह इरफान के लिए उनकी गुरु दक्षिणा होगी। पंकज हमेशा से ही इरफान की परफॉर्मेंस से प्रेरित रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी 'हासिल', 'मकबूल', 'पान सिंह तोमर' जैसी फिल्मों का उन पर काफी प्रभाव पड़ा है। पंकज कहते हैं कि भारतीय सिनेमा में इरफान का योगदान सराहनीय है। शायद ही कोई कलाकार हो, जो उनकी तरह न बनना चाहता हो। होमी अदजानिया निर्देशित फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' 13 मार्च को रिलीज होगी।

# काजोल के साथ अजय ने ली कैमरे के पीछे वाली सेल्फी

सोमवार को अजय देवगन और काजोल की शादी की 21वीं सालगिरह थी। दोनों के रिश्ते में अब भी पहले-सी मिठास बनी हुई है। मंगलवार की सुबह काजोल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह सीढ़ियों पर बैठी मुस्कुरा रही हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने जो लिखा, उससे लगता है कि वह चाहती थीं कि उनके पति अजय उनके साथ सेल्फी लें। आखिर अजय ने उनकी खूबसूरत तस्वीर ले ही ली। काजोल ने संवाद शैली में लिखा, 'मैं : बेबी चलो एक सेल्फी लेते हैं। पति : जाओ, वहां बैठो, मैं लेता हूं। मैं : सेल्फी मतलब दोनों साथ रहते हैं, और उनमें से कोई एक तस्वीर खींचता है। उनका जवाब है यह तस्वीर।' अजय ने भी यह तस्वीर साझा कर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, 'यह मेरे तरीके की सेल्फी है, जिसमें मैं कैमरे के पीछे रहता हूं।' बता दें कि अजय देवगन और काजोल की शादी 24 फरवरी 1999 में हुई थी।

# मॉम का मतलब होता है 'मास्टर ऑफ मल्टीटास्किंग' : करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर वेब सीरीज 'मेंटलहुड' से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर रही हैं। करिश्मा काफी लंबे समय बाद अभिनय में वापसी कर रही हैं। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'डेंजरस इश्क' के बाद वह अभिनय से दूर थीं। सोमवार को मुंबई में 'मेंटलहुड' वेबसीरीज का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जहां करिश्मा कपूर, संजय सूरी, श्रुति सेठ और तिलोत्तमा शोम जैसे सितारों के साथ शो की निर्माता एकता कपूर भी मौजूद थीं। इस वेब सीरीज में मां बनने के बाद एक औरत की जिंदगी में होने वाले परिवर्तनों को दिखाया जाएगा। इस मौके पर मां का मतलब समझाते हुए करिश्मा ने कहा कि वह खुद दो बच्चों की मां हैं और उनके अनुसार, मां का मतलब 'मॉम' यानी मास्टर ऑफ मल्टीटास्किंग होता है। उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद हम अपनी जिंदगी में प्राथमिकताओं को समझते हैं और जीवन के अन्य पहलुओं के बीच संतुलन बनाना सीखते हैं। इस मौके पर करिश्मा ने एकता के साथ बिताई हुई बचपन की कुछ यादें भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में उनके पिता रणधीर कपूर और एकता के पिता जितेंद्र कुछ अन्य एक्टरों के साथ जम्मू-कश्मीर घूमने जाया करते थे। उनके साथ वे दोनों भी जाया करती थीं। करिश्मा के मुताबिक, सब लोग जिस जगह ठहरते थे, वहां पर कई फव्वारे होते थे। जिसमें एक फव्वारे के पास जितेंद्र जी बैठते थे, दूसरे के पास रणधीर कपूर। जब सब लोग रात खाना खाने जाते, तो एकता वहां पर सबके सामने जितेंद्र के गानों पर डांस किया करती थीं।

# सख्त डाइट से राणा दग्गुबाती ने घटाया तीस किलो से ज्यादा वजन

फिल्मों के किरदारों के मुताबिक कलाकारों को अपने लुक में बदलाव करने पड़ते हैं। राणा दग्गुबाती ने भी अपनी आगामी फिल्म 'हाथी मेरे साथी' में अपने लुक के लिए काफी मेहनत की है। फिल्म में राणा जंगल में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपना जीवन ही जंगल में बिता देता है। किरदार को वास्तविक बनाने के लिए उन्होंने अपने खानपान में कई बदलाव किए। सख्त डाइट करके उन्होंने 30 किलो से ज्यादा वजन कम किया। पूरी फिल्म में वह लंबी दाढ़ी और ग्रे रंग के बालों में दिखेंगे। फिल्म में उनके कंधे झुके हुए भी होंगे। शारीरिक बदलाव को लेकर राणा ने बताया कि फिल्म के निर्देशक प्रभु सर चाहते थे कि सब कुछ वास्तविक हो। मेरे लिए वजन कम करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हमेशा से ही मेरी शारीरिक बनावट भारी-भरकम रही है। फिल्म के किरदार के लिए दुबला दिखना जरूरी था, जिसकी लिए शारीरिक ट्रेनिंग लेनी पड़ी। फिल्म में पुलकित सम्राट, श्रिया पिलगांवकर भी नजर आएंगे।

## मानुषी ने बनाया अपने किरदार का स्केच

मिस वर्ल्ड रह चुकीं मानुषी छिल्लर अपनी पहली फिल्म 'पृथ्वीराज' की शूटिंग में व्यस्त हैं। यशराज फिल्म्स की इस बड़े बजट की फिल्म में लीड रोल अक्षय कुमार निभा रहे हैं, जबकि मानुषी उनकी पत्नी रानी संयोगिता के किरदार में दिखेंगी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने किरदार का एक स्केच बनाकर शेयर किया है, जिसमें उनके लुक की झलक देखी जा सकती है। अपनी इस रचनात्मकता पर वह कहती हैं, 'मैं कुछ समय से स्केच बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूं और अब मौका मिलते ही मैं अपनी इस कला को और निखारूंगी। मैं सेट पर एक छोटा ब्लैकबोर्ड और चॉक साथ ले जाती हूं और ब्रेक के दौरान स्केच बनाती हूं। जब निर्देशक मुझसे पहली बार मिले थे, तब उन्होंने कहा था, तुम राजकुमारी संयोगिता हो, तुम्हे शेरनी की तरह दहाड़ना चाहिए। मुझे उनकी यह बात याद रही और मैंने सेट पर उनकी सोच को मूर्त रूप देने की कोशिश की। उनके इस बात में राजकुमारी संयोगिता की हिम्मत झलकती है और इससे मुझे स्क्रीन पर किरदार को निभाने में मदद मिली।' बता दें कि 'पृथ्वीराज' इस साल दिवाली पर रिलीज होगी।